

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 जुलाई, 1998

खण्ड-2, अंक-6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 28 जुलाई, 1998

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45(1) के अधीन मेज सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(6)17
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)28

ध्यानाकर्षण प्रस्तावो इत्यादि की सूचनाएं	(6)36
वाक आउट	(6)47
वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानो तथा विनियोजनाओ से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(6)47
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(8)50
बैठक का समय बढ़ाना	(6)77
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)77
बैठक का समय बढ़ाना	(6)89
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)90
बैठक का समय बढ़ाना	(6)97
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)97

बैठक का समय बढ़ाना	(6)113
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)113
बैठक का समय बढ़ाना	(6)116
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)116
बैठक का समय बढ़ाना	(6)125
वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(6)125
बिल्लज	
(i) हरियाणा सहकारी सोसायटी (सं तोधन) विधेयक, 1998	(6)134
(ii) पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा सं तोधन) विधेयक, 1998	(6)136

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 28 जुलाई, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Seepage in Loharu Canal

***757. Sh. Satpal Sangwan:** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the several thousand acreage of land of Achina, Rawaldhi, Loharwala, Khatiwas, Dhikra, Charkhi, Khera, Bura, Biri, Barsana, Manakwas and Ghasola etc. villages has become uncultivable due to the seepage in Loharu Canal; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to make the aforesaid land cultivable?

सिंचाई मंत्री (श्री हर्ष कुमार):

(क) जी हां, श्रीमान् जी।

(ख) लोहारु नहर मे रिसाव को कम करने के लिए क्षति ग्रस्त लाइनिंग का काम किया गया। 6500 फुट लाइनिंग रुपये 6 लाख की लागत से पहले ही मरम्मत की जा चुकी है। धन की उपलब्धता पर बाकी बचे कार्य को फेजो मे दो साल के अन्दर अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा। इसके अलावा लोहारु नहर के साथ "सीपेज ड्रेन" का निर्माण प्रस्तावित है, ताकि साथ लगते खेतों में रिसाव के पानी का प्रवे । पर नियंत्रण किया जा सके।

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, इस पर मेन्टेनेंस का जो काम हुआ है यह बहुत अच्छा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह का मेन्टेनेंस का जो काम अभी बकाया पडा है वह भी कराया जाये क्योंकि इससे पहले इस नहर की आज तक कभी भी मेन्टेनेंस वगैरा नहीं की गई थी और उसमें बडे बडे होल थे इसलिए अब मेरी यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से कम्पलीट कराया जाये।

श्री हर्ष कुमार: स्पीकर साहब, ठीक है, हम इस काम को और जल्दी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जब वर्ष 1995 मे बाढ आई थी तो उस वक्त उससे दादरी, कलानौर, जीन्द मिसाथल के एरियाज मे काफी हालत खराब हुई थी। वहां पर 10-10 फुट पानी खडा रहा जिस वजह से आज वह जमीन काबिल का त नहीं रही। सीपेज की वजह से यह सब हुआ है। जुई कैनाल के साथ

लगते एरिया में यह सीपेज की समस्या अधिक बढ़ी है। वर्ष 1995-96 में उस वक्त की सरकार ने मैनुअल लेबर से काम करवाने की बजाये मॉर्निंग से करवाया था जिससे वहां सीपेज ज्यादा हो रहा है। क्या अब आप उस काम को दुबारा ठीक ढंग से कराएंगे ताकि सीपेज को रोका जा सके?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि हमने सफाई का काम शुरू कर किया हुआ है। मेन्टीनेंस का काम चल रहा है। सतपाल सांगवान उस वक्त मेरे साथ थे जब हमने इनके एरियाज का निरीक्षण किया था। जिस ढंग से अब काम हो रहा है उसकी काफी अच्छी प्रोग्रेस है। जहां-जहां पर काम हो रहा है उसकी डिटेल्स मैं आपको भिजवा दूंगा। आप भी इस काम को देख लेना और मैं भी स्वयं जाकर देख लूंगा।

Evening College

***671. Sh. Ram Pal Majra:** Will the Minister for Education be pleased to state whether the Evening College of Maharashi Dayanand University, Rohtak has been closed. if so, the reasons thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्गव): जी हां। महर्षि दयानन्द वि विद्यालय सांध्यकालीन महाविद्यालय, वि विद्यालय का एक अनुरक्षित महाविद्यालय था। वि विद्यालय ने यह निरीक्षण करने हेतु कि क्या सांध्यकालीन महाविद्यालय को चालू रखना आर्थिक तथा भौतिक दृष्टिकोण से उचित है, वि शेषज्ञ तथा

अनुभवी शिक्षको/अधिकारियो की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने एक चेतनात्मक सन्तुति की कि इतने बड़े खर्च से सांध्यकालीन महाविद्यालय को चालू रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसे तुरन्त प्रभाव से बन्द किये जाने से कोई अहित नहीं होगा। वि. वि. विद्यालय के प्राधिकारियो ने तदानुसार निर्णय लिया।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या इस सांध्यकालीन महाविद्यालय में निरंतर 3 वर्षों से शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या घट रही थी या बढ़ रही थी? इस प्रकार के और भी बहुत से कालेज हैं जहां पर बच्चों की संख्या कम है लेकिन वहां पर अभी यह सुविधा उपलब्ध है। फिर इस महाविद्यालय को ही बन्द क्यों किया गया?

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय में दिन में पढने वाले बच्चों की जो संख्या रही है उसकी 5 प्रतिशत से अधिक संख्या सांध्यकालीन कक्षाओं में बच्चों की नहीं रही। दिन में जो लोग मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इसे चलाया गया था। यह सुविधा कई और जगहों पर भी है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सांध्यकालीन एल0 एल0 बी0 व दूसरे कोर्सिज की कक्षाएं लगती हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से आई0 ए0 एस0 और बाकी दूसरे लोग उसमें एल0 एल0 बी0 करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यह महा विद्यालय रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस में भी प्रारंभ किया गया था परंतु इस

महाविद्यालय में नौकरी पेशे वालों की संख्या 5% से अधिक नहीं थी दूसरे प्रोफेसर लोग ज्यादा थे। अध्यक्ष महोदय, श्री माजरा जी ने कहा कि कई जगहों पर इस महाविद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या से कम के भी और महाविद्यालय है। उनकी यह बात बिल्कुल सही है, जैसे दुवलधन में है, नगीना में है। अध्यक्ष महोदय, नगीना महाविद्यालय में तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि प्राध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या से बढ़ जाती है। मेवात का इलाका है, मोरनी का इलाका है इन इलाकों में भी ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें छात्रों की संख्या यूनिवर्सिटी के कैम्पस में चलने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से कम है फिर भी हम उनको चला रहे हैं। इन सब के हम जन हित के लिए चला रहे हैं। परंतु अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी के कैम्पस में ऐसी कोई आवृत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह कदम एकदम नहीं उठाया गया बल्कि वहाँ के छात्रों की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से जब इस बारे में बात आई उसके बाद ही इस मामले को यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक उपसमिति बनाई। उस उपसमिति ने इन सारी बातों का निरीक्षण किया, जांच की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यहाँ पर इतने बड़े खर्च से सांध्यकालीन महाविद्यालय चलाने की बजाय इसका समायोजन कैम्पस में जो बड़े कॉलेज हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत है, छात्र संख्या के हिसाब से अध्यापकों के हिसाब से उनमें कर दिया जाए। इसलिए सर, बाद में यह निर्णय लिया गया।

श्री बलवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने जवाब में एक बात कही है कि दुवलधन और नगीना में सांध्यकालीन महाविद्यालय उन इलाको के पिछडेपन को देखते हुए चला रखे है, क्या रोहतक युनिवर्सिटी कैम्पस के सांध्यकालीन महाविद्यालय मे गांव के छात्र पढने के लिए नही आते? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोहतक यूनिवर्सिटी कैम्पस के सांध्यकालीन महाविद्यालय में 5% लोग ही ऐसे पढने आते थे जो नौकरी-पे गा वाले थे। मैं नहीं माना कि वहां पर नौकरी पे गाे वाले सिर्फ 5% लोग ही पढने आते है, मेरे हिसाब से ज्यादा आते है। फिर इस महाविद्यालय को क्यों बंद किया जा रहा है इस बात पर मंत्री महोदय क्या कुछ रो गानी डालेंगे?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बलवंत सिंह मायना जी ने गांव के छात्रो के बारे मे जो बात कही है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जहां तक उन छात्रो के पढने का सवाल है वे छात्र रात मे पढने के लिए नही आते, वे दिन में ही आते है। अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय मे ऐसे छात्रो की संख्या ज्यादा थी जो कई वर्षो से फेल हो रहे थे या किसी और कारण से महाविद्यालय मे रहता चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है तब से हम इस युनिवर्सिटी के वातावरण को पढाई योग्य और अनु गासित बनाने के लिए लगातार कोर्ि गा कर रहे है। अकेले एक संस्थान में 20-22 हजार छात्रो की संख्या है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस युनिवर्सिटी

में कोई कालेज बंद नहीं किया बल्कि जो सांध्यकालीन महाविद्यालय था उसका समायोजन दिन में चलने वाले बड़े संस्थान में कर दिया।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने प्रश्न के लिखित जवाब में और बाद में जो सप्लीमेंटरी की गई है उसके जवाब में अलग अलग बात कही है। मैं आपके द्वारा इनको यह कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आदि जनता से जुड़े हुए विभाग हैं। अध्यक्ष महोदय, जो इवनिंग क्लासिज़ बंद की गई है वह इस इलाके के लोगों के साथ द्वेष की भावना के कारण बंद की गई है। श्री राम बिलास भार्मा जी बहुत योग्य मंत्री हैं इसलिए उनसे मेरी पुरजोर गुजारिश है कि वे इस पर फिर से गौर करें। उसमें 5% या 10% बच्चों की बात नहीं है बल्कि यह मामला हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए इस बारे में क्या वे दोबारा विचार करेंगे? इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल महिलाओं की शिक्षा के बारे में है। यहां पर महिलाओं की चर्चा हो रही है। अग्रसेन कालेज झज्जर के अंदर साईंस की क्लासिज़ चल रही थी वह भी बंद कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर देहात की 100% बच्चियां पढ़ने के लिए देहात से आती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे देहात की बच्चियों को साईंस के सब्जेक्ट से अलग रखने की

कुचेष्टा नहीं कर रहे हैं? इस बारे में शिक्षा मंत्री महोदय थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री धीरपाल सिंह जी से कहना चाहूंगा कि जो जवाब लिखित रूप में दिया गया है उसके तदानुरूप ही मैंने अपनी बात कही है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ। झज्जर का वे या कालेज इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी मैं चौधरी धीरपाल सिंह जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के कुछ नियम होते हैं उनके अनुसार यूनिवर्सिटी हर कालेज का सर्वेक्षण करती है। वे य कालेज झज्जर के बारे में लोगों की शिकायत थी कि वहां पर ट्रेड प्राध्यापक नहीं है फिर भी वहां पर विज्ञान की क्लासिज चलाई जा रही है। इस बात की जांच करने पर पाया कि वहां पर विज्ञान की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन क्लासों को बंद करने की सिफारिश की। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं अपने भाई धीरपाल सिंह जी को एडवाइस करूंगा कि वे वहां की मैनेजमेंट से मिल लें और उनसे कहें कि विज्ञान क्लासिज चलाने के लिए वहां पर योग्य प्राध्यापकों का प्रबंध करें। उनको आवासन देता हूँ कि यदि मैनेजमेंट ऐसा कर देती है तो हम वहां पर ये क्लासें शुरू करने के लिए फिर से विचार कर सकते हैं।

श्री बीजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि हमारे यहां थर्मल पावर प्लांट कालोनीज में एक दस जमा दो का स्कूल है जो कि यह सोच कर खोला गया था कि यहां के इम्पलाईज के बच्चे यहां पर पढ़ सकेंगे। लेकिन उनको वहां पर यह सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल है वह अपनी मनमर्जी करता है। (विधन) मैं चाहूंगा कि इस स्कूल की चेंकिंग की जाए। इसके साथ ही वहां पर एक हाई स्कूल भी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको दस जमा दो में अपग्रेड किया जाए ताकि इस स्कूल की मोनोपली न रहे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक डी० ए० वी० स्कूल कांट्रैक्ट बेसिज पर क्लासिज चला रहा है जिससे वहां के बिजली बोर्ड के इम्पलाईज बड़े परेशान हैं। क्या इस बारे में मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे? (विधन)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेन सवाल से इस सप्लीमेंटरी का कोई संबंध नहीं है फिर भी मैं अपने भाई बीजेन्द्र सिंह कादयान को बताना चाहूंगा कि एच० एस० ई० वी० कॉलोनी पानीपत के डी० ए० वी० स्कूल के बारे में कुछ शिकायतें मुझे भी मिली हैं और इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि युनिवर्सिटी के सांध्यकालीन कालेज के कुछेक

विधार्थी थे जो लगातार फेल होते जा रहे थे इसलिए भी इसको बंद करना पडा। यदि किसी कालेज में 5-7 विधार्थी अपना कोई स्वार्थ पूरा कर रहे है तो उनको निकालने की बजाए इन्होंने कालेज ही बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, 5-7 विधार्थियों को कॉलेज से निकालने की बजाए कॉलेज को ही बंद कर देना वहां के लोगो को परे तान करना है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि इस कालेज को बंद करने की बजाए उन्होंने भारारती तत्वो को इस कॉलेज से निकालने की कार्यवाही क्यों नही की?

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी सिरी कृष्ण हुड्डा को बताना चाहूंगा कि यह हमने नही किया है। वैसे इसको बंद करने से 40 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बचत भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला कई वर्षो से चल रहा था और डेढ साल पहले ही एग्जिक्यूटिव काउंसिल बनाई गई और उसकी एक उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लिया गया। (विघ्न)

**Construction of a Link Road from Village Kailashpur to
Sonapat City**

***635. Sh. Dev Raj Dewan:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no proper link road/passage from village Kailashpur to Sonapat City; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the aforesaid village with Sonepat Bahalgarh road or Sector-15 of Sonepat City?

Public Works Minister (Sh. Dharam Vir Yadav):

(a) Yes, Sir.

(b) There is no such proposal at present.

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के दो गांव है जिनका नाम बईयांपुर खुर्द और कैला ापुर है। वहां पर रास्ता न होने के कारण खेतों में से होकर मेन सडक पर पहुंचते हैं जिसकी वजह से वहां पर कभी कभी लडाई भी हो जाती है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन दोनों गावों का रास्ता जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। मंत्री जी यह भी बताएं कि ये रास्ते कब तक बन जाएंगे?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये गांव नान-डायेरेक्टरी में आते हैं। जिन गावों की आबादी 250 से कम हो वहां पर सडके बनाने का कोई प्रबंध नहीं है।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, बईयांपुर खुर्द गांव की 3000 की आबादी है और कैला ापुर की 400 की आबादी है। मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि वहां पर 250 की आबादी नहीं है।

मेरा इनसे अनुरोध है कि वहां पर जल्दी सडके बनवाये ताकि लोगो को राहत मिले ।

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, हम पहले लेटैस्ट पोर्जी गन की असैसमेंट करवा लेगे और उसके हिसाब से जो भी उचित कार्यवाही होगी उसको हम करेंगे ।

Construction of Small Dam on Krishnawati River

***645. Sh. Kailash Chander Sharma:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in Narnaul Constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct small bandh (Dam) on Krishnawati river at Nangal Choudhary, Maandi and Kojinda villages to solve the problem of the drinking water of the said area?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) 26 गावों में कुछ कमी है परन्तु बहुत कमी नहीं ।

(ख) 26 पानी की कमी वाले गावों में जल वितरण में बढौतरी करने का प्रस्ताव है । कृष्णवती एक बरसाती नाला है । इस पर बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री कैला । चन्द्र भार्मा: स्पीकर सर, मै नारनौल या महेन्द्रगढ के लिए पीने के पानी की समस्या के बारे में बार बार इसलिए क्वै चन कर रहा हूं क्योकि वहां पर कोई भी नहर बेस्ड स्कीम नही है । इसलिए वहां पर पीने का पानी या तो टयूबवैल से दिया जाता है या बोरिंग करके दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, नारनौल मे तो एक कैनाल बेस्ड स्कीम है ।

श्री कैला । चन्द्र भार्मा: स्पीकर सर, सिर्फ नारनौल में ही है बाकी उस पूरे इलाके में कहीं पर भी नहर बेस्ड स्कीम नही है । मंत्री जी ने अपनी रिप्लाइ में 26 गावो में पीने के पानी की कुछ कमी बतायी है । मै उनसे जानना चाहता हूं कि वे 26 गांव कौन कौन से है? क्या मंत्री जी उन गावों के नाम बताने का कश्ट करेंगे जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था बढायी जा रही है ।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, ये 26 गांव इस प्रकार है:- खतौती कलां, खतौती खुर्द, खोरमा, जख्मी, वशपरोली, नंगल कथा, जैलफ मोहम्मदपुर, डोहर कलां, डोहर खुर्द, गोठ बलवा कलां, गोद बलवा खुर्द, जादूपूर, भांकरी, मकसुसपुर, पचनोटा, मसनोटा, गोलबा, अमरपुर, जोरासी, ताजीपुर, छिलरपो, घटे 1र, रसूलपुर, थाने और लुतेफपुर ।

श्री नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोद, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है और स्वयं माना है कि नारनौल के आस पास के 26

गावों में पीने के पानी की कमी है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अटेली के आस पास के भी कुछ गांवों में ऐसी दिक्कत है। क्या मंत्री जी इन हल्को में कोई कैनल बेस्ड स्कीम या बोरिंग करके पीने के पानी की सुविधा करने जा रहे हैं और ये कितने गावों को इस योजना के अंदर ऐसी सुविधा देंगे?

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, इन 26 गावों में से 19 गावों के अंदर तीन योजनाएं बनायी जा रही हैं जिनका ऐस्टीमेट वगैरह बन चुका है। वे तीनों ही योजनाएं कैनल बेस्ड होंगी। इसके अलावा सात गावों के और ऐस्टीमैंट्स तैयार हो रहे हैं। सन् दो हजार तक हम इन सारे गावों को कवर कर लेंगे। लेकिन भार्मा जी ने जैसे कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में 93 गांव हैं और इन 93 गावों में से 65 गांव ऐसे हैं जिनमें चालीस लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा आठ गांव ऐसे हैं जहां पर तीस लीटर प्रति व्यक्ति के पानी दिया जा रहा है। इस तरह से भार्मा जी यह नहीं कह सकते कि वहां के गावों में पीने का पानी बिल्कल ही नहीं दिया जा रहा है। 20 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से कम पानी कहीं पर नहीं दिया जा रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिजली के फेल हो जाने से या दूसरी किसी दिक्कत की वजह से समस्या हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इनका कुछ एरिया पहाड़ी है हम वहां पर पहाड़ों के अंदर भी गहराई तक जाकर बोरिंग करके देखते हैं लेकिन वहां पर पानी कम ही दिखता है और कुछ समय बाद यह

कम पानी भी खत्म हो जाता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, सन् दो हजार के बाद हम सभी जगह पर पूरा पानी देंगे ।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। सर, मेरे चुनाव क्षेत्र नीलोखेड़ी में तीन गांव यानी भुकापुर, बुढेडा और मचताना ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है, क्या मंत्री जी इन गांवों को पीने का पानी मुहैया करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: आपका यह क्वैश्चन रैलेवैन्ट नहीं है, आप बैठें ।

श्री कैलाश चन्द्र भार्गव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिन गांवों में पीने के पानी की कमी बता रहे हैं, उनमें से दुचाना और डोहर कलां के बारे में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पानी बहुत नीचे है। जब वहाँ सरकारी अधिकारी बोरिंग लगाने जाते हैं तो वह केवल दो सौ फुट तक बोर करके ही अपनी मीन उखाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि वहाँ पानी नहीं है। जबकि उन्हीं गांवों में जब प्राइवेट आदमियों ने मीन से चार सौ फुट तक बोरिंग करवाया तो वहाँ पर पानी निकल जाता है। सरकार अधिकारी नीचे तक बोरिंग नहीं करते और वे पानी की गहराई को नापने में दिक्कत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गांवों में हमने बोर करके चार सौ फुट पर पानी निकाला है और अब इन

दोनो गावों को प्राईवेट पार्टीज द्वारा पीने का पानी दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो इसकी इंक्वायरी करवा सकते है। सरकारी अधिकारी दो घंटे मे ही अपनी मीन उखाड कर चले जाते है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी समस्या है।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, इन सबको चैक करवा लेंगे। बाकी राणा साहब ने जो सवाल किया था उसके बारे मे बताना चाहूंगा कि हम सारे हरियाणा में सभी गावों मे पीने का पानी दे रहे है। कभी किसी गांव में दिक्कत पड जाती है तो वह इसलिए कि या तो नहर में पानी नही होता या बिजली फेल हो जाए तो हम पीने का पानी नही दे पाते वरना तो जहां पर 100 आदमियो की बस्ती है वहां पर भी हम कोर्िंग कर रहे है कि सभी को पीने का पानी मिले।

श्री जय सिंह राणा: मैने जिन गावों के नाम बताए है उनमें आज भी पानी नही है। (इस सवाल का जवाब नही आया।)

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधू: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी राणा साहब के सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि सभी गावों में पीने का पानी दे रहे है तो मै बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के के गुमथला गढी की तीनो पंचायतो डेरा फतेहसिंह, डेरा मदनपुर मे आज भी पीने के पानी का कोई प्रबंध नही है इनके बारे में बताएं कि वहां बोर कब तक लगवा देंगे और पानी कब तक दे देंगे?

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। 26 महीने हो गए हैं इन 26 महीनों में न इन्होंने इस बारे में कोई सवाल पूछा, न लिखकर दिया और न कोई कार्यवाही की इसमें तो इनकी खुद की ही लापरवाही है। अगर इन डेरो में पानी की कमी है तो मेरे को इस बारे में लिखकर नोटिस दे, पूरा काम कर देंगे।

Samples of Insecticides

***767. Sh. Narender Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the number of samples taken by the joint Directors. Agriculture and Additional Directors, Agriculture, who have been appointed as Insecticide Inspectors during the year 1997-98 and 1998-99 i.e. upto 30th June, 1998; and

(b) number of samples taken by the Insecticide Inspectors in the presence of the Joint Directors and Additional Directors during the above said period together with the number of samples out of them which has been certified by the Joint Directors and Additional Directors?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) संयुक्त कृषि निदेशकों एवं अपर निदेशकों द्वारा स्वयं कोई नमूने नहीं लिये गये थे।

(ख) अन्य कीटना ाक निरीक्षको द्वारा भरे गये नमूनो को अपर कृशि निदे ाको/संयुक्त कृशि निदे ाको द्वारा प्रमाणीकरण करने की कोई प्रथा नहीं है ।

फिर भी अपर निदे ाको/संयुक्त कृशि निदे ाको की उपस्थिती मे कीटना ाक निरीक्षको द्वारा भरे गये नमूनो का विवरण इस प्रकार से है:-

वर्ष	भरे गए नमूनो की संख्या
1997-98	133
1998-99	137
(6 / 98 तक)	

श्री नृपेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने सवाल के भाग-3 मे कहा है However, the number of samples drawn by the insecticides inspectors in the presence of Additional Directors/Joint Directors of Agriculture are as under. उससे पहले ये कहते है there is no system of certification by Additional Directors/Joint Directors of Agriculture in respect of samples drawn by other insecticides inspectors. मै जानना चाहता हूं कि जब सैम्पल प्रैजैन्स में लिए गए तो सर्टिफिकेट ान न करने के पीछे क्या कारण है?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, प्रदे 1 के अंदर जो कीटना 1क दवाईयां है उनमे किसी प्रकार की कोई खामियां न हो, किसानो को किसी तरीके से उनसे नुकसान न हो, उसके लिए हमारे विभाग ने व्यापक तौर पर अभियान चलाया। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कई दफा फिल्ड से रिक्वायर्मेंटें आती है कि हमारे निरीक्षक प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं करते, इसलिए हम हैड आफिस से ज्वायंट डायरेक्टर और ऐडी इनल डायरेक्टर को भेजा ताकि इनकी देखरेख में सैम्पल लिये जा सके। हालांकि इनकी उपस्थिति में निरीक्षण हुआ था लेकिन उसके सर्टीफिकेट के उपर उन्होंने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए इस बारे में इस महान सदन को बताना चाहता हूं। जब हमारे सीनियर आफिसर सैम्पल की देखरेख के लिए जाते हैं और मामलो में जब फर्मों के खिलाफ कार्यवाही होती है तो यदि ज्वायंट डायरेक्टर और ऐडी इनल डायरेक्टर ने दस्तखत किए हों तो इनको अदालतों में चक्कर लगाने पडते हैं जिससे हमारे विभाग की कार्यवाही रुक जाती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इनके विभाग ने जो सैम्पल लिये थे उनमें क्या कोई कीटना 1क दवाईयां नकली पाई गई हैं और यदि पाई गई हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई केस रजिस्टर किए गए हैं? क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात है कि सरसों की फसल जो पिछली दफा हुई थी उसमें एक जैडीन

और एक मैनक्का जैल दो किस्म की दवाईयां डाली गई थी जिससे उनकी पत्तियां जल गईं?

10:00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैप्टन साहब ने नकली दवाईयो के बारे में जिक्र किया है मैं उसके बारे में इनको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों निसिंग के अंदर एक आदमी नकली दवाई बेच रहा था, उसके खिलाफ विभाग ने कार्यवाही की है। मैं हर वर्ष लिए गए सैम्पलज के बारे में इस सदन को बता देता हूं। 1996-97 में विभाग ने 1588 सैम्पलज लिए और उनका अनालेसिस करवाया तो उनमें 207 मिक्स ब्रांडिड पाये गये। इनमें से 196 के खिलाफ हमने प्रोसीक्यू इन किया। यह कार्यवाही इंसेक्टिसाईडज 1968 से 1971 के रूलज के तहत की जाती है। जो दवाईयों के सैम्पलज मिक्स ब्रांडिड पाये जाते हैं उनके खिलाफ गंभीरता से कार्यवाही की जाती है। कुछ सैम्पलज को सैन्ट्रल लैब में भेजा जाता है जहां पर उनको ठीक करार भी दे दिया जाता है। 1998-99 में अभी तक 336 सैम्पलज लिये गये हैं जिनमें से 129 का वि. अनालेसिस करवाया गया है इनमें से 18 सैम्पलज मिक्स ब्रांडिड पाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूं कि दवाईयों के बारे में हमारा विभाग पूरी तरह से सजग है। पिछले दिनों हमने पूरे विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इस बारे में निर्देश दिए हैं कि किसानों से संबंधित जितनी भी

दवाईयां या पैस्टीसाईड है उनका गंभीरता के साथ निरीक्षण करवाये ।

Outstanding Payment of Sugarcane

***631. Shri. Sampat Singh & Krishan Lal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the total quantity of sugarcane crushed by each Cooperative Sugar Mill during the year 1997-98 in the State together with the rate at which it was purchased; and

(b) whether the payment to the farmers who supplied sugarcane during the year referred to in part (a) above is outstanding against the Haryana State Cooperative Sugar Mills; if so, the mill wise details thereof?

Minister of Cooperation (Sh. Narbir Singh): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) The total quantity of sugarcane crushed by each Cooperative Sugar Mill during 1997-98 is given here as under:-

S. No	Name of Mill	Quantity of cane crushed during the season 1997-98
1	Panipat	10.26
2	Rohtak	20.42
3	Karna	28.62

4	Sonepat	18.00
5	Sahabad	41.42
6	Jind	21.51
7	Palwal	21.76
8	Meham	21.65
9	Kaithal	25.20
10	Bhuna	11.48
	Total	220.32

The rate of the cane for different varieties at which the cane was purchased by the Cooperative Sugar Mills is as under:-

Varieties	Rate as per Qtl.
COJ-64 & COH-56	Rs. 82
CO-7717, COH-99 & CO-8436	Rs. 80
Other varieties	Rs. 78

(b) The Karnal, Sonepat, Shahbad, Jind, Palwal, Meham and Kaithal Sugar Mills have made the entire payment of the amount referred to in part (a) The outstanding amount as on 13-7-98 in respect of other Mills is as follows:-

Name of Mill	Amount
Panipat	0.65
Rohtak	0.55
Bhuna	2.43
Total	3.63

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो गन्ने की बकाया राशि 3.63 लाख रुपये किसानों को देय है वह बकाया राशि उनको कब तक दे देंगे तथा उस राशि पर क्या 15 प्रतिशत ब्याज देने का भी प्रावधान है क्योंकि ऐसा हाईकोर्ट का निर्देश है?

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सदन के पटल पर रखी गई है उसमें बकाया राशि 3.63 लाख दिखाई गई है परन्तु आज तक की पोजीशन यह है कि किसानों की बकाया राशि 2.81 लाख रुपये बाकी है। सम्पत सिंह जी ने जो 15 प्रतिशत ब्याज के बारे में बात की है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे गन्ने का रेट फिक्स किया गया 45 रुपये प्रति क्विंटल और बाद में उसको बढ़ा दिया गया 48.90 पैसे प्रति क्विंटल तो इस बढ़ी हुई राशि पर तो हम ब्याज दे सकते हैं परन्तु बकाया राशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो बकाया राशि है उसकी पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दी जायेगी।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रस्ट की बात कर रहा था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन पर टैक्स लग रहा है तो सेल पर क्यों नहीं? (विधन) कोर्ट केस भी पब्लिक इंट्रस्ट में नल एंड वाएड कर दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इंट्रस्ट में तो बिल्ज वगैरह भी अमैडमेंट की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मिल घाटे में है और वे किसानों को इंट्रस्ट देने की स्थिति में नहीं है तो उन किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। चाहे वह बोनस के रूप में हो अथवा किसी और तरीके से हो, किसी न किसी तरीके से सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार तो गन्ने का रेट फिक्स करती है लेकिन जो इन्होंने ब्याज देने की बात कही है, मैं इन को बताना चाहूंगा कि ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि पानीपत भूगर मिल की तरफ किसानों की पिछले दो सीजन की कुल कितनी राशि बकाया है? दूसरा मेरा मुख्य सवाल यह था कि जब भूगर मिलो ने गन्ना लेना भुरु कर दिया था, उस समय सरकार ने गन्ने के रेटस भी फिक्स नहीं किए थे। बाद में जब रेटस फिक्स किए गए तो प्रति क्विंटल गन्ने के भाव में 18 रुपए का अंतर आया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों को जो पेमेंट की गई है क्या ये 18 रुपए भी उसमें इन्कल्यूड किए गए थे?

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पानीपत भूगर मिल में आज के दिन किसानों की कुल एक लाख रुपए का राशि बकाया है तथा किसानों को कोई भी पेमेंट कटौती कर के नहीं दी जा रही है।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं भी पानीपत भूगर मिल में गया था, वे किसानों को कटौती करके कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि पानीपत भूगर मिल में आज के दिन किसानों की एक लाख रुपये की राशि ही बकाया है जबकि रिप्लाइ में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उन के मुताबिक यह राशि 65 लाख रुपये है। कृपया मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ठीक फरमा रहे हैं कि 65 लाख रुपए की राशि दी गई है, लेकिन यह बकाया राशि तो 13-7-98 को थी। आज के दिन जो किसानों की पानीपत भूगर मिल में राशि बकाया है, वह एक लाख रुपए है।

Providing of Drainage System

***785. Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the area between Gochhi and Seria is affected by rainy water every year and farmers of the said area could not sow

their crops for the last three years; if so, the steps taken or proposed to be taken to provide proper drainage system for draining out the rainy water of the aforesaid areas?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार): जी हां, श्री मान् जी। सेरिया-गोच्छी पम्प हाउस लिंक ड्रेन योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना पर धन की उपलब्धता प भीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत: स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस काम पर कुल कितना पैसा खर्च होगा और यह स्कीम कब तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ मै यह भी जानना चाहूंगा कि डीघल और गंगटान साथ साथ लगते गांव है उन गावों में जब भी ज्यादा बरसात होती है तो बरसात का पानी खा होने की समस्या हो जाती है क्याउन गावों से बरसात का पानी निकालने के बारे में महकमे की तरफ से कोई योजना अंडर कंसीड्रेशन है?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, 1995 की बाढ मे बेरी हल्का, रोहतक का इलाका और भिवानी का इलाका काफी प्रभावित हुआ और वहां पर बाढ के कारण काफी नुकसान हुआ। उन इलाको में कही ड्रेन क्षतिग्रस्त हुई, कही माईनर क्षतिग्रस्त हुई और कही पर बाढ का पानी खडा हो गया जिसके कारण उन इलाको में काफी नुकसान हुआ। इस कारण जहां तक मै समझा हूं वह यह है कि हमारी सरकार से पहले की जो सरकारें रही, भायद

वे किसानों के प्रति उदासीन रही। जितना भी बिगडा हुआ स्ट्रेक्चर था, चाहे वह ड्रेन का था चाहे वह नहरों का था चाहे कहीं पर सीपेज ठीक न की गई हो या चाहे कहीं पर बाढ का पानी खडा होने की समस्या हो, उसके बारे में पहले की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने पिछले दो साल के दौरान उन कामों को प्राथमिकता दी। माननीय सदस्य ने इस योजनापर कुल कितना खर्च करने के प्रावधान के बारे में पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस योजना पर 21.15 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है और 17-4-98 को बाढ नियंत्रण बोर्ड ने इस योजना को स्वीकृत करवाया जा चुका है। हम इस योजना के लिए जो कोर्षा कर रहे हैं उससे हमें उम्मीद है कि यह योजना 3-6-99 तक पूरी हो जाएगी।

डा० बीरेन्द्र पाल अहलावत: स्पीकर साहब, डीघल और गंगटान गावों में बरसात का पानी खडा होने की बहुत भारी समस्या है उस पानी को निकालने के बारे में क्या इनके महकमे के पास कोई योजना अंडर कंसीड्रेशन है?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में भी हम सर्वे करवा रहे हैं। जब उसकी अलाइमेंट निश्चित हो जाएगी तो इस योजना को भी पूरा करवाने की कोर्षा करेंगे।

श्री सिर्री कृष्ण हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, रीठाल और मुंढाल माइनर सरकार ने पिछले साल बनाई उस पर 50 लाख

रुपए खर्च किए गए है लेकिन उस माइनर से रीठाल गांव का पानी निकलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस माइनर को बनाने पर जिन अधिकारियों की वजह से नाजायज पैसा लगाया गया है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, उस माना के बारे में एक कमैटी इंक्वायरी कर रही है और उस कमैटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो कार्यवाही की जाएगी उसकी रिपोर्ट और कमैटी की रिपोर्ट माननीय सदस्य हुडडा साहब को भिजवा दी जाएगी।

श्री बलवंत सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य डा० बीरेन्द्र पाल जी ने मेन सवाल मे पूछा है कि पिछले तीन साल से गोच्छी और सेरिया गावो के क्षेत्र के किसान अपनी फसलो की बुवाई नहीं कर सके है। मैं आपके माध्यम से इस बारे में यह जानना चाहता हूं कि जिन दोनो गावो के किसान पिछले तीन साल से फसलो की बुवाई नहीं कर सके क्या सरकार उन किसानो को मुआवजा देगी? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सेरिया गोच्छी पम्प हाउस लिंक ड्रेन योजना को कौन सी ड्रेन के साथ जोडा जाएगा?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस ड्रेन के पम्प हाउस का पानी झज्जर सब ब्रांच मे डाला जाएगा।

डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें राठाल, कबूलपूर और जुलाना भी शामिल है या नहीं। (गोर एवं विघ्न)

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह सवाल पूछने की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब सवाल पूछने का समय आता है तो ये सवाल भी ठीक तरह से नहीं पूछे जाते। डा० वीरेन्द्र पाल जी ने पूछा था कि क्या यह तथ्य है कि गोच्छी तथा सेरिया के बीच का एरिया प्रत्येक वर्ष बरसाती पानी से प्रभावित होता है तथा गत तीन वर्षों से उक्त क्षेत्र के किसान अपनी फसलों की बुवाई नहीं कर सके। यदि हा, तो पूर्वोक्त क्षेत्र से बरसाती पानी के निकासी के लिए उचित निकासी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए क्या पग उठाये गए या उठाए जाने प्रस्तावित है। मैं बताना चाहूंगा कि इनका सवाल भी सही नहीं था क्योंकि जिसका ये जिक्र कर रहे थे वह माईनर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये सवाल गलत पूछते हैं लेकिन फिर भी हम मेहनत करके सही जवाब देते हैं।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो सवाल पूछा था वह सही था। इस तरह से कई सवाल थे। हो सकता है कि मेरी गलती से या आफिस की गलती से ऐसा हो गया हो। लेकिन मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि यह 20730 आर० डी.० है और इस्माइला डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर है यह जुलाना गांव की जमीन में है और यह नाला दिवाना गांव

की आबपा गी करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यह किसी कि गलती से ऐसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप बताएं कि जिस गांव मे पिछले तीन चार साल से सिंचाई के लिए एक बून्द पानी न जाये तो उस गांव की क्या हालत होगी? यह आप भी समझ सकते है। मेरा सवाल यह है कि वर्ष 1995-96 की बाढ मे जो 20730 आर0 डी0 नाला डैमेज हो गया था, वह कब तक बना देंगे?

श्री हर्ष कुमार: मैंने पहले भी बताया था कि वर्ष 1995-96 मे जो सरकार थी, उसमे इरीगे टन की तरफ सही ध्यान नही दिया। उस सरकार की उदासीनता की वजह से ही हमारी नहरें, नाले, ड्रेने आदि खराब हुए पडे है। अब हमें इन सारे कामो को पूरा करने के लिए धन की कमी आ रही है। हम धीरे धीरे इनको पूरा कर रहे है और उम्मीद है कि दो साल के अंदर अंदर हरियाणा की पूरी टेलो पर पानी पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो माइनर है, नाले है या डिस्ट्रीब्यूटरी है उन सब की भी गाद निकालने का काम करके उनकी सफाई आदि कर देंगे। इन दो सालो मे ही जिस नाले का डा0 बीरेन्द्र पाल जी जिक कर रहे है, वह भी इनमें भामिल है।

Treasury Office, Jind

***718. Shri Ram Phal Kundu:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that the treasury office and its lock room, Jind are functioning in

separate buildings; if so, the time by which the said office is likely to be shifted in one building?

वित्त मंत्री (श्री चरणदास): यह ठीक है कि खजाना कार्यालय व इसका सुदृढ कक्ष तथा सिंगल लॉक इस समय अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। जब लघु सचिवालय के नये खण्ड का निर्माण होगा तो खजाना कार्यालय का अमला तथा सुदृढ कक्ष एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जायेंगे।

श्री रामफल कुण्डु: अध्यक्ष महोदय, जींद के अंदर ट्रेजरी आफिस कही है और डबल लॉक रुम कही है। जब पब्लिक अपने काम के लिए जाती है तो उस वक्त कंसर्ड आफिसर कभी ट्रेजरी आफिस में बैठता है, कभी डबल लॉक रुम में बैठता है, जिसके कारण वह पब्लिक को नहीं मिल पाता। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों आफिसरज को एक जगह पर कब तक लायेंगे? वहां पर मिनी सचिवालय पहले से ही जींद में बना हुआ है।

श्री चरण दास: अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही जींद के अंदर ट्रेजरी आफिस और डबल लॉक रुम को एक जगह पर लाने का काम करवा देंगे। इस काम के लिए 1546200 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

श्री राम फल कुण्डु: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह काम कब तक कर दिया जायेगा?

श्री चरण दास: अध्यक्ष महोदय, यह कम बहुत जल्दी कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो डेट रामफल जी दे देंगे, उस डेट तक काम कर दिया जायेगा।

Distributary from Pal Minor

***703. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to off-take a distributary Canal from Pal Minor to village Sohati in District Sonapat; and

(b) if so, the time by which the construction work of the aforesaid distributary is likely to be started/completed?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) इस उद्दे य के लिए धन की उपलब्धता के प चात कार्य भुरु किया जाएगा।

श्री नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पाई माईनर से गांव सोहटी तक राजवाह निकालने के लिए धन कब तक उपलब्ध होगा और इस पर कब तक काम भुरु होगा और क्या खर्चा आएगा?

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, सोहटी माना आर० डी० ० से 135500 तक पाई राजवाह आर० डी० 53170 से निकाला

जाना है, सरकार ने 30-1-96 को इसके लिए 4.5 लाख रुपये की प्रासन्निक स्वीकृति प्रदान कर दी है। अध्यक्ष महोदय, नई सोहटी माइनर की लम्बाई 4 कि० मी० है और इसका भीर्श डिस्चार्ज 5.45 क्यूसिक है, इसके लिए कोई जमीन अधिग्रहण नहीं की गई है, इसके लिए जमीन लाभान्वित लोगो द्वारा मुफ्त प्रदान की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस राजवाह से सोनीपत जिले के गांव गोपालपुर, बरोना, सोहटी और पहलादपुर आदि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, इससे इन गावो को करीब 100 एकड जमीन सिंचित होगी और वहां के लोगो को लाभ पहुंचेगा, परंतु धन के अभाव के कारण यह योजना अभी तक भुरु नहीं की जा सकी है। अध्यक्ष महोदय, अब इस राजवाह के लिए संशोधित परियोजना अनुमान 18.66 लाख रुपए का बनाया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना को भुरु करने के लिए धन आर० डी० आई० एफ०-3 के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता अप्रैल, 1997 से मार्च, 1999 तक उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, नई सोहटी का निर्माण कार्य अनुमानित स्वीकृति मिलने के बाद भुरु कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अब क्वै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर

Physical Education

***746. Shri Jai Singh Rana:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the classes from which sanctioned posts of Physical Education has been introduced in schools in the State;

(b) the total number of sanctioned posts of Physical Education Teachers in the State together with the number of posts lying vacant amongst them at present; and

(c) the total number of schools in which Physical Education Teachers have not yet been posted in spite of having the subject of Physical Education therein?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा):

(क) भारीरिक् शिक्षा विशय हरियाणा राज्य के विद्यालयो में श्रेणी नौवी से भुरु किया गया है ।

(ख) भारीरिक् मास्टर (डी० पी० ई०) तथा भारीरिक् टीचर (पी० टी० आई०) के स्वीकृत पदो की संख्या क्रम 1: 628 और 2658 हैं इन पदो मे से 324 पद भारीरिक् मास्टर (डी० पी० ई०) और 215 पद भारीरिक् टीचर (पी० टी० आई०) के वर्तमान समय में खाली पडे है ।

(ग) उन विद्यालयो की संख्या जिनमें भारीरिक् शिक्षा विशय के रुप में है परन्तु भारीरिक् मास्टर (डी० पी० ई०) व भारीरिक् टीचर (पी० टी० आई०) नियुक्त नहीं है उनकी संख्या 228 है ।

Rural College of Education, Kaithal

***665. Shri Ram Pal Majra:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Rural College of Education, Kaithal has been closed; if so, the reasons thereof; and

(b) whether Government intends to re-open the said College?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा):

(क) कुरुक्षेत्र विविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा रुरल शिक्षण महाविद्यालय, कैथल को भौक्षणिक सत्र 1990-91 से असम्बन्ध (डिसएफीलिएट) कर दिया गया था।

(ख) इस महाविद्यालय को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

Setting up of 220 K.V. Sub-Station at Sonapat

***620. Shri Dev Raj Dewan:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal consideration of the Government to set up 220 K.V. Sub-Station at Sonapat; if so, the time by which it is likely to start functioning?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): हां श्रीमान् जी, इस उपकेन्द्र को दिनांक 31-3-1999 तक चालू करने की योजना है।

Construction of Roads by H.S.A.M.B

***647. Sh. Kailash Chander Sharma:** Will the Minister of State for Horticulture & Marketing be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Amarpur t Ramgarh (Rajasthan Border) and from Nayan to Baba Bhaiya up to Ashram. District Mahindergarh?

बागवानी तथा विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक): वर्तमान में, इन सडको का निर्माण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Retirement Age

***742. Sh. Mani Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to raise the retirement age limit of the State Government employees?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। हरियाणा सरकार द्वारा इस विषय में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Power Projects

***632. Sh. Sampat Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The total number of Power Projects (Hydro & Thermal) are in the State at present together with the date on which these projects were commissioned;

(b) the generating capacity of each of the project as referred to in part a) above;

(c) the total MW quantity of electricity being generated in the State at present together with per unit generating cost of electricity;

(d) whether electricity is being purchased by HSEB from any other sources; if so, the names thereof and the per unit rate at which it is being purchased; and

(e) the per unit rate being charged for supplying of electricity to Domestic, Agricultural, Commercial and Industrial Sector, separately?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): श्रीमान् जी, एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) तथा (ख) राज्य में वर्तमान बिजली परियोजनाओं एवं उनकी चालू होने की तिथियों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम	क्षमता	चालू होने की तिथि

			यूनिट-1	यूनिट-2
1 पि चमी यमुना नहर जलीय विद्युत				
	बिजली घर ए	2x8 मैगावाट	29-5-86	13-6-86
	बिजली घर बी	2x8 मैगावाट	15-5-87	1-6-87
	बिजली घर सी	2x8 मैगावाट	27-3-89	18-4-89
कुल 48 मैगावाट				
2 थर्मल पावर स्टे 1न, फरीदाबाद				
	यूनिट-1 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	60 55 मैगावाट	22-11-74	
	यूनिट-2 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	60 55 मैगावाट	6-3-76	

	यूनिट-3 मैगावाट अब क्षमता कम कर दिया गया है	60 55 मैगावाट	1-4-81	
	कुल 165 मैगावाट			
3 थर्मल पावर स्टे 1न, पानीपत				
	यूनिट-1	110 मैगावाट	1-11-79	
	यूनिट-2	110 मैगावाट	27-3-80	
	यूनिट-3	110 मैगावाट	1-11-85	
	यूनिट-4	110 मैगावाट	11-1-87	
	यूनिट-5	210 मैगावाट	28-3-89	
	कुल	650 मैगावाट		

	कुल योग	863 मैगावाट		
--	---------	----------------	--	--

(ग) राज्य में वर्तमान समय में कुल उत्पादित बिजली तथा इन परियोजनाओं पर पैसों में प्रति युनिट चालू औसतन बिजली उत्पादन लागत निम्न प्रकार है:-

क्र० स०	नाम	प्रतिदिन औसत बिजली उत्पादन / यूनिट लाखों में	प्रति युनिट बिजली दर / पैसों में
1	पिचमी यमुना नहर जलीय परियोजना	8.10	77
2	फरीदाबाद थर्मल परियोजना	20.22	204
3	पानीपत थर्मल परियोजना	90.95	185

(घ) बोर्ड विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं से निम्नलिखित विवरण के अनुसार बिजली कय करता है:-

क्र० स०	परियोजना	पावर प्लांट का नाम	दर पैसों में प्रति यूनिट

1	राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम	सिंगरौली / यू० पी०	80
		रिहंद सुपर थर्मल केन्द्र / यू० पी०	163
		अटा गैस पर आधारित विद्युत परियोजना / राजस्थान	114
		औरिया गैस पर आधारित परियोजना / यू० पी० दादरी	114
		गैस / यू० पी०	
		दादरी थर्मल / यू० पी० उंचाहार / यू० पी०	124 193
		157	
2	राष्ट्रीय जलीय बिजली विद्युत निगम	सलाल जलीय परियोजना	55
		जम्मू-क मीर / उरी / जम्मू-क मीर	220
		बैरासूल जलीय परियोजना / एच० पी०	37
		टनकपुर जलीय परियोजना / यू० पी०	138

Malenka Minor

***695. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state the date on which the

construction work of the Malenka Minor was started together with the time by which the work of the said minor is likely to be completed?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार): कालेनका माना का कार्य दिसम्बर 1979 के दौरान आरम्भ किया गया था तथा बूर्जी नं०-42000 तक का कार्य 4/1987 तक पूरा हो चुका था। आर्थिक तंगी व मुकदमेबाजी के कारण 10/1996 तक कार्य निलम्बित रहा। बूर्जी नं०-82620 तक मिट्टी का भोश कार्य तथा 7 पुलो के निर्माण का कार्य अप्रैल 1997 के अन्त तक पूरा हो चुका था। भोश कार्य धन की उपलब्धता होने पर पूरा कर लिया जाएगा।

Construction of a Rivuet

***786. Dr. Virender Pal Ahawat:** Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that a Rivulet in village Baghpur, district Jhajjar at Moga No. 78957 alongwith left side of J.S.B Canal and parallel to drain No. 8 at time of its desilting; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct another Rivulet parallel to the said drain?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) इ मोगे को ड्रेन नं०-८ की बाहरी सीमा के किनारे से बदल कर पुनः निर्माण किया गया है।

Recruitment of Police Constables

***788. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for Home be pleased to state whether any recruitment in Police Department has been made during the period from 1st April, 1996 to date; if so, the category-wise names and addresses of the persons so recruited?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): 1-4-1996 से आज तक कोई भर्ती नहीं हुई सिवाय 69 सिपाही अनुग्रह पूर्वक नीति के अन्तर्गत तथा 12 सिपाही न्यायालय के आदे ानुसार भर्ती किये गये। अनुग्रह पूर्वक नीति के अन्तर्गत भर्ती किये गये 69 सिपाहियों व न्यायालय के आदे ानुसार 12 सिपाहियों का विवरण सदन के पटल पर रख रखा है।

दिनांक 1-4-1996 से अब तक अनुग्रहपूर्वक अनुदान नीति के अन्तर्गत भर्ती किये गये 69 उम्मीदवारों की सूची

क्र० स०	उम्मीदवार का नाम व पिता का नाम	वर्ग	यूनिट	पता
1	वीर सिंह पुत्र स्व० फतेह सिंह	सामान्य	सोनीपत	गांव गढी खेवा, जिला पानीपत।

2	गीता देवी पुत्री स्व० श्री रणबीर सिंह	सामान्य	सोनीपत	गांव नारनौंद, जिला हिसार
3	प्रमिला देवी पुत्री स्व० श्री धर्मबीर	सामान्य	सोनीपत	गांव मकरौली कलां, जिला रोहतक ।
4	बीरमति पत्नी स्व० श्री सतपाल	सामान्य	सोनीपत	गांव काकरोई, जिला सोनीपत ।
5	चान्दकौर पत्नी स्व० श्री कृष्ण चन्द	सामान्य	पानीपत	गांव खानपुर कलां, जिला सोनीपत ।
6	निर्मला देवी पत्नी स्व० श्री विनोद कुमार	सामान्य	पानीपत	गांव मुंडलाना, जिला सोनीपत ।
7	गायत्री देवी पत्नी स्व० श्री विनोद कुमार	सामान्य	पानीपत	गांव बढाना, जिला सोनीपत ।

8	सन्तोश कुमारी पत्नी स्व० श्री धर्म सिंह	सामान्य	पानीपत	गांव मल्लाह माजरा, जिला सोनीपत
9	नवीन कुमार पुत्र स्व० श्री राम कुमार	सामान्य	पानीपत	म० नं० 194-आर, भगत नगर, पानीपत
10	उर्मिला देवी पत्नी स्व० श्री जयप्रकाश	सामान्य	पानीपत	गांव कुलासी, जिला झज्जर
11	हवा कौर पुत्री स्व० श्री अशोक कुमार	सामान्य	रोहतक	गांव गिवाना, जिला सोनीपत।
12	विद्यावती पत्नी स्व० श्री तबीर सिंह	सामान्य	रोहतक	गांव राजल गढी, जिला सोनीपत
13	तेज सिंह पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र	सामान्य	चतुर्थ वाहिनी	गांव घुसकानी, जिला रोहतक

	सिंह			
14	विनोद कुमार पुत्र स्वं श्री धर्म सिंह	सामान्य	अम्बाला	गांव नसीरपुर, जिला सोनीपत
15	कृष्ण चन्द पुत्र स्व० श्री रणधीर सिंह	सामान्य	द्वितीय वाहिनी	गांव निजामपुर, जिला सोनीपत
16	सुभाश चन्द पुत्र श्री साधु राम	सामान्य	यमुना नगर	गांव ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र
17	करण सिंह पुत्र स्वं श्री सुखबीर सिंह	सामान्य	अम्बाला	गांव पिन्जौर, पंचकूला
18	कृष्ण सिंह पुत्र स्व० श्री सरण सिंह	यथोपरी	गुडगांव	गांव अदलपूर, महेन्द्रगढ
19	संजय कुमार पुत्र स्व० श्री वेद प्रकाश	यथोपरी	अम्बाला	गांव फोगट संजरवास, भिवानी

20	संजय कुमार पुत्र स्व० श्री रोहता । सिंह	यथोपरी	रेवाडी	गांव जोरा गी, गुडगांव
21	विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह	यथोपरी	चतुर्थ वाहिनी	गांव बरोना, सोनीपत
22	संजीव कुमार पुत्र स्व.० श्री नसीब सिंह	यथोपरी	कुरुक्षेत्र	गांव हबतपुर, यमुनानगर
23	हेमराज पुत्र स्व० श्री ब्रह्म सिंह	यथोपरी	गुडगांव	गांव काकरी, फरीदाबाद
24	अजय कुमार पुत्र स्व० श्री औम प्रका ।	यथोपरी	जी० आर० पी	म० न० 167 / 27 जवाहर नगर, सोनीपत
25	प्रदीप कुमार पुत्र स्व० श्री चतर	यथोपरी	चतुर्थ वाहिनी	गांव बडौदा, सोनीपत

	सिंह			
26	अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री बलवान सिंह	यथोपरी	चतुर्थ वाहिनी	गांव मलिक कालौनी, सोनीपत
27	विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री हुक्म सिंह	यथोपरी	चतुर्थ वाहिनी	गांव सपेरा, जिला सोनीपत
28	विजय पाल पुत्र स्व० श्री औम प्रका ।	यथोपरी	चतुर्थ वाहिनी	गांव हसनपुर, जिला गुडगांव
29	सुनीता रानी सपुत्री स्व० श्री राज कुमार	यथोपरी	सिरसा	गांव चेनात, जिला हिसार
30	अ गोक कुमार पुत्र स्व० श्री रधुबीर सिंह	यथोपरी	हिसार	गांव मोरखडी, रोहतक
31	हरदीप सिंह	सामान्य	हिसार	गांव कथूरा,

	पुत्र स्व० श्री राम कुमार			सोनीपत
32	बिरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री दलबीर सिंह	यथोपरी	जींद	गांव पिलाना, रोहतक
33	सज्जन कुमार पुत्र स्व० श्री जगदी । चन्द्र	यथोपरी	कैथल	गांव रिवाडी खेडा, झज्जर
34	रजनी । कुमार पुत्र स्वं श्री रणबीर सिंह	यथोपरी	जी० आर पी	गांव झिन्नसाली, सोनीपत
35	देवेन्द्र पाल पुत्र स्व० श्री रत्न सिंह	सामान्य	प्रथम वाहिनी	गांव सांपली, फतेहगढ साहिब, पंजाब
36	नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री रणबीर सिंह	सामान्य	गुडगांव	गांव बुटाना, सोनीपत

37	प्रवीण कुमार पुत्र स्व० श्री रामफल	सामान्य	फरीदाबाद	गांव वीरधाना, झज्जर
38	राजे । कुमार पुत्र स्व० श्री कर्म चन्द	पिछडे वर्ग	अम्बाला	म० नं० 486 / 5, मोहन नगर, थानेसर, कुरुक्षेत्र
39	गुरदीप सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह	पिछडे वर्ग	अम्बाला	गांव कुलवेरी, करनाल
40	बीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री सुरजभान	पिछडे वर्ग	गुडगांव	गांव बुलोट, महेन्द्रगढ
41	द र्ना देवी पत्नी स्व० श्री लाल चन्द	पिछडे वर्ग	कैथल	गांव धनाना, अम्बाला
42	सु लील कुमार पुत्र स्व० श्री सूरत राम	पिछडे वर्ग	यमुना नगर	मं० नं० 18, सैक्टर 20ए, चण्डीगढ

43	संजीव कुमार पुत्र स्व श्री वीरेन्द्र सिंह	पिछडे वर्ग	गुडगांव	गांव भटनागर, रेवाडी
44	अ गोक कुमार पुत्र स्व० श्री नर सिंह	पिछडे वर्ग	यमुना नगर	गांव डांडा, कैथल
45	देव कुमार पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र सिंह	पिछडे वर्ग	गुडगांव	गांव भाहबाजपुर, रेवाडी
46	नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री जगदी । प्रसाद	पिछडे वर्ग	गुडगांव	गांव बेहोली, महेन्द्रगढ
47	संदीप कुमार पुत्र स्व० श्री महासिंह नन्द	पिछडे वर्ग	फरीदाबाद	मकान नं० 705 डबुआ, जिला फरीदाबाद ।
48	समे सिंह पुत्र स्व० श्री रणबीर	पिछडे वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव गोकलगढ, रेवाडी

	सिंह			
49	तेजपाल पुत्र स्व० श्री सिंह राम	पिछडे वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव नथौरी बहरोर, अलवर
50	सुरे ा कुमार पुत्र स्व० श्री मोहिन्द्र सिंह	पिछडे वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव कमालपुर, रेवाडी
51	बलवनत सिंह पुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह	पिछडे वर्ग	चतुर्थ वाहिनी	गांव मउडेहराना, नारनौल
52	जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री जोरावर सिंह	पिछडे वर्ग	तृतीय वाहिनी	गांव डिचानी, महेन्द्रगढ
53	सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री रिछपाल	पिछडे वर्ग	फरीदाबाद	गांव सतलिप, दादरी गाजियाबाद, यू० पी०
54	संजय कुमार	यथोपरि	यथोपरि	गांव अटेली,

	पुत्र स्व० श्री राम चन्द्र			महेन्द्रगढ
55	सत्य प्रकाश	यथोपरि	यथोपरि	मं० नं० 456, एस जी एम नगर,एन एच 4, फरीदाबाद
56	मंगू राम पुत्र स्वं श्री हरभगवान	यथोपरि	यथोपरि	गांव जाटूसाना, रेवाडी
57	सुरे श कुमार पुत्र स्व० श्री देवी दत्त	पिछडा वर्ग	करनाल	गांव सराय औरंगाबाद, झज्जर
58	नरे श कुमार पुत्र स्व० श्री गोपी राम	यथोपरि	करनाल	गांव अर्धाना, करनाल
59	जसवन्त सिंह पुत्र स्व० श्री हरि सिंह	यथोपरि	पंचकूला	मं० नं० 64/26, ब्रह्मनगर, सोनीपत

60	राजे ा कुमार पुत्र स्व० श्री औम प्रका ा	अनुसूचित जाति	पानीपत	मं० नं० 201, दौलतपुर महम, जिला रोहतक
61	मनजीत सिंह पुत्र स्व० श्री राम मूर्ति	यथोपरि	यमुना नगर	गांव गल्लहा, जिला अम्बाला
62	राजबीर सिंह पुत्र स्व० श्री जगन नाथ	यथोपरि	चतुर्थ वाहिनी	मं० नं० 31/32, मायापुरी बैंक कालोनी
63	गुरमीत सिंह पुत्र श्री मान सिंह	यथोपरि	यथोपरि	गांव चकरा हीरा, जिला सिरसा
64	चुनी लाल पुत्र स्व० श्री रणधीर सिंह	यथोपरि	गुडगांव	गांव भगलपुर, जिला रोहतक
65	सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री विजय सिंह	यथोपरि	हिसार	गांव गौड, जिला नारनौल

66	सु नील कुमार पुत्र स्व० श्री आजादसिंह	यथोपरि	फरीदाबाद	गोब गेट, जिला सोनीपत
67	सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री दयानंद	यथोपरि	यथोपरि	मं० नं० 176 / 14, सैनीपुरा रोहतक
68	सती 1 कुमार पुत्र स्व० श्री सतपाल	यथोपरि	अम्बाला	गांव लाडवा, जिला झज्जर।
69	अतर सिंह पुत्र स्व० श्री सोहन लाल	यथोपरि	जी आर पी	गांव बि गोहा, जिला रेवाडी।

विवरण

12 सिपाहियों की सूची जो 1-4-1996 से आज तक न्यायालय के आदेशानुसार भर्ती किये गये

क० सं०	यूनिट का नाम	उम्मीदवार का नाम	वर्ग	पता
1	पुलिस अधीक्षक, गुडगांव	श्री सुन्दर पाल पुत्र श्री औम	पिछडे वर्ग	गांव मोला हेरा, जिला

		प्रकाश		गुडगांव
2	पुलिस अधीक्षक नारनौल	श्री दया राम पुत्र श्री मंगतु राम	पिछडे वर्ग	गांव नियामपुर जिला महेन्द्रगढ
3	पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र	श्री गुरबखभा सिंह पुत्र स्व० श्री करतार	पिछडे वर्ग	गांव नलवी, जिला कुरुक्षेत्र
4	पुलिस अधीक्षक, रोहतक	श्री राजपाल पुत्र श्री तेलु राम	सामान्य	गांव वैन्डी, जिला रोहतक
5	पुलिस अधीक्षक, रोहतक	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री औम प्रकाश	सामान्य	गांव खिडवाली, जिला रोहतक
6	पुलिस अधीक्षक, गुडगांव	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बाल किशन	सामान्य	गांव पटौदी, जिला गुडगांव
7	पुलिस अधीक्षक, गुडगांव	श्री इन्द्रपाल पुत्र श्री राजपाल	सामान्य	गांव कालीयाका, जिला गुडगांव

8	चतुर्थ वाहिनी, मधुबन	श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री दरियाव सिंह	सामान्य	गांव कथूरा, जिला सोनीपत
9	पंचम वाहिनी, मधुबन	श्री जगदी ा पुत्र श्री चेत राम	सामान्य	गांव डीगल, जिला रोहतक
10	पंचम वाहिनी, मधुबन	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री भाई राम	सामान्य	गांव डीगल, जिला रोहतक
11	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार	श्री भोर सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह	पिछडे वर्ग	गांव निजामपुर, जिला यमुनानगर
12	पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार	श्री धर्मपाल पुत्र श्री लाल सिंह	सामान्य	गांव सैदापुर, जिला यमुनानगर

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Expenditure Incurred on Advertisement

48. Sh. Sampat Singh: Will the Minister of State for Public Relations be pleased to state the total expenditure incurred on account of advertisements given in the newspapers/magazines and other media by the State

Government during the year 1996-97, 1997-98 and 1998-99 to-date; together with the details of the amount paid to each newspaper, magazine and other media during the aforesaid period?

Interim Reply.

“ATTAR SINGH SAINI

**Minister of State for
Public Relations, Parliamentary
Affairs, Non conventional
Energy Sources and Power
Haryana, Chandigarh**

Dated: 22-7-1998.

**Subject:- Unstarred Question No. 48 Expenditure incurred
on Advertisement**

Respected Sir,

The notice of Unstarred Question No. 48 seeking information about expenditure incurred on advertisements during the years 1996-97 and 1998-99 to-date has been received in this office on 15th July, 1998. As the information is to be given for every newspaper, magazine and other media for the above years, it shall require a lot of time to compile the requisite information.

It is, therefore, requested that a period of at least two weeks by way of extension of time may kindly be allowed for answering this question.

Yours Faithfully,

Sd/-

(ATTAR SINGH SAINI)

Minister of State for

Public Relations.

Prof. Chhatar Singh Chauhan

Speaker

Haryana Vidhan Sabha.”

Pabra Canal

49. Sh. Sampat Singh: Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state-

(a) the date on which the new Pabra Link Canal/Channel was sanctioned.

(b) the present stage of the construction fo the aforesaid canal togetherwith the time by which it is likely to be completed; and

(c) whether the compensation for the acquisition of land for the construction of the aforesaid canal/channel has been given, if so, the details thereof?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार):

(क) पावडा जोड नहर के निर्माण का परियोजना अनुसार दिनांक 02-1-1991 को स्वीकृत किया गया था।

(ख) पुलो को छोडकर, पावडा जोड नहर का निर्माण बुर्जी नं0 22000 से 31250 (अन्तिम छोर) तक पुरा हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिगृहित भूमि के बारे में दिए गए स्थगन आदे 1, जो कि मार्च 1998 में निरस्त किए गए हैं, के कारण भीर्श छोर का कार्य पहले भुरु नहीं किया जा सका। इस कार्य के लिए निविदाएं पहले ही आमंत्रित की जा चुकी हैं ओर मई 1998 में खोली जा चुकी है। बुर्जी नं0 से 22000 तक का कार्य भीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा तथा वर्ष 1998 के अन्त तक इसके पूरा होने की सम्भावना है।

(ग) जिला राजस्व अधिकारी/भूमिग्रहण अधिकारी, हिसार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 3512520 रु 30 पैसे के निर्णय की घोशणा की जिसमें से 2005534 रु 80 पैसे की राशि का भुगतान भूमि मालिकों को भूमि के मुआवजे के रूप में किया जा चुका है। भोश 1506285 रु 50 पैसे की राशि 1, जो कि गांव सैनियाना तथा चगार खेडा से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा है क्योंकि भूमि मालिकों ने इसे लेने से इंकार कर दिया है।

Memorandum of Understanding on Yamuna Water

50. Sh. Sampat Singh: Will the Minister of State for Irrigation be pleased to state-

(a) whether any Memorandum of understanding between Haryana, U.P., Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi regarding allocation of surface flow of Yamunanagar was signed on 12-5-1994; if so, the details thereof;

(b) whether the aforesaid accord is in the interest of Haryana State; and

(c) if the reply to para (b) above be in negative, whether there is any proposal under consideration of the Government to reject the said accord?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री हर्ष कुमार):

(क) जी हां, यमुना के सरफेस फलो (सतह बहाव) के बंटवारे के बारे में पांच बेसीज राज्यों के मुख्य मंत्रियों जो कि: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मध्य तत्कालीन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में 12-5-94 को समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

इस समझौते के अनुसार अंतिम स्तर पर निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न राज्यों में बंटवारा निर्धारित हुआ:-

हरियाणा	5.730 बी० सी० एम०
---------	-------------------

उत्तर प्रदेश	4.032 बी० सी० एम०
राजस्थान	1.119 बी० सी० एम०
हिमाचल प्रदेश	0.378 बी० सी० एम०
दिल्ली	0.724 बी० सी० एम०
कुल	11.983 बी० सी० एम०

(ख) जी हां।

(ग) नहीं।

Releasing of Grant to Maharaja Agarsen Medical College

51. Shri Sampat Singh: Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state-

(a) whether any agreement between Haryana Government and Maharaja Agarsen Medical Education & Science for Research Society was signed on June, 1990; if so, the details thereof; and

(b) whether the amount of grant was released to the society as per aforesaid agreement till to-date; if so, the yearwise details thereof?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मडिया):

(क) जी हां, हरियाणा सरकार तथा महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं विज्ञान बोध समिति अग्रोहा के बीच 1-6-90 को एक इकरारनामा हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि राज्य सरकार भवन निर्माण/सामग्री (अनावर्ती) खर्च का 50 प्रतिशत व आवर्ती खर्च का 99 प्रतिशत वहन करेगी। सरकार ने 267 एकड़ 14 मरले भूमि 99 साल की लीज पर समिति को एक रुपया वार्षिक नाम मात्र किराये पर दी हुई है।

(ख) सरकार ने समिति को अनावर्ती अनुदान 31-3-96 तक निम्न प्रकार जारी किया:-

वर्ष	राशि
1990-91	6071000.00
1991-92	7850000.00
1992-93	10650000. 00
1993-94	14828000. 00
1994-95	13648000. 00

1995-96	7463000.00
कुल	60510000.0

Expenditure Incurred on the Repair/Construction of Roads

52. Dr. Virender Pal Ahlawat: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state the constituency wise expenditure incurred on the construction of new roads and on repair in the state during the period from July 1997 to June 1998?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह): जुलाई, 1997 से जून, 1998 तक की अवधि के दौरान राज्य में निर्विचार क्षेत्रवार नई सडको के निर्माण तथा मुरम्मत पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नई सडको के निर्माण पर हुआ खर्च (रु लाखो में)	मुरम्मत पर हुआ खर्च (रु लाखो में)
1	कालका	339.30	231.28
2	नारायणगढ	5.15	104.60
3	साढौरा	39.90	62.96
4	छछरौली	6.04	44.47

5	जगाधरी	16.26	31.07
6	यमुनानगर	—	41.33
7	मुलाना	36.88	70.01
8	अम्बाला कैँट	1.67	—
9	अम्बाला सिटी	5.01	45.51
10	नग्गल	10.38	79.40
11	इन्द्री	17.30	58.30
12	नीलोखेडी		56.81
13	करनाल	3.55	29.06
14	जुंडला	0.42	71.03
15	घरौँडा	2.28	41.66
16	असंध	—	58.66
17	पानीपत	—	73.18
18	समालखा	15.40	71.28
19	नौलथा	10.83	53.96

20	भाहबाद	5.97	137.31
21	रादौर	25.15	41.18
22	थानेसर	5.26	132.82
23	पेहवा	5.98	130.98
24	गुहला	—	46.85
25	कैथल	42.39	109.25
26	पुन्डरी	6.65	63.02
27	पाई	0.67	60.46
28	हसनगढ	15.01	41.35
29	किलोई	11.95	73.11
30	रोहतक	10.14	11.13
31	मेहम	6.21	129.21
32	कलानौर	16.59	85.46
33	बेरी	—	113.55
34	सालावास	61.43	179.71

35	झज्जर	108.46	97.11
36	बादली	0.21	57.70
37	बहादुरगढ	45.50	61.46
38	बडौदा	6.68	52.70
39	गोहाना	9.04	76.02
40	कैलाना	0.02	50.89
41	सोनीपत	0.26	77.29
42	राई	—	44.94
43	रोहट	6.44	100.21
44	कलायत	4.82	23.94
45	नरवाना	—	58.94
46	उचाना	—	61.00
47	राजौंद	—	36.75
48	जींद	12.55	83.19
49	जुलाना	1.90	81.55

50	सफीदो	0.43	55.88
51	फरीदाबाद	—	19.55
52	मेवला महाराजपुर	5.80	71.26
53	वल्लभगढ	0.04	46.98
54	पलवल	14.71	72.00
55	हसनपुर	16.16	45.00
56	हथीन	0.53	57.00
57	फि0 झिरका	6.66	95.85
58	नूंह	0.96	58.50
59	तावडू	5.31	80.76
60	सोहना	27.87	81.31
61	पटौदी	6.72	86.30
62	गुडगांव	0.22	76.90
63	बाढडा	28.47	26.16
64	दादरी	41.18	66.61

65	मुंढाल	49.77	82.48
66	भिवानी	70.04	122.02
67	तो गाम	18.30	127.52
68	लोहारु	2.18	80.32
69	बवानी खेडा	46.57	105.99
70	बरवाला	14.96	103.16
71	नारनोंद	1.78	119.87
72	हांसी	0.32	106.88
73	भट्टू कलां	94.44	12.58
74	हिसार	27.41	38.25
75	धिराय	7.59	89.31
76	टोहाना	61.90	107.54
77	रतिया	77.61	31.92
78	फतेहाबाद	83.29	67.98
79	आदमपुर	65.51	42.06

80	दडबा कलां	32.55	43.51
81	ऐलनावाद	22.00	73.15
82	सिरसा	0.15	34.70
83	रोडी	8.10	53.14
84	डबवाली	—	39.47
85	बावल	4.28	161.33
86	रिवाडी	25.43	45.92
87	जाटुसाना	32.34	98.46
88	महेन्द्रगढ	24.24	50.88
89	अटेली	2.30	65.35
90	नारनौल	0.60	31.93
	कुल	1848.37	6418.94

ध्यानाकर्षण प्रस्तावो इत्यादि की सूचनाएं

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बस में बम विस्फोट संबंधित हमारी एक कालिंग अटैं न न मो न न नं0 8 थी वह आपने यह कह कर रद्द कर दी कि alleged incident took place in Delhi which falls

within jurisdiction of Delhi Administration. अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा रोडवेज की जिस बस में बम दिल्ली में फटा वह बम सफीदो और पानीपत के बीच के एरिया में रखा गया था। (विधन) दिल्ली प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम हरियाणा में भेजी है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश इस प्रकार के अपराधियों की भारणस्थली बन गया है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, आप हर चीज को डिसअलाउ कर देते हैं। *****

श्री अध्यक्ष: यह कल ही डिसअलाउ हो चुका था।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कल जो मामला था वह दूसरा था और आज जो यह मामला है वह दूसरा है क्योंकि यह मामला हरियाणा प्रदेश से जुड़ा हुआ है। यह बम सफीदो और पानीपत के बीच के एरिया में उस बस में रखा गया और दिल्ली प्रदेश ने अपनी एक पुलिस टीम इस बात का पता लगाने के लिए हरियाणा में भेजी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस मामले को अलाउ कर दें। (विधन)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौटाला साहब ने गिनीज बुक का जो जिक्र किया है वह चेयरमैन साहब की गरिमा के अनुरूप नहीं है इसलिए उसको रिकार्ड से निकलवाने की कृपा करें। (विधन)

श्री अध्यक्ष: गिनीज बुक का जो जिक्र चौटाला साहब ने किया है उसको रिकार्ड न किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए बम विस्फोट के बारे में मैं थोड़ी क्लैरिफिके ान कर दूँ। हमारी रिलायेबल इन्फर्मे ान है कि दिल्ली में जो बम फटा है वह इस किस्म का बम था कि वह 15 मिनट से ज्यादा का टाईम का बम नहीं हो सकता है। 15 मिनट से ज्यादा उसकी लिमिट ही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 15 मिनट में ही वह बम हरियाणा की हद में रख दिया गया हो और 15 मिनट में वह बम दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है, सारी बात सामने आ जाएगी। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: क्या यह तय हो गया है कि यह टाईम बम ही था?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हा यह टाईम बम ही था। जिस किस्म का यह बम था उसकी ड्यूरे ान 15 मिनट से ज्यादा नहीं है।

श्री सम्पत सिंह: क्या इस बारे में फोरेंसिक लैबोरेट्री की रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री बंसी लाल: रिपोर्ट अभी कहां आ गई, अभी तो पुलिस इन्वैस्टीगे ान कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी

रिलायेवल इन्फर्मे ान यही है कि इस किस्म का बम 15 मिनट से ज्यादा डयूरे ान का होता नहीं है। (विधन)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई फाईन्डिंग ही नहीं आई है। (विधन)

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास भी अभी इस बारे में इन्फर्मे ान है। लेकिन समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी एक टीम इन्कवायरी के लिए हरियाणा में भेजी है। वह टीम इस बारे में जानकारी लेने के लिए आई है।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, अगर आपके पास कोई इन्कवायरी की रिपोर्ट हो तो आप बता दें।

श्री औम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह समाचार पत्रों में छपा है कि दिल्ली पुलिस ने इस बात की इन्कवायरी के लिए अपनी एक टीम भेजी है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मेरी इन्फर्मे ान के मुताबिक जिस किस्म का यह बम था वह 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था, वह 15 मिनट में ही फट जाना था। क्या इनके पास पुलिस से ज्यादा इन्फर्मे ान है या जो पुलिस इन्कवायरी कर रही है उसने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार को दे दी है? अध्यक्ष महोदय, ये गलत ढंग से बात को सदन में पे ा करने की कोि ा ा कर रहे हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, गलत बात को गलत ढंग से पे ा करने की कोि ा ा ये करते है मैने तो स्पष्ट कहा है कि जिस क्वालिटी का वह बम था वह 15 मिनट मे ही फट जाता है ।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता ने जो रिप्लाइ दिया है उस बारे में मै यह कहना चाहूंगा कि सफीदो से दिल्ली पहुंचने के लिए दो ही रास्ते है एक तो वाया पानीपत होकर और दूसरा वाया रोहतक—बहादुरगढ होकर ।

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगवीर सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय, तीसरा रास्ता भी है वह वाया गोहाना सोनीपत होता हुआ दिल्ली को जाता है ।

वास्तुकला राज्य मंत्री (श्री राजकुमार सैनी): अध्यक्ष महोदय, इन्होने यह आईडिया कैसे लगाया कि उस बस में सफीदो में ही बम रखा गया था ।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से वाया मुरथल दिल्ली जाने वाली बसें दिल्ली बाई पास पर सवारियां छोडती है वहां से और भी सवारियां चढती है । आधा धंटा दिल्ली मे चलने के बाद ही कोई भी बस अंतराष्ट्रीय बस अड्डे दिल्ली पर पहुंचती है । इस बीच में बस कहीं पर भी नही रुकती है । इसलिए मुख्य मंत्री जी अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें ।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि बस दिल्ली बस अड्डे पर 11:15 बजे पर पहुंची और बम एक्सप्लोजन 11:35 पर हुआ यानि 20 मिनट बाद वह बम फटा।

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मैंने काल अटेंशन मोशन बडथल गांव की पंचायत से संबंधित भूमि को हथियाने के बारे में दिया था जिसको आपने रिजैक्ट कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: राणा जी, जिस तरह से काल अटेंशन मोशन देनी चाहिए थी वह आपने नहीं दी। आपकी काल अटेंशन मोशन रुलज़ के हिसाब से नहीं थी इसलिए इसको रिजैक्ट कर दिया गया है। (विघ्न) राणा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपकी यह मोशन डिस-अलाऊ हो चुकी है। (गोर एवं व्यवधान) आप इस बारे में चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से पूछ लें कि किस तरह से काल अटेंशन मोशन दी जाती है। (गोर एवं विघ्न) आप बैठ जाएं।

श्री जय सिंह राणा: ***** ।

श्री अध्यक्ष: ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, जय सिंह राणा जी जिस जमीन से संबंधित बात कर रहे हैं। मैं इनको

बताना चाहूंगा कि इस सरकार से पहले इनकी सरकार थी तो उस वक्त गोहाना के अंदर क्या हुआ था। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठें। दलाल साहब, आप थोडा अपनी बात को दुरुस्त करे क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस का राज था तो राणा साहब इंडीपेंडैन्ट एम0 एल ए0 थे और इनका राज नहीं था। (विघ्न)

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, आज भू-माफिया वहां पर जमीनो पर गलत ढंग से कब्जे कर रहा है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। अध्यक्ष महोदय, जमीनो पर कब्जे करना या गलत ढंग से इनकी रजिस्ट्रीयां करवाना यह तो कांग्रेस पार्टी के राज का काम है। पिछली बार इनके राज में गुडगांव मे जमीनो पर कब्जे हुए थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीट पर बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है कि गुडगांव जिले के कई गांवो की कई सौ एकड जमीनो पर इनके राज मे उनके मालिको को तहसील मे बुलाकर आर्मी के जनरल के नाम पर पट्टा करवाया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीटो पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। हमारी सरकार में कोई भू-माफिया नहीं है और न ही हमारी सरकार इस तरह के किसी अपराधी तत्वों को प्रोत्साहन देती है। अगर माननीय सदस्य राणा साहब के नोटिस में कोई इस तरह की बात थी तो इनको वहाँ के अधिकारियों से इस बारे में मिलना चाहिए था और अगर वे फिर भी कोई कार्यवाही नहीं करते तो फिर इनको महकमे के मंत्री जी से या मुख्य मंत्री जी से मिलकर अपनी बात करनी चाहिए थी। (विधन) इनके अपने राज में गुडगांव और फरीदाबाद जिले की जमीनों के फर्जी दस्तावेज मंजूर करवाकर अपनी पार्टी के लोगों और अपने चहेतों को दिए गए।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पीछे क्या हुआ या क्या होता रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब भी इनके राज में कंटीन्यू रहेगा। क्या ये उसको कंटीन्यू रखना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हम कंटीन्यू नहीं रखना चाहते हैं। ये अभी पिछली बातों को भूले नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का प्रैर पहले गुडगांव और फरीदाबाद की तरफ था। लीडर आफ दी हाउस भी इस बात को मानेंगे कि वहाँ पर जमीनों के कितने स्कैंडल हुए। हम को भी पता है कि कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि दिल्ली का प्रैर अब करनाल, पानीपत और बहादुरगढ़ के हल्कों की

तरफ बढ़ना भुरु हो गया है। आज इस भू-माफिया जिनको प्रोपर्टी डीलर कहना भायद ज्यादा अच्छा भाब्द होगा, इस किस्म की हरकते, इस किस्म की बाते अब इन इलाको में भुरु हो गयी है। इससे पहले कि यहां पर भी कोई एक बडा स्कैंडल इस तरह का उभरकर आए, अगर माननीय सदस्य इस बारे में अपनी कोई बात यहां पर रखना चाहते है तो उसमें बुराई क्या है? वह केवल 100 एकड जमीन की ही बात नही है बल्कि उन तत्वो को सकीय होने से रोकना भी है ताकि कोई भी किसी पंचायत की जमीन पर गलत ढंग से कब्जा न कर सके। अध्यक्ष महोदय, करनाल जैसे क्षेत्र मे इस सौ एकड जमीन का दस लाख रुपये प्रति एकड तो साल का पट्टा ही हो सकता है। इसलिए मै यह चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियो में सरकार का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे तत्वो को किसी भी जमीन को हडपने से रोके।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जो बात चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे है अगर इस किस्म का कोई तत्व है तो ये सदन मे बताएं या सदन के बाहर बताएं, हम ऐव न लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इसलिए ही हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए है। जो करनाल जिले में बडथल गांव है उसमें 98 एकड जमीन पंचायत की है उस जमीन को कुछ लोग ट्रस्ट के नाम से हथियाना चाहते है। पंचायत की जमीन इस तरीके से ट्रांसफर होनी चाहिए जिस तरीके से डी0 सी0 रिपोर्ट करते रहे है और डायरैक्टर पंचायत उसके सैव न देते रहे है।

करनाल और कुरुक्षेत्र में इसका प्रैार पड़ेगा। इन इलाकों में पंचायतों की जमीनें भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, मेरी यह सबमिान है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पूरे प्रदेश के अंदर करनाल जिले के जिस एक गांव का नाम लिया है हम उसकी जांच करेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन इसके साथ ही चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को अपनी पार्टी के राज के दिन याद करने चाहिए। इनकी सरकार ने गुडगांव और फरीदाबाद में कोई गांव नहीं छोड़ा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जिनको ये सुनना चाहते हैं वे आज हैं नहीं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ और इनको बताना चाहूंगा कि जितनी पंचायतों की जमीनें चाहे वह भामलात हो चाहे और किसी किस्म की हो या चाहे ट्रस्ट की हो, अगर किसी जमीन को कोई आदमी हथियाने की कोशिश करता है तो आप मेरे नोटिस में लाए, उस जमीन को मैं बचाऊंगा।

श्री खुर्द अहमद: हम तो यह मामला आपके नोटिस में लाए हैं, इसके आप जरूर बचाएं। This is our request.

श्री बंसी लाल: इनके पार्टीकुलर्ज दे देना हम कार्यवाही कर देंगे।

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह): अध्यक्ष महोदय, सितम्बर 1997 में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सारे बी० डी० ओज० और ऐ० डी० सीज० की कांफ्रेंस बुलाई थी उसमें सबको हिदायत दी गई थी कि एक गांव पहले लेकर उसकी पैमाइश व निदान देही करवाएं और फिर आगे की कार्यवाही करें। इस प्रोग्राम के तहत थ्रू-आउट कार्य चल रहा है। गुडगांव जिले में बहुत वैल्यूएबल जमीन है। वहां मैं दो बार विजिट कर चुका हूं। इनके राज में एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ को पंचायत की जमीन यूं ही सौंप दी गई थी वह जमीन भौंडसी गांव में है। इस प्रकार जहां भी नाजायज कब्जे हैं हम उन्हें छुड़ाएंगे।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कभी टाइम दे दिया करें। फिर आप कहते हैं कि मैं रोला मचाता हू। (विघ्न)

श्री खुर्द अहमद: सर, आपकी इजाजत से इस हाउस का ध्यान एक खबर की तरफ दिलाना चाहता हूं। The headline of the news is- "Who can use red lights on cars." मेरे पास 25 की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट 27 की आई है। जब यह लिस्ट बनती है तो रैड लाइट कहां कहां यूज हो, इस बारे में इस हाउस की ओर ख्याल सबसे बाद में जाता है। इस लिस्ट में पहले तो सारे एम० पीज०, एम० एल० एज० साफ थे। अब जो लिस्ट बाद में आई है उसमें एम० पीज०, एम० एल० ए के नाम तो करैक्ट कर दिए गए हैं लेकिन विधान सभा की कार्यवाही चलाने के लिए जिस

अधिकारी की आपको जरूरत पडती है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। there is an institution of a Secretary in this House.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, किसी एम एल ए या एम पी का नाम इस लिस्ट से कभी डिलीट नहीं किया गया। जिस आदमी ने गलती से यह नाम काट दिये थे उन नामों को फिर से दुरुस्त कर दिया गया है। यह गलती परिवहन विभाग के सैक्रेटरी या कमी नर के कार्यालय से हो गयी थी और जिस कर्मचारी ने यह गलती की थी उसकी कल ही एक्सपलेने इन काल कर ली गई है।

श्री खु र्द अहमद: अध्यक्ष महोदय, इसमें सैक्रेटरी विधान सभा ओर सै इन जज का भी नाम होना चाहिए क्योंकि अगर सैक्रेटरी विधान सभा को कही रास्ते में डिटें कर लिया तो इस सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? उनका नाम भी होना चाहिए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में इस बारे में सब बातें खु र्द अहमद जी से हो गई है, इन्होंने अपना नाम दर्ज कराना था सो वह हो गया है (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैने तो चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से यह पूछना था कि भूमि माफिया कौन थे? क्योंकि हम तो इस सदन में नये आये हैं परन्तु चौधरी वीरेन्द्र सिंह इस सदन में मौजूद नहीं हैं। मेरा अपना कोई क्वै चन नहीं था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौ० खु र्द जी बता देंगे ।

श्री खु र्द अहमद: जिन भूमि माफिया को मैं जानता था उनको तो छः महीने की सजा हो चुकी है । (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने चौटाला साहब ने और कुछ मेंबरज ने एक काल अटैं इन मो इन दिया था जोकि गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी के बारे में था । हरियाणा के जितने भी कालेज और यूनिवर्सिटीज का गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिए इन था उसको खत्म कर दिया गया है और गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी को एक रेजीडेंि ायल यूनिवर्सिटी बना दिया है जबकि गुरु जम्भे वर हिन्दुस्तान में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको एक साल के अन्दर यू० जी० सी० ने मान्यता प्रदान की हैं और ग्रान्ट दी है । इसी पैटर्न पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने अब एक एक्ट बनाया है और वे भी इसे फोलो कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आपका काल अटैं इन मो इन डिस—अलाउ कर दिया गया था ।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अपने कल यह कहा था कि यह काल अटैं इन मो इन अंडर कंसीड्रे इन है और डिस अलाउ नहीं किया गया है । स्पीकर साहब, इस बात का सवाल नहीं है कि अकेले प्र ासनिक मुददे ही सामने आये बल्कि अर्जेन्ट मैटर भी सामने आ सकते हैं । इससे अर्जेट मुददा और क्या होगी कि जहां प्रौफै इनल कोर्सिज चलते हो और उन कालेजो का

यूनिवर्सिटी से एफीलिए उन खत्म कर दिया जाये? स्पीकर साहब, आज प्रौफैनेलिज्म का जमाना है। आज बी0 ए0 और एम0 ए0 करने से बात नहीं बनेगी। आज तो बिजनैस मैनेजमेंट, फार्मेसी और टैक्नीकल कोर्सिज का जमाना है। बिजनैस मैनेजमेंट, फार्मेसी और इंजीनियरिंग टैक्नोलोजी के कोर्सिज गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी में चल रहे थे। एक डैलीगे उन भी यहां आया था, आज जापान और फिनलैंड इस यूनिवर्सिटी को फोलो कर रहे हैं लेकिन उस यूनिवर्सिटी का एफीलिए उन आप खत्म कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्या इनमें से कोई कोर्स बन्द कर दिए गये हैं?

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जितने कालेज जैसे इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज या टैक्नीकल कालेज हैं उनका एफीलिए उन इस यूनिवर्सिटी से खत्म कर दिया है जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने भी इस यूनिवर्सिटी की बिनाह पर ही एक एक्ट बनाया है। एक यूनिवर्सिटी जो कि राईजिंग स्टेज पर है उसकी एफीलिए उन इस बिनाह पर खत्म नहीं की जाये कि वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मेरी मांग यह है कि इस पर डिस्कशन के बाद सरकार रिप्लाय दे कि किन कारणों से इसको डिस्टिफिलिएट किया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा और भी कई माननीय सदस्यों ने उठाया था और आज भी मैंने अपने जवाब में यह बात कही कि गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी का कोई किसी तरह का दर्जा हम ने नहीं घटाया है। हमारी सरकार के समय में हम ने इस वि विद्यालय के लिए ग्रांट्स दी है और आनॅगोइंग वर्क्स जो अधूरे पडे थे, उन को पूरा किया है। हमारे भासनकाल में इस यूनिवर्सिटी ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मान्यता प्राप्त की है। हम ने इस पर करोडो रुपये खर्च किए है। यू० जी० सी० ने भी इसको मान्यता दी है। अध्यक्ष महोदय, हम ने इस वि विद्यालय मे नये पुराने लगभग 62 टैक्नीकल कोर्सिज भुरु किए है। जब हमारी सरकार बनी तब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लोगो ने महामहिम राज्यपाल महोदय से दरखास्त की कि कुरुक्षेत्र मे जो रीजनल इंजीनियरिंग कालेज है, वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की चारदीवारी मे है तथा उसका छात्रावास भी इसी वि विद्यालय के प्रांगण मे है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते है कि कुरुक्षेत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है, इसके साथ और कोई चीज जोडने की आव यकता नहीं है। जब कभी भी किसी को दि ा निर्दे ा की आव यकता होती है, चाहे महाभारत की लडाई में अर्जुन की बात हो अथवा विधान सभा की बात हो, तो उस समय सभी को कुरुक्षेत्र याद आता है। कुरुक्षेत्र वि विद्यालय की चारदीवारी में रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई थी। पिछले तीन वर्ष के समय मे जब इंजीनियरिंग के छात्रो को अपने परिणाम समय पर नहीं प्राप्त होते थे तो उनका

कैरियर खत्म हो गया। हमारी सरकार आते ही लोगो ने यह मांग की कि इस कालेज को इसकी पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के साथ जोडा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ, गुडगांव और फरीदाबाद के कालेज एम0डी0यू0 रोहतक के नजदीक पडते है और हिसार से दूर पडते है। इस प्रकार से सारी बातो को देखते हुए हमने गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी को टैक्नीकल यूनिवर्सिटी का स्वरुप दिया है। इसमें इलैक्ट्रॉनिक्स, एम0 बी0 ए0, बी0 ई0 इत्यादि कोर्सिज चल रहे है। जिस प्रकार से कैंब्रिज और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जैसे 40-50 वि वविद्यालय दुनिया भर मे समझे जाते है। उन के हिसाब से हम ने हरियाणा में एक्सक्ल्युसिवली इस यूनिवर्सिटी को रैजिडेंसियल स्टेटस दिया है। इस के साथ हम ने कोई भेदभाव नही किया है। इस में कोई किसी प्रकार का राजनीतिक बात नही है। जब यह सरकार बनी थी तो उस समय भी यह कहा गया था कि गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी का आस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मै अपने माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि इस का आस्तित्व समाप्त होने का सवाल ही पैदा नही होता, बल्कि हम इस का और भी ज्यादा विकास करेंगे और इन पिछले दो सालो में हम ने करोडो रुपए इस यूनिवर्सिटी के अधुरे कार्यों पर, जो पिछली सरकार छोड कर गई थी, खर्च किए है। कही भी इस वि वविद्यालय मे किसी प्रकार की कोई असुविधा नही है और इस के साथ कोई राजनीतिक भेदभाव नही है।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी को सरकार द्वारा ग्रांटस भी दी गई है। मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है तब से इस यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांटस में कटौती की गई है। आप निःसन्देह वर्ष 1995-96, 1997-98 व 1998-99 के ग्रांटस के आंकड़े देख सकते हैं, हर साल दो-अढ़ाई करोड़ रुपए का कट लगाया जा रहा है। जब यह एक्ट इस सदन में पास होने के लिए आया था उस समय मैंने प्वायंट आउट किया था कि इसमें कई कमियां हैं। कुरुक्षेत्र वि विद्यालय के कैम्पस में जो कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कालेज है उसके बारे में मैंने भी कहा था कि यह इंजीनियरिंग कालेज उससे एफीलिएटिड नहीं होना चाहिए। जो लॉ क्लासिज है वे टैक्नीकल क्लासिज में नहीं आती। ये लॉ क्लासिज भी गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी के साथ एफीलिएटिड नहीं होनी चाहिए। उस समय भी हम सभी ने इसका विरोध किया जबकि मैंने इसकी अमैण्डमेंट मांगी थी। जहां तक ये दूरी की बात करते हैं, क्या डबवाली कुरुक्षेत्र के नजदीक है? दूरी की बात नहीं हुआ करती। साईंस यूनिवर्सिटीज ही टैक्नीकल यूनिवर्सिटीज होगी। वे जो सब्जेक्ट प्रमोट कर सकेगी वे दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकेगी। अभी रामबिलास भार्मा जी ने जिक्र किया कि कितने बढ़िया कोर्सिज हैं जैसे मास कम्यूनिके ान, इन्वायरमेंट साईंस, एम0 एस0 सी0, एप्लायड मैथेमैटिक्स, एम0 एस0 सी0 इण्डस्ट्रीयल कैमेस्ट्री, बिजनैस एडमिनिस्ट्रे ान, कम्प्यूटर साईंस इत्यादि। जिस फोरन यूनिवर्सिटी की ये बात कर रहे हैं वे टैक्नीकल

यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली टैक्नीकल यूनीवर्सिटी पूरे हिन्दुस्तान में हिसार में ही बनी थी। हिन्दुस्तान वाले बाहर से एग्जाम्पल ले आते हैं कि ये रैजिडैन्सियल यूनिवर्सिटी नहीं है इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि that is a residential university but not a technical university. That is for other purposes but not for technical purposes. ये सारे सब्जेक्ट टैक्नीकल परपज के लिए उन लडको को पढाए जाते हैं जो अनएम्पलायड रह जाते हैं ताकि उनको प्रौफैशन मिल सके। आज भी जो कम्प्यूटर जानने वाले लडके हैं उनको अमरीका वाले बुला रहे हैं। जहां तक प्रिएम्बल की बात है— that is holy. Every section of the Act can be amended but the preamble of the Act cannot be amended. You may amend the Constitution of India but you cannot amend the preamble of the Constitution of India. So, the preamble of the Act says-

“to establish and incorporate a teaching-cum-affiliating University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers of technology. Pharmacy, environmental studies, non-conventional energy sources and management studies and also to achieve excellence in these and connected fields.”

This was an affiliating University.

स्पीकर साहब, अब यह यूनिवर्सिटी किन कालेजों का एफीलिएशन करेगी जब ये रैजिडैन्सियल बन गई है? राम बिलास जी के पास इसका जवाब हो तो दें।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपको याद होगा क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया था कि दो अढाई साल पहले जब मैं और आप विपक्ष में थे तो मैंने और अपने सबसे पहले कहा था कि कुरुक्षेत्र और सोनीपत के इंजीनियरिंग कालेज इस यूनिवर्सिटी के साथ एफीलिएटिड नहीं होने चाहिए, यह एक गलत बात है। आप यह बताएं कि अगर ये यूनिवर्सिटीज अब रैजीडेंटि यल बन गई है तो क्या इससे इसकी टीचिंग या रिसर्च स्टैंडर्ड में कोई कमी आ जाएगी? आप आप और मैं दोनों ही एजुकेशन से संबंधित रहे हैं इसलिए आप बताएं कि जहां तक इस यूनिवर्सिटी के स्टेट्स का संबंध है, जहां तक एकेडमिकल स्टेट्स की बात है तो क्या इसके रैजीडेंटि यल बनने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा?

श्री सम्पत सिंह: जी हां, कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनमें फर्क पड़ेगा जैसे लाइब्रेरी। उसमें रिसर्च करने वालों को वह सुविधा अब नहीं मिल पाएगी जो पहले मिलती थी। इसलिए जो यह कालेजों की डिंस-एफीलिएटिड हो रही है, यह ठीक नहीं है। सिरसा में जो कालेज है उसके लिए इस बजट में एक पैसा भी नहीं रखा गया है। उस समय हमने यह भी कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में एन्वायरमेंटल साईंस और फोरैस्ट्री के सब्जेक्ट्स भी पढाए जाने चाहिए। अगर ये दोनों बातें इसमें और जुड़ जाती, तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में गोदारा साहब कुछ बोलेंगे या नहीं।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि जिस महानुभव ने यह युनिवर्सिटी बनाई थी उसको यह देखना चाहिए था कि इसका बाद में रिएक्शन क्या होगा।

श्री सम्पत सिंह: आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है क्या आप यह चाहते हैं कि इस का एफिलिएशन हो?

श्री मनी राम गोदारा: मैं तो यह चाहता हूँ कि कायदे कानून के हिसाब से इसमें सब कुछ हो।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात क्लैरीफाई करना चाहता हूँ। गुरु जम्भे वर जी की इज्जत मैं इन सबसे ज्यादा करता हूँ। इनका गुरु जम्भे वर के सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं है लेकिन मैं उनके सारे सिद्धांतों को मानता हूँ।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, गुरु जम्भे वर जी के हिन्दू फेथ के 20 और 9 यानी 29 सिद्धांत हैं और उनका हिन्दुस्तान में बहुत आदरणीय स्थान है। उनके नाम से हिसार का विविद्यालय बनाया गया। हमारी सरकार आने के बाद कई लोगों को यह अंदाज़ था कि इसका नाम बदला जाएगा या इसके अस्तित्व को समाप्त किया जाएगा लेकिन हमने उसके उल्टे इस विविद्यालय को, गुरु जम्भे वर जी के नाम के इस विविद्यालय को करोड़ों रुपया लगा करके आगे बढ़ाया है।

श्री सम्पत सिंह: आप उसकी ग्रांट के बारे में भी बता दें।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने कहा कि गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी की ग्रांट घटाई गई है। अध्यक्ष महोदय, उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट नहीं घटी। जो पिछले दो साल का दौर था, वह हमारे उपर आर्थिक संयम बरतने का दौर था और जितना भी यूनिवर्सिटीज थी चाहे वह गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी थी चाहे वह महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी थी और चाहे वह कृषि वि विद्यालय था सबकी ग्रांट उस समय कम की गई। सम्पत सिंह जी, आपको स्मरण होगा कि जब यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी उस समय आप भी सदन में थे, चौधरी बंसी लाल जी भी सदन में थे, मै भी सदन में था और माननीय अध्यक्ष महोदय भी सदन में थे। उस समय जब रिजनैल इंजीनियरिंग सेंटर कुरुक्षेत्र को गुरु जम्भे वर यूनिवर्सिटी के साथ लगाया जा रहा था तो हम सबने उसका विरोध किया था। यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है कि एक क्लास किसी युनिवर्सिटी में चल रही है उसको किसी दूसरी युनिवर्सिटी के साथ मिला दिया जाए। अब हमने इस युनिवर्सिटी को एक रैजीडेंटियल युनिवर्सिटी की स्वीकृति दे दी है। हमने इस युनिवर्सिटी के किसी कोर्स को बंद नहीं किया है। अब भी लगभग 62 टेक्नीकल कोर्स उस यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं। गुरु जम्भे वर युनिवर्सिटी को यू0 जी0 सी0 ने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी करार दिया है। उन्होंने इसको एक

मॉडल यूनिवर्सिटी बताया है। हमारी उस यूनिवर्सिटी के साथ कोई दुर्भावना नहीं है, उसके पीछे कोई राजनैतिक कारण नहीं है। इस बारे में कमैटी की जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के अनुसार हमने यह काम किया है। इस यूनिवर्सिटी के दर्जे को हमने नहीं घटाया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इस वि विद्यालय के बारे में चौटाला साहब व सम्पत सिंह जी की बातों को हमारे शिक्षा मंत्री जी ने तसल्ली से जवाब दिया है। लेकिन चौटाला साहब ने फरीदाबाद में किसी भीतकालीन सम्मेलन के बारे में कहा कि वहां पर 10-12 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई सम्मेलन हमने वहां पर नहीं किया।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जब मण्डियाली में किसानों को गोलियों से मारा गया था, उस समय वहां फरीदाबाद में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें नाच गाने हुए थे।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मण्डियाली में जो कुकर्म हुआ था वह भी इन्हीं का कराया हुआ था। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जब मेहम का वार्ड-इलैक्ट्रिक न हो रहा था तो इनका होम मिनिस्टर वहां पर तख्त के नीचे छिप गया था, वहां से निकाला था। चौटाला साहब के एक छोटे लडके को, जो वहां बुथ कैपचरिंग करवा रहा था, गांव के लोगो ने पकड़ लिया था। उसके बाद उनके पिता श्री के व दादा श्री के टेलीफोन आए कि किसी तरह उस लडके को गांव से निकालो। पुलिस को कहा गया कि

उसको पुलिस की वर्दी पहन कर निकाल दो। लेकिन कोई पुलिस वाला वर्दी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक सरदारो का बच्चा बेचारा नया नया भर्ती हुआ था उसको धमका कर उसकी वर्दी छिन ली और पहना कर इनके लडके को वहां से निकाल दिया गया। जब गावों वालो को इस बात का पता चला तो गांव वालो ने उस लडको को गंडासो से व दूसरे हथियारो से काट दिया। वह लडका अपने मां बाप का अकेला था। दो दिन बाद उसकी बहन की भादी होनी थी। मै इनसे पूछना चाहता हूं कि जब बैंसी गांव मे यह हो रहा था तो ये उस वक्त क्या कर रहे थे?

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ग्रेवाल कमी इन की रिपोर्ट में यह बात पूर्ण रूप से साफ हो चुकी है कि उस समय वहां अभय सिंह नहीं था। इसके बाद भी अगर सरकार यह समझती है कि अभय सिंह दोशी है तो मै सरकार को चुनौती देता हूं कल भी मैने चुनौती दी थी कि वह ग्रेवाल कमी इन की रिपोर्ट पर कार्यवाही करे, उसे लागू करे। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय की तो दूसरो पर आरोप लगाने की आदत बन गई है यह बात मै कल भी कह चुका हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि कोर्ट ने उन्हे बरी कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, कल आपने भी मुझे कहा था कि मै इनके बारे में दिया गया 5 जजो का फैसला आपको पढकर सुनाऊ। यह फैसला मै आपको पढकर सुना देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन 5 जजो ने युनानीमसली फैसला दिया है (विघ्न एवं भाोर) कोर्ट ने सूओमोटो

कन्टैम्प्ट मुख्य मंत्री के खिलाफ दिया और 5 जजों की एक बेंच मुकर्रर की। (विधन एवं भाोर)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इस कोर्ट आफ कनैटैम्प्ट के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे एक दिन पहले भी मैंने सदन में इस बारे में बताया था कि मैंने अदालत में क्या ब्यान दिया, इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है—

“Before parting with the case, I would like to make it clear that no observation made here shall be taken to have been proved for that purpose, other than this case against the present Chief Minister Ch. Devi Lal, Ch. Dharam Singh, D.I.G (C.I.D), Shri Raj Singh] Supdt. of Police, Haryana and Shri Banarsi Lal, Inspector.”

और ये सब बातें डिसकस होकर जो जजमेंट आई वह यह है—As a result of the foregoing discussion, the rule stands discharged against both the respondents. अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस मेरे और श्री हंस राज भारद्वाज के खिलाफ जारी किया गया था वह कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खिलाफ कोर्ट में कोई केस नहीं है। As if, there was no case. (Interruptions) as if no case came to the court. अध्यक्ष महोदय, पता नहीं ये लोग क्या-क्या कहेंगे और क्या न कहेंगे, क्योंकि इनकी स्कीम कामयाब नहीं हुई, ये लोग मुझे मार नहीं सके, इस बात का इन्हे दुख है। (विधन एवं भाोर)

श्री औम प्रका 1 चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जिस जजमेंट का जिक्र मुख्य मंत्री महोदय ने किया वह आई० आर० पेज नं० 166 पर है जिस के लास्ट पैरा नं० 170 में लिखा हुआ है कि—

Both the respondents are unanimously held guilty under section 12 of the Contempt of Court Act, 1970.”

यह मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट का फैसला है, 5 जजों की बैंच का फैसला है। अध्यक्ष महोदय, जो बात मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं वह तो मुख्य मंत्री जी के वकील ने बाद में कोर्ट में दरखास्त देकर कही थी कि मुझे माफ किया जाये। इसके बाद तीन जजों ने तो इन्हें माफ कर दिया लेकिन श्री एस एस संधावालिया और श्री पी सी जैन ने उन्हें माफ नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक संगीन जुर्म है और इस जुर्म को माफ नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय यह हाई कोर्ट का फैसला है मेरा नहीं (और एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में गीता को कोट किया गया और गीता में लिखा हुआ है कि—‘क्रोधार्थ भवति सम्मोहत, सम्मोहत स्मृति विभृत, स्मृति भ्रष्टम बुद्धि ना गो, बुद्धि नष्ट प्राणस्ति’। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब क्या होता है यह तो श्री राम बिलास भार्मा जी ही बताएंगे।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय हमारी मुक्ति कल यह है कि अनपठ आदमी से पाला पड गया है। (हंसी) In the last portion of the judgement, it is written-

“As a result of foregoing discussion, the rule stands discharged against both the respondents.”

जब मामला डिस्चार्ज ही हो गया तो फिर इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि क्या डिस्कस हुआ। अल्टीमेटली वह डिस्चार्ज हो गया तो फिर बाकी बात खत्म हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, भायद इनको वह बात याद नहीं है जब ये घड़ियों की चोरी में पकड़े गए थे और इनको एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ था। इस समय इनके पिता श्री ने कहा था कि यह मेरा लडको नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह लडका उनका नहीं यह तो मनी राम गोदारा का गोद हो गया, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इनको उल्टा फिर ले लिया और वे बोलने कि यह तो मेरा उत्तराधिकारी है। कई बार ये उनके उत्तराधिकारी बने और कई बार यह उनका बेटा होता ही नहीं, इनका हम क्या करें। अध्यक्ष महोदय, इनकी किस किस चीज का जवाब दें। मैं अभी इन के किस्से के बारे में कह रहा था लेकिन महम के किस्से का इनका पास कोई जवाब नहीं। ये ग्रेवाल रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, ग्रेवाल रिपोर्ट क्या है। अध्यक्ष महोदय, महम काण्ड में अगर चौटाला साहब के लडके को उस गरीब सरदार की वर्दी न पहनाई गई होती और उस सरदार के लडके को इनके लडके के कपड़े न पहनाए होते तो उस सरदार के लडके का कत्ल नहीं होता क्योंकि

वहां पर उसका कोई दु मन नहीं था। अध्यक्ष महोदय, वह लडको तो इन्होंने मरवा दिया लेकिन अपने लडके के लिए उसकी वर्दी छीन ली और पुलिस के बीच में से उसको निकाल कर ले गए। जब लोगो ने वहां पर इनके लडके के कपडे पहने हुए उस लडके को देखा तो उन्होंने सोचा कि इनका लडका जा रहा है उसके बाद लोगो ने आव देखा न ताव उसको काट डाला। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कनटैण्ट की बात करते है। जैसे कि मैने उस जज के खिलाफ ब्यान दिया था, सी० जे० एम० के खिलाफ ब्यान देने पर मेरे खिलाफ कनटैण्ट का केस तो बनना ही था। अध्यक्ष महोदय, बिजली को हाथ लगवा कर या दूसरी मंजिल से धक्का दे कर मुझे मारने का इनका प्रोग्राम था और मेरे पास अपनी जान बचाने का कोई और चारा नहीं था,, जान तो बचानी ही थी। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि महम में क्या हुआ। (विघ्न) इन्होंने जो इतने कुए खोद रखे है, उनका क्या हुआ? (विघ्न)

वाक आउट

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करते हुए पांच जजो के फैसले का जिक्र किया। (विघ्न)

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: Now this matter ends.. Zero hour is over. Nothing is to be recorded without my permission. मेरी

लीडर्ज आफ दी पार्टीज से प्रार्थना है कि वे अपनी पार्टी के ऐसे विधायक, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है उनके नाम लिख कर मेरे पास भेज दें।

श्री औम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमें कन्टैण्ट आफ कोर्ट से संबंधित मामले पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम सभी सदस्य एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(At this stage, all the members of the Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party, present in the House staged a walk out as a protest against not having been allowed to speak on the matter concerning the contempt of court.)

वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानो तथा विनियोजनो से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: जो इण्डिपेंडेंट मैम्बर्ज है अगर उनको भी बोलना है और अगर वे पहले नहीं बोले हैं तो they may please give the list of the speakers so that I may ask those members to speak. मैंने कल सदन को आ वासन दिया था कि आज चाहे रात के 9 बज जाएं, कोई भी सदस्य जिसको बोलने का मौका नहीं मिला है उसको आज समय जरूर मिलेगा।

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save the time of the House, the excess demands over grants for the year 1993&94 on the order paper (Nos. 3,5,6,8,15,18,23 and 25) are deemed to have been read

and moved together and a general discussion on the excess demands is permitted. However, the members are requested to indicate the demand No. on which they wish to raise discussion while speaking.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 26917967** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Home**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 13747787** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Excise & Taxation**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 434177** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Finance**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 70452773** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Building & Roads**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 237850309** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Irrigation**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 17108328** be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Animal Husbandry**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 78061212** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Transport**.

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 23079146** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Loans and Advances**.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बोलने की बात आ रही है मुझे बोलने का समय नहीं मिला था तो क्या अब मैं बोलू।

श्री अध्यक्ष: मैं यह कह रहा हूँ कि जिन मैम्बर्ज को पहले बोलने का समय नहीं मिला है उनकी लिस्ट बनाकर मेरे पास भेज दे ताकि उन मैम्बर्ज को बोलने का समय मिल सके।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं मिला था।

श्री अध्यक्ष: अभी आप बैठ जाए। यह जो एक्सैर डिमांड 1993-94 है इस पर कोई डिस्कान नहीं होती। इसको बिना डिस्कान के पास कर लेते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, आप उन सदस्यों को ही बोलने का समय देना जिनको अभी तक बोलने का

समय ही नहीं मिला हो। अध्यक्ष महोदय, 1993-94 की ऐक्सैस डिमांड को छोड़कर बाकी सब पर इकट्ठी ही डिस्कान करवा लें।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर, 1993-94 की ऐक्सैस डिमान्डज को हम पास कर लेते हैं और बाकी पर बाद में इकट्ठी डिस्कान करवा लेंगे।

Mr. Speaker: Now, I shall put various demands to the Vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 26917967** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Home**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 13747787** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Excise & Taxation**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 434177** be made to regularize the charges already incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Finance**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 70452773** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Building & Roads**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 237850309** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Irrigation**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 17108328** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Animal Husbandry**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 78061212** be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Transport**.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 23079146** be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1993-94 in respect of **Loans and Advances**.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion and voting on the demands for grants on Budget for the year 1998&99 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands for grants on the order paper will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion. The notices of cut motions given by Sarvshri Capt. Ajay Singh, Sampat Singh, Ram Pal Majra, Khurshid Ahmed and Ashok Kumar, M.L.As on demand No. 2, Sarvshri Randeep Singh, Capt. Ajay Singh, Ram Pal Majra, Sampat Singh, M.L.As on Demand No.3, Sarvshri Capt Ajay Singh, Birender Singh and Khurshird Ahmed, M.L.As on Demand No.4, Sarvshri Birender Singh, Capt. Ajay Singh, Sampat Singh, Khurshid Ahmed and Satvinder Singh Rana, M.L.As on Demand No. 8, Sarvshri Randeep Singh, Khurshid Ahmed, Sampat Singh, Ram Pal Majra and Capt. Ajay Singh, M.L.As on Demand No. 9, Sarvshri Sampat Singh, Capt. Ajay Singh, Satvinder Singh, Birender Singh and Khurshid Ahmed,

M.L.As on Demand No. 10, Sarvshri Sampat Singh, Khurshid Ahmed, Capt. Ajay Singh and M.L.As on Demand No. 11, Sarvshri Randeep Singh, Khurshid Ahmed, Capt. Ajay Singh and Ram Pal Majra, M.L.As on Demand No. 13, will also be deemed to have been read and moved.

That a sum not exceeding **Rs. 28462000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 28836000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 995689000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 586479000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 1763073000-** for revenue expenditure and **Rs. 100000000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 253584400-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 3- Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 311423000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 660355000-** already

voted on account) in respect of charges under **Demand No. 4- Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 195884000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 228818000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 5- Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 2759106000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 2654192000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 6- Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 3160818000** for revenue expenditure and **Rs. 933000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 4329758000-** and capital expenditure amount of **Rs. 467000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 7- Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 2048549000** for revenue expenditure and **Rs. 1536145000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 998503000-** and capital expenditure amount of **Rs.**

347348000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 8- Building & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 7509302000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 6275510000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 9- Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 3540770000** for revenue expenditure and **Rs. 1097773000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 2571147000-** and capital expenditure amount of **Rs. 516327000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 10- Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 319464000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 196533000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 11- Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 340998000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 292179000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 12- Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 1811715000** for revenue expenditure and **Rs. 27836000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 851171000-** and capital expenditure amount of **Rs. 9164000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding **Rs. 92654000** for revenue expenditure and **Rs. 918379000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 142117000-** and capital expenditure amount of **Rs. 3968447000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 14- Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 2333738000** for revenue expenditure and **Rs. 3387828000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 5744700000-** and capital expenditure amount of **Rs. 2478172000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 15- Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 295318000** for revenue expenditure and **Rs. 149217000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs.**

143424000- and capital expenditure amount of **Rs. 41183000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 16- Industries.**

That a sum not exceeding **Rs. 1536667000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 980934000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 17- Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 515179000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 481701000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 18- Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs. 53376000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 28407000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 19- Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 600054000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 222961000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 20- Forest.**

That a sum not exceeding **Rs. 821354000-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of **Rs. 463292000-** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 21-Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 118010000** for revenue expenditure and **Rs. 111538000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 134398000-** and capital expenditure amount of **Rs. 33562000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 22-Cooperation.**

That a sum not exceeding **Rs. 2864535000** for revenue expenditure and **Rs. 295933000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 2114366000-** and capital expenditure amount of **Rs. 189567000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 23-Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 95000** for revenue expenditure and **Rs. 28867000-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of **Rs. 5375000-** and capital expenditure amount of **Rs. 13433000** already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24-Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 2478172000** out of **Rs. 6057190000-** already voted on account for capital expenditure be transferred to Demand No. 15 to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 under that Demand & balance amount of **Rs. 3579018000-** already stands on account under **Demand No. 25-Loan and Advances by State Government for the year 1998-99.**

Demand No.2

Capt. Ajay Singh;

Shri Sampat Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Shri Khurshid Ahmed;

Shri Ashok Kumar;

That Demand No. 2 of Rs. 1614211000 on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 3

Shri Randeep Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Shri Sampat Singh;

That Demand No. 3 of Rs. 447791000 on account of Home be reduced by Rs. 100000/-

Demand No. 4

Capt Ajay Singh;

Shri Birender Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

That Demand No. 4 of Rs. 971780000 on account of Revenue be reduced by Re.1/-

Demand No. 8

Shri Birender Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Sampat Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

Shri Satvinder Singh;

That Demand No. 8 of Rs. 4941345000 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-

Demand No. 9

Shri Randeep Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

Shri Sampat Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Capt. Ajay Singh;

That Demand No 9 of Rs. 13784817000 on account of Education be reduced by Re. 1/-

Demand No. 10

Shri Sampat Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Satvinder Singh;

Shri Birender Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

That Demand No. 10 of Rs. 7727577000 on account of Medical and Public Health be reduced by Re. 1/-

Demand No. 11

Shri Sampat Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

That Demand No. 11 of rs. 515997000 on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-

Demand No. 13

Shri Randeep Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

Capt. Ajay Singh;

Shri Ram Pal Majra;

That Demand No 13 of Rs. 2699886000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re. 1/-

Demand No. 15

Shri Khurshid Ahmed;

Shri Birender Singh;

Shri Sampat Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Satvinder Singh;

That Demand No. 15 of Rs. 15324438000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-

Demand No. 16

Shri Randeep Singh

Capt. Ajay Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Shri Khurshid Ahmed;

That Demand No. 16 of Rs. 629182000 on account of Industries be reduced by Rs. 100000/-

Demand No. 17

Shri Khurshid Ahmed;

Shri Sampat Singh;

Capt. Ajay Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Shri Randeep Singh;

That Demand No 17 of Rs. 2518751000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-

Demand No. 21

Shri Birender Singh;

Shri Khurshid Ahmed;

Capt. Ajay Singh;

Shri Ashok Kumar;

Shri Ram Pal Majra;

That Demand No. 21 of Rs. 1284731000 on account of Community Development be reduced by Re. 1/-

Demand No. 22

Shri Khurshid Ahmed;

Capt. Ajay Singh;

That Demand No. 22 of Rs. 397513000 on account of Co-operation be reduced by Re. 1/-

Demand No. 23

Shri Khurshid Ahmed;

Capt. Ajay Singh;

Shri Ram Pal Majra;

Shri Randeep Singh;

That Demand No. 23 of Rs. 5463111000 on account of Transport be reduced by Re. 1/-

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। अभी जो आपने कहा था कि जिन सदस्यों को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है उनको हम डिमांड पर बुलाएंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारी डिमांडज तो इकट्ठे पास नहीं होगी बल्कि एक एक करके पास होगी इसलिए जिन मैम्बर्ज के कट मोमेंट है उनको भी अगर आप हर डिमांड पर एक एक या दो दो मिनट का बोलने का समय दे दें तो यह बहुत अच्छा होगा।

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद): स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे डिमांडज पर बोलने के लिए इजाजत दी। सर, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा हमारे ऊपर आगे भी बनी रहेगी। अगर मैं इररैलवैन्ट बोलूँ तो आप खुद ही मुझे टोक दे बताएँ इसके की कोई दूसरा मुझे कुछ कहे।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं।

श्री सम्पत सिंह: सर, यह तो बहुत थोड़ा समय है। आप मुझे 50 मिनट बोलने के लिए दे दें।

श्री अध्यक्ष: नही आपको केवल 15 मिनट बोलने के लिए दिए जाते हैं।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं डिमांडज के बारे में डिमांडवाइज ही डिस्क करूंगा और उस समय ही मैं डिमांड का नम्बर भी बता दूंगा। सर सबसे पहले इस बजट की वजह से जो डिमांड किएट हुई है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, स्टेट इस बात के लिए सीरियस नहीं है कि इसका फाईनैण्डियल मैनेजमेंट ठीक किया जाए। अगर आप फाईनैण्डियल मैनेजमेंट ठीक नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद ही स्टेट इतना जबरदस्त दिवालिया हो जाएगा कि इसके पास कर्ज तो क्या ब्याज चुकाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा। सर, ऐक्चुअललायबिलिटीज 31 मार्च, 1997 को 467.78 करोड रुपये की थी जबकि अब 31 मार्च, 1998 के लिए जो ऐस्टीमेट बने हैं उसमें यह लायबिलिटीज 80527/.करोड रुपये हो जाएगी। इसलिए स्पीकर साहब, अगर स्टेट इतनी बड़ी लायबिलिटीज झेल रहा है तो फिर स्टेट जीवित कहां रहेगी? इसी तरह से दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी कर्ज की अदायगी हर साल बढ़ती ही जा रही है। आप तो कर्ज की अदायगी ही नहीं दे पाएंगे तो फिर आप नये कर्ज लेने की बात क्यों कर रहे हैं? 1995-96 में यह अदायगी 555.73 करोड रुपए की थी जबकि आज यह अदायगी 1056.95 करोड रुपये की हो गयी है। स्पीकर साहब, इसके बावजूद भी कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। लेकिन

केवल टैक्स का ही रैवेन्यू 1995-96में 1055 करोड रुपये का था और उसके बाद यह तकरीबन 1700 करोड रुपये का हो गया यानी यह रैवेन्यू भी बढ़ गया है और 700 करोड रुपये के टैक्सिज लोगो पर लगे हुए है फिर ये कैसे कह सकते है कि टैक्सिज नही लगे है? स्पीकर साहब, लेकिन इनके बदले में जनता को सर्विसिज क्या मिली है?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास भार्मा): स्पीकर साहब, यह माना कि प्रो० सम्पत सिंह जी तैयारी से बोल रहे है परंतु कल मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि 171 करोड रुपये का यह पिछला सारा भार भाराबा है और उसमें सिर्फ जो बढ़ाया है वह इतना है। अध्यक्ष महोदय प्रो० सम्पत सिंह जी 700 करोड रुपये के सेल्ज टैक्स की बात कर रहे है वह तो सरकार की कार्यकुशलता हैं हमने कोई टैक्स नही बढ़ाया है। जो रैवेन्यू कनैक्टिव हुआ, जो चोरी रोकती या जो टैक्स पीछे लगे हुए थे उनको ही हमने रिकवर किया। रेट ऑफ टैक्स नही बढ़ा।

श्री सम्पत सिंह: यह जो बीच में जवाब आ रहे है इनके बारे में मैं रिक्वैस्ट करुंगा कि वित्त मंत्री जी जवाब देते समय बता दें कि कितनी रिकवरी की है ओर बाकी का एरियर कहां से वापस लेंगे? यह तो आपका उदाहरण है कि जब असैट्स से फालतू लायबिलिटीज हो गई तो आज तो चलो ठीक है कि ये बडी बडी स्कीमे देंगे लेकिन कल को कैसे चलेगा? स्पीकर सर, अब मैं पावर पर बोलना चाहता हूं। राम बिलास भार्मा जी कहेंगे कि पावर की

तो डिमांड ही नहीं है। मे इनको बताना चाहूंगा कि करीब 210 करोड रुपये स्टेट गवर्नमेंट एच0 एस0 ई0 वी0 को देने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इससे माडे और इससे बुरे हाल बिजली बोर्ड के पहले कभी नहीं हुए। बार बार डींगे मारी गई डेटस भी दी गई और कहा गया कि बिजली के बारे में सारे के सारे सदस्य बिजली के उपर बोल रहे हे और ये सभी कह रहे है कि पिछली सरकारो ने बिजली के मामले मे कुछ नहीं किया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो कम मै करके गया था वही हुआ उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। सर, मै आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जनरे 1न के हैड में हरियाणा प्रदे 1 की 1975-76 के अंदर हमारी कैपेसिटी 55 मैगावाट थी और वह भी केवल फरीदाबद में थी, बाकी जगह जो प्लान्ट्स लगे है वह आफ्टर 1976 मे लगे है उसके बाद जो कैपेसिटी बनी, वह 876 मैगावाट थी। यह 55 से 876 मैगावाट की कैपेसिटी तक कौन लेकर आया? यह 17-18 गुनी बढ़ौतरी हुई। इसी तरह से अगर यूनिट्स के हिसाब से देखें तो उस समय 32 करोड यूनिट बिजली पैदा होती थी जबकि अब 336 करोड यूनिट बिजली ले रहे है तो यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि सारा कुछ उसी टाईम हुआ। दूसरी बात इसके बारे में मुझे यह कहनी है कि जब चौधरी बंसी लाल जी राज छोडकर गए थे, उस समय 7 लाख कंज्यूमर्ज थे जबकि आज 33लाख 90 हजार 245 कंज्यूमर्ज है। उनकी डिमांड को मीटआउट किसने किया? अगर आने वाली कोई भी सरकार यह सब काम न करती तो आगे कैसे कर देते? टयूबवैल्ज के

कनैव न यदि किसी सरकार के समय में घटे है तो इनकी सरकार के समय में घटे है। पिछले दो साल के अंदर ट्यूबवैलज कनैव न घटे है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय 3 लाख 75 हजार 934 ट्यूबवैलज के कनैव न हैं और अगले साल ये 3 लाख 66 हजार समथिंग रह गए और बाद में ये 3 लाख 64 हजार समथिंग रह गए। कितने ट्यूबवैलज घट गये, 12 हजार के करीब ट्यूबवैलज कनैव न घटे है। नये ट्यूबवैलज कनैव न देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1975-76 में 45 लाख यूनिट डेली बिजली उपलब्ध थी जबकि 1990-91 में 260 लाख यूनिट बिजली डेली उपलब्ध थी और अब एट वन डे 315 लाख यूनिट बिजली 25-5-90 को थी।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौधरी सम्पत सिंह जी ने ट्यूबवैलज कनैव न अंज के बारे में जिक्र किया है। इस बारे में तो आंकड़ों से ही पता चलेगा क्योंकि पिछले ढाई साल में जब से हमारी सरकार आई है, हमने नहरों के पानी को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसलिए जब किसान को नहरों से पानी मिलेगा। तो वह ट्यूबवैलज को क्यों चलायेगा?

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, दलाल साहब एक सवाल का जवाब दें कि 75 हजार ट्यूबवैलज कनैव न की एप्लीके न पैडिंग क्यों है? (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसमी न के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 1974-75 में ट्रांसफार्मज की संख्या 21 हजार थी और आज यह

एक लाख से भी ज्यादा है यानी पांच गुणा ट्रांसफार्मज कहां से आ गये हैं? पहले 46991 कि० मी० बिजली की लाईन थी जो आज 165827 कि० मी० हो गई तो यह डिवलपमेंट कैसे हुई? जहां तक सब-स्टे टाज की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, 1974-75 में 220 के० वी० के सब स्टे टान नहीं थे। सब स्टे टान तो 1975-76 के बाद में ही लगाये गये हैं। मुख्य मंत्री महोदय का यह कहना कि सारा कुछ उन्होंने ही किया है यह कोई जवाब नहीं है। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: आपके राज में बिजली की प्रोग्रेस कितनी और कहां कहां हुई, यह हमें बतायें?

श्री सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में मुख्य मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसको आप पढ़कर देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है? पानीपत का प्लांट नम्बर 1 और 2 1977 में हमारी सरकार ने ही भगुरु किया था। (विधन)

श्री सोमबीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये इस सदन को बताये कि जब 1987 में इनकी सरकार आई तो कितने टयूबवैल्ज के कनैक्टान पैडिंग थे और जब इनकी सरकार नहीं रही उस समय में कितने कनैक्टान पैडिंग थे?

श्री सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने चार साल के अंदर साठ हजार टयूबवैल्ज कनैक्टान दिये थे

जबकि वर्तमान सरकार ने कुल 12 हजार ट्यूबवैल्ज कनेक्शन ही दिये हैं जोकि टोटल में से भी कुछ घटे हैं इस पर इनका यह कहना कि पावर की उपलब्धि न होने के कारण या नहरों में पानी देने के कारण यह हुआ है, यह कोई जवाब नहीं है। फिर आज के दिन 75 हजार ट्यूबवैल्ज कनेक्शन की एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों पड़ी है? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने फरवरी के मीने में जो अपना वजैटरी एस्टिमेट्स दिया था उसमें स्टेट प्लान में जो बजट एस्टिमेट था, वह 325 करोड़ रुपये और एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स का 228 करोड़ रुपये का था। जाकि वर्तमान बजट 325 करोड़ रुपये जमा 180 करोड़ रुपये जो कुल 505 करोड़ रुपये हो जाता है। जब इस सरकार ने चार पांच महीनों में ही बजट को 50-60 करोड़ रुपये घाटा दिया तो बाकी को यह सरकार कैसे पूरा करेगी? मेरा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है। 1997-98 में बिजली बोर्ड का घाटा 313 करोड़ रुपये का था और अब इन्होंने 1998-99 में 485 करोड़ रुपये के घाटे का बजट एस्टिमेट्स दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोन लिया गया है, उसकी मूल पेमेंट तो 183 करोड़ रुपये सालाना होगी और इस पर ब्याज की राशि 290 करोड़ रुपये सालाना होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो मूलधन की राशि दे रहे हैं उससे ज्यादा तो इसका ब्याज ही देना पड़ेगा। इसलिए चाहे सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव में कमी हो या इनएफिशिएंसी हो, या बिजली बोर्ड में कमी हो, कारण कोई भी हो सकता है। There is

something wrong in the HSEB, दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने मेरा अनस्टार्ड क्वै चन तो पढ लिया होगा। अगर नही पढाप तो मै इनको पढकर सुना देता हूं। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले से ही चल रहा था, उसका जिक्र तो इन्होंने किया नही है।

श्री सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पहले कुछ नही चल रहा था। मै बता भी सकता हूं लेकिन इससे हाउस का समय बर्बाद होता है। उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल प्लांट की 110 मैगावाट की दोनो यूनिट्स 1977 मे चालू की गई थी और बाद में हमारी सरकार के समय मे ही बिजली की जनरे 1न भी की गई। उसके बाद पानीपत थर्मल प्लांट मे ही 220 मैगावाट की यूनिट हमारे समय में ही पूरी हुई है। (तोर एवं विधन)

श्री सतपाल सांगवान: उपाध्यक्ष महोदय, इस में काम किस ने करवाया है? ये कहते है कि 1977 मे इनकी सरकार ने इस यूनिट को चालू करवाया लेकिन इस की कमि गनिंग भी हुई होगी, टैस्टिंग भी हुई होगी, वह किसने करवाई?

श्री सम्पत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहता हूं कि पानीपत में 210 मैगावाट की 5वीं यूनिट रिकार्ड टाइम में तैयार हुई थी तथा उस वक्त हमारी सरकार ने मुलाजिमो को बोनस भी दिया था। इस युनिट का ओवर-टाईम कार्य करवा कर हमारी सरकार ने ही इसको तैयार करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय,

48 मैगावाट की हाईडल यूनिट भी हमारी सरकार के समय में ही पूरी हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले से ही जो बिजली जनरेट हो रही है, उन में से अधिकतर यूनिट्स तो हमारे समय की ही हैं। हां, चौधरी बंसी लाल जी ने जो बिजली जनरेट इन का कार्य अपने समय में किया है, वह 55 मैगावाट से ज्यादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानीपत की छठी यूनिट के बारे में बताना चाहता हूँ। The project for the 6th unit (210 MW) was cleared by the Ministry of Environment and the Planning Commission on 7-4-89 and 3-7-89, respectively. The estimated cost was Rs. 238.27 crores. चौधरी बंसी लाल जी ने बताया कि अगर उस वक्त यह प्रोजेक्ट बन जाता तो इतने करोड़ रुपये खर्च होते। The H.S.E.B had given a letter of intent for Boiler and T.G set to BHEL on 23-3-89 with an advance payment of Rs. 11.25 crores. Designing was completed and machinery worth Rs. 80 crores from BHEL was received in 1998 and it is lying idle. उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 5 अप्रैल को हमारी सरकार चली गई तथा 30 मार्च, 1991 तक इसमें कार्य चल रहा था। उसके बाद दुर्भाग्य से उसपर कार्यबंद हो गया। आज का भी पता नहीं कि वहां पर काम हो रहा है अथवा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो फाउंडेशन तैयार किया गया था, उसमें पिछले सालों में पानी भर गया था चाहे वह फलड की वजह से भरा हो या किसी और कारण से। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह नए प्रोजेक्ट्स का भी है और आनॉगोइंग वर्क्स का भी है। मंत्री जी अपने जवाब में बता देंगे कि क्या बजट में इस छठी यूनिट के लिए

पैसे का कोई प्रावधान किया गया है? मैं कहता हूँ कि इस के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है और ये कहते हैं कि इस को अगले साल तक तैयार कर देंगे। जहां तक उसके रैनोवे इन की बात है तो उसकी रैनोवे इन की जाए ताकि उसकी बिजली पैदा करने की कपैसिटी बढ़ जाए। उस समय इंजीनियर्स ने इसकी रैनोवे इन के लिए 100 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था, बाद में उसे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया और जब तक उसकी रैनोवे इन की जाएगी तब तक यह कोस्ट बढ़कर 400 करोड़ रुपये हो जाएगी। बिजली की जनरे इन पिछले 3 सालों में कितनी बढ़ी है, अगर इसका हिसाब ले लें तो इनका यही जवाब था कि 1996-97 में 2700 मिलियन यूनिट जनरेट हुईं एवं 1997-98 और 1998-99 में भी वही 2700 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट हुईं। इसका मतलब यह हुआ कि थर्मल पावर प्लांट में रैनोवे इन का कोई असर नहीं हुआ। इस पर ये जितना खर्च कर रहे हैं, वह सब बेकार कर रहे हैं। फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट के बारे में दलाल साहब भी कह रहे थे कि पहले कोई प्रोजेक्ट मंजूर भी होता है तो फरीदाबाद का थर्मल प्लांट लगाने के लिए हमारे समय में मंजूर हुआ था। यह जो प्रोजेक्ट है, यह है—

Initially the proposal for the gas based power plant of 300 M.W at Faridabad was sent by the H.S.E.B to Central Electricity Authority in November, 1990.

उसके बाद उसके बारे में यह डिजाइड किया गया कि उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी बल्कि उसको एन0 टी0 पी0

सी० बनाएगी। एन० टी० पी० सी० ने उसको बढ़ाकर 432 मैगावाट का कर दिया। उस वक्त जो प्राईम मिनिस्टर थे उन्होंने उसका पत्थर रखा था लेकिन डिप्टी स्पीकर सर, it is in open market. उससे हमें जो पावर मिलेगी वह मार्किट रेट पर मिलेगी। मार्किट रेट पर तो आज भी पावर एवेलेबल है। आज भी ले लो, उससे आपको कौन रोकता है। मार्किट रेट पर जो पावर मिलती है वह सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। फरीदाबाद का अपना प्लांट नहीं है। इसके अलावा यमुनानगर थर्मल प्लांट की बात करते हैं। यमुनानगर थर्मल प्लांट के लिए नवम्बर 1987 में सरकार ने लैंड एक्वायर करने के बारे में एक्वीजिशन लेने का डिसेाईड किया था और 1132 एकड लैंड एक्वायर की गई वह लैंड भी हमारी सरकार ने एक्वायर की थी। उस पर करोडों रुपये का कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया after that physical possession of land acquired by H.S.E.B was also handed over to NTPC on 1-2-1990. उसके बाद एन० टी० पी० सी० को दे दिया गया। एन० टी० पी० सी० को देने के बाद वे उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आने वाली सरकार काम न करे तो हम क्या कर सकते हैं? आज की सरकार कह रही है कि हम काम करेंगे लेकिन आज की सरकार कितना काम करेगी। पिछले साल इस सरकार ने 15 लाख रुपये खर्च किए, वह भी नहरों की गाद निकालने और माईनर्ज की सफाई आदि करने पर खर्च कर दिया होगा। इस बार उस प्रोजैक्ट पर 22 करोड रुपये खर्च कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, 210 मैगावाट का प्रोजैक्ट

हो, उस पर आप 22 करोड रुपये खर्च करने की बात करते हैं जबकि इस पर हजारों करोड रुपये खर्च होने हैं।

एक आवाज: वह 110 मैगावाट का प्रोजैक्ट है।

श्री सम्पत सिंह: पहले वह 210 मैगावाट का था, अब उसको 110 मैगावाट का कर दिया होगा। फिर भी उस पर हजारों करोडों रुपये खर्च होंगे। आप उसके पुराने एस्टीमेट्स को देखें, वह 1744 करोड रुपये का था। अगर यह सरकार हर साल उस पर 22 करोड रुपये खर्च करती रहे तो उसको कम्प्लीट होने में 100 साल लग जाएंगे। दलाल साहब ने हिसार थर्मल पावर प्लांट का जिक्र कर दिया कि हिसार में भी थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। जब बजट स्पीच में देखा तो पता लगा कि 1997-98 में उसके लिए 65 लाख रुपये रखे गये थे लेकिन 1998-99 में निल यानि उसके लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। वह थर्मल पावर प्लांट बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में कुछ पता नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो बिजली की नई जनरेटन आएगी वह कहां से आएगी क्योंकि इन्होंने बजट में नए प्रोजैक्ट के लिए कोई पैसा नहीं रखा है। यदि नए प्रोजैक्ट नहीं बनेंगे तो नई जनरेटन आने की कोई गुंजाइश नहीं है केवल मात्र आप 240 करोड रुपये का लोन लेकर राजी हो रहे हैं कि उससे काम चल जाएगा लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है।

बिजली राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी): यह मैं आपको बता दूँ कि यह जनरे इन कहां से आएगी। वह आप अगले डेढ़ साल में देख लेना तब बिजली फालतू होगी। बिजली कहां से आएगी, उस बारे में मुख्य मंत्री जी ने कल बताया था कि हम कहां-कहां से बिजली की जनरे इन करेंगे।

श्री सम्पत सिंह: सैनी साहब, अगर आपको याद नहीं है तो आप गोदारा साहब से अपना मैनीफैस्टो पूछ लें। मैं आपके मैनीफैस्टो की कापी कल नहीं लाया था लेकिन आज लेकर आया हूँ। उसमें साफ लिखा है कि विदिन 3 मन्थस बिजली की समस्या हल हो जाएगी। जैसे कोई जादू से हल हो जाएगी। हां, हल करने वाला आदमी तो सदन से चला गया।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सदन में बिजली की बात हो रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आप यह सम्पत सिंह जी की क्वालीफिके इन समझ लो या इनका यह हाउस के साथ मजाक या इनकी यह हाउस में झूठ बोलने की बात समझ लो। हर चीज को कह देते हैं कि यह पडी है। मैं कहता हूँ कि दिखा तो दे कि कहां पडी है।

श्री सम्पत सिंह: यह मैं आपको मार्किट कमैटी की दुकानों के आबंटन वाली बात के बारे में कापी देता हूँ, इसको आप पढ़कर सुना दो।

(इस समय माननीय सदस्य श्री सम्पत सिंह जी द्वारा माननीय गृह मंत्री को कुछ कागज दिए गए)

श्री उपाध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप यह बताएं कि आप कहते हैं कि तीन महीने के अन्दर बिजली देने की बात कही है वह किसने कही थी?

श्री सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं वह भी बता दूंगा।

श्री मनी राम गोदारा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने मुझे मंडियों के बारे में कागज दिया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि नव निर्मित मंडियों में आढतियों को उचित दामों पर दुकाने आबंटित की जाएंगी। (गोर)

श्री सम्पत सिंह: आब उन से नहीं उचित दामों पर आबंटित की जाएगी। उचित दाम आब उन थोड़े ही होता है। आप यह बता दें कि उचित दाम क्या होता है? (गोर)

श्री औम प्रकाश चौटाला: उचित दाम का क्या मतलब होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि उचित दाम का मतलब होता है जो प्राईस सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: उचित दाम का मतलब होता है रिजनेबल प्राईस। (गोर)

श्री औम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं या तो उचित दाम हो या आवक इन हो। ओपन आवक इन के विरोध में उचित दाम का मतलब सीधा है कि रिजर्व प्राईस पर जो चीज सरकार उचित दाम पर और जगहों पर देती है उसी प्रकार से उनको दी जाए। (गोर)

श्री अतर सिंह सैनी: रिजर्व प्राईस का मतलब होता है आरक्षित दाम। (गोर)

श्री अशोक कुमार: आप यह बता दें कि उचित दाम क्या होता है? (गोर)

श्री सम्पत सिंह: आप उचित दाम बताओ क्या होता है। (गोर)

श्री मनी राम गोदारा: उचित दाम का मतलब होता है रिजनेबल प्राईस ओर रिजर्व प्राईस का मतलब होता है आरक्षित दाम। आज के दिन अगर हम कहीं पर जमीन लेते हैं तो उसकी जो प्राईस आएगी वह रिजर्व प्राईस होगी ओर उसकी कीमत जो आज के दिन है जिस समय हम उसको अलाट करेंगे उस समय वही कीमत ली जाएगी। हो सकता है 10 साल के बाद कोई दुकान ले या न ले और कोई आढती वहां जाना चाहे या न जाना चाहे तो उस समय क्या पोजीशन होगी और उचित दाम क्या होगा।

श्री सम्पत सिंह: अगर आपने दुकाने आकान से देनी थी तो उसका आपने अपने मैनिफैस्टो में क्यों जिक्र किया (तोर) मैनिफैस्टो में उसका जिक्र करने से लाइसेंस को क्या फायदा हुआ? चलो यह कल का वाद विवाद था इसलिए वह कल पर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने तीन महीने नहीं दो महीने में 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी। मैंने तो एक महीना आपको फालतू बता दिया था इन्होंने जो यह बात अपने चुनाव मैनिफैस्टो में लिखी हुई है वही बात मैंने आपको कही है। इसके अन्दर लिखा हुआ है हरियाणा विकास पार्टी दो महीने के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि क्या लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है? इनकी सरकार बने दो साल हो गए हैं और डेढ साल के बाद ये 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात अब कर रहे हैं। ये चार साल बाद वह वायदा पूरा करने की बात करते हैं जो आज से दो अढाई साल पहले पूरा होना चाहिए था। मैं यह कागज गोदारा साहब को दे देता हूँ। यदि इस कागज में यह बात नहीं है तो मैं अपने भाब्द वापिस ले लूंगा। इन्होंने अपने मैनिफैस्टो में यह कहा था कि दो महीने के अन्दर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। दो महीने भी हो लिए, उसके बाद दो साल भी हो लिए और आज ये कह रहे हैं कि डेढ साल के बाद 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: डिप्टी स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी हमारे मैनिफैस्टो का जिक्र कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, कल मुख्य मंत्री जी ने बिजली से संबंधित सारी जानकारी सदन को दी थी। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार बिजली पैदा करने के लिए प्रयास कर रही है। ये हमारे घोशणा पत्र की बात करते हैं इनको घोशणा पत्र को याद करना चाहिए। (गोर)

Shri Sampat Singh: Sir, I want to know under what rule you are allowing him. he cannot speak now.

Mr. Deputy Speaker: I have permitted him to speak.

Shri Sampat Singh: But, Sir, under what Rule? kindly quote that Rule.

Mr. Deputy Speaker: I can allow him to speak. You cannot dictate me.

Shri Sampat Singh: This will be bailing out the Government. This will be shielding the Government.

12:00 बजे

श्री औम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेशों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनको कोई भी सदस्य बीच में प्वायंट आफ आर्डर का नाम लेकर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और प्वायंट आफ आर्डर करने की बजाए दूसरी बातें कहने लग जाते हैं ये ठीक प्वायंट आफ आर्डर नहीं करते। (गोर)

श्री सतपाल सिंह सांगवान: उपाध्यक्ष महोदय, ये सीनियर मोस्ट मैम्बर है। इनको इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए। (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: आप सभी मर्यादा में रह कर अपनी बात कहें। दलाल साहब एक मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं, इनको कह लेने दें। इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री सम्पत सिंह: इसका मतलब क्या है कि ये तो सारी मर्यादाएं तोड़ते रहे लेकिन we do not expect such a thing from you, Sir.

श्री कर्ण सिंह दलाल: इनके जिने भी वरिष्ठ नेता है, सदस्य है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि क्या ये कुछ भी कहते रहेंगे? इन्होंने बोलते हुए बडी मुस्तैदी के साथ चुनावी घोशणा पत्र का जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि 1987 में भी इनकी पार्टी ने चुनावी घोशणा पत्र तैयार किया था। उस समय दुनिया भर के असत्य वायदे करके आये थे।

श्री औम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ठीक कहा था कि यह हमारा गठजोड़ नहीं है, जुगाड है।

श्री मनी राम गोदारा: मैंने ऐस जुगाड वाली बात नहीं कहीं मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर कोई बात नहीं हुई तो इनको कैसे पता चला क्योंकि ये वहां पर थे नहीं? इन्होंने तो

अपने घोशणा पत्र में नोट छापने वाली मीन का जुगाड करने की बात कही थी क्या अब ये वह मीन लायेंगे? ये जुगाड वाला भाब्द कहां से लाए, ये जानते होंगे। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, please conclude within a minute. आपको बोलते हुए 35 मिनट हो गए हैं।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे बोलते समय टोटल इनट्रॉप्शन रही है।

श्री मनी राम गोदारा: फतेहाबाद के इलैक्ट्रॉनिक्स के दौरान मैंने एक बात कही थी वह सही है कि सम्पत सिंह जी तो पढा लिखा है लेकिन बाकी तो सारे नौवीं फेल है। यह बात सही है। (विधन)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज मुझे पढे लिखे का सर्टिफिकेट दिया है, कल दूसरे किसी मेरे और साथी को देंगे, धीरे धीरे हम सबको दे देंगे। (विधन एवं भाोर) I am speaking on facts. There is nothing political.

Mr. Speaker: You are requested to conclude within two minutes.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मैनीफैस्टो का जिक्र नहीं करूंगा। इसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। इसके बारे में सरकार ने बहुत कुछ कहां अध्यक्ष महोदय,

सरकार ने कहा कि हमने 1997-98 में 148 करोड़ खर्च कर दिये और 1998-99 में 458 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे। अध्यक्ष महोदय लाईन लोसिज कितने है। 1995-96 में 28% थे, 1996-97 में सरकार आते ही 29½% हो गए, 1997-98 में खर्चा बढ़ाने से लाईन लोसिज 32.15 प्रति त हो गए और 1998-99 में यह 31% हो गए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, please sit down. Now, I would request another member. Shri Satvinder Singh Rana to speak. (Interruptions)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पावर पर गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहा हूं इसलिए मेरी बात इनको पिंच हो रही होगी। उसके लिए आप इनको कहे कि यह सरकार बेल आउट हो जायेगी। They are being bailed out.

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायें।

श्री मनी राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, बिजली आदि के बारे में जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, तो ये लोग अपनी सरकार के वक्त में कहा गये थे, उस समय इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, जब 1996 में हमारी सरकार आई, उस समय बिजली की बहुत खराब हालत थी। हमारे मुख्य मंत्री जी की डेढ़ साल की मेहनत केबाद हरियाणा में बिजली की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले डेढ़ साल में हम हरियाणा प्रदेश के गांव गांव में पूरी बिजली दे देंगे। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, यदि चौ० सम्पत सिंह जी अपने साथ साथ जो विपद्वा के दूसरे भाई है, उनका जिक्र भी करते, उनके कारनामों का जिक्र करते तो ज्यादा अच्छा होता, वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? (विधन एवं भाोर)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि क्या यह सिस्टम ठीक हुआ तो इन्होंने कहा, हां हो गया। अध्यक्ष महोदय यह सिस्टम इतना ठीक हुआ है कि ठीक होने के बाद 28% प्रतिगत लाईन लोसिज की बजाय 29½% लाई लोसिज दे रहा है और 31 मार्च, 1998 तक ये लाईन लोसिज 32.15% हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कुछ भी पढ़ते हैं, मैं 31 मार्च 1998 इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत करके इसको पढ़ा है, देखा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्स्टाल्ड कैपेसिटी आफ ट्यूबवैल्ज की बात है तो 1990-91 में यह 35% थी और आज यह कैपेसिटी 29% रह गई है। स्पीकर साहब, ओनली 29% और ये दे रहे हैं 8 घण्टे। 8 घण्टे के लिए उसे 365 दिन के लिए बुक किया गया। एग्रीकल्चर सैक्टर में 365 दिन में से एक तिहाई तो किसान को बिजली की आवश्यकता नहीं होती और बाकी के दिनों में जब उसको जरूरत होती है तो किसान को ये बिजली देते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय 43% का वन थर्ड होता है 14 और यही भी बिजली किसानों को मिलती नहीं है। (विधन)

Mr. Speaker: I would request Shri Sampat Singh to kindly take his seat.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी बातो से गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है इसलिए आप मुझे बोलने के लिए टाईम नही देना चाहते है, यह हमारे साथ इनजस्टिस है।

श्री अध्यक्ष: यह आपकी अपनी प्रिडिक्शन है, मैं इस बारे में आपको कुछ नही कह सकता। आप खुद देखिये कि आपने कब बोलना शुरू किया था।

श्री सम्पत सिंह: मैं एकदम रैलेवैन्ट बोल रहा हूँ इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि मुझे थोडा और समय दीजिए ताकि मैं कन्कल्यूड कर सकूँ।

श्री अध्यक्ष: अगर अपनी बात को खत्म नही करना चाहते तो वह आपकी अपनी मर्जी है मैं फोर्स नही कर सकता। आप एक मिनट में कन्कल्यूड कीजिए।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं पावर के उपर अपनी बात कन्कल्यूड कर रहा था। अगर टोटल एक्चुअल लोस को देखा जाए तो यह लोस 60% तक बन जाता है इसलिए यह मांग है कि बिजली बोर्ड की वर्किंग की हाईकोर्ट के सिकी सिटिंग जज से इन्कवायरी करवाई जाए। सबसिडी के बारे में भी इन्होंने कहा कि 700 करोड रुपये की सबसिडी बिजली पर दे रहे है। इस तरह की सबसिडी आपके अपने बजट में 150 करोड रुपया कै 1 और 100

करोड रुपया की एडजस्टमेंट की बात है बजट मे असत्य आंकडे तो कम से कम नही होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 250 करोड मे एडजस्टमेंट का कोई लाजिक नही है। 700 करोड रुपये मे से 400 या 300 करोड रुपया सबसिडी का होगा और बाकी एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि सबसिडी सारी की सारी थैफ्ट हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अब तो गवर्नमेंट के पास एक्सार्इज रैवेन्यू काफी आ गया है और 200 करोड रुपये एग्रीकल्चर ट्यूबवैलज से भी आने है इसलिए क्यों न पंजाब पैटर्न पर इसको माफ कर दिया जाए? 775 करोड के करीब रैवेन्यू सरकार के पास आना है क्यों न उसमें 200 करोड रुपये माफ कर दिए जाएं?

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप बैठ जाएं।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा (राजौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हू। मैं सबसे पहले डिमांड नं० 3 जो गृह और ला एण्ड आर्डर से जुडी हुई है से अपनी बात भुरु करता हू। उसके बाद मैं डिमांड नं० 8,9,10,12, और 15पर भी अपने विचार रखूंगा। सरकार मेरी बातो पर ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होने सरकार मे आने से पहले बहुत ही लम्बे चौडे वायदे किए थे। जब से यह सरकार बनी है तब से हरियाणा का नौजवान भटक रहा है और लूट खसोट कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वायदा किया था कि हम भाराब बंद करेंगे जिसका हम सबने समर्थन किया था। इन्होने

हरियाणा में भाराब बंद की लेकिन पता नहीं किन कारणों से दोबारा हरियाणा में भाराब खोल दी। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली के अंदर कोई लूट खसोट होती है तो कहा जाता है कि हरियाणा के नौजवान यह सब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कोई सरकार आती है और उसका मैनीफैस्टो होता है उसमें ये नौजवानों को कहते हैं कि हम तुम्हें गैस एजेन्सी देंगे, पेट्रोल पम्पस देंगे और बसों के परमिट देंगे। इसके साथ साथ उनको नौकरियां भी देने का वायदा किया जाता है। जब हमारा नौजवान इन सब चीजों से हताश हो जाता है और उनके मां बाप उनको कहीं पर नौकरी न करने की वजह से ताने मारते हैं तो वह काईम में इन्वाल्ड हो जाता है। मां-बाप आज पता नहीं किस तरह से अपना पेट काट कर बच्चों को पढाई करवाते हैं और इस एच० बी० पी० और बी० जे० पी० की सरकार ने आते ही सबसे पहले नौकरियों पर बैन लगाया और नौजवानों को नौकरी से महरूम होना पड़ा। कल मुख्यमंत्री जी ने एक लिस्ट पढ़ी उसमें ढिढाना गांव का नाम आया और इन्होंने कहा कि जो चार मुलजिम पकड़े गए वे फलां पार्टी के थे। ये क्या हो रहा है? आज हम जो नारे देकर नौजवानों को विवास देते हैं कि हम आपको पेट्रोल पम्प देंगे, गैस एजेन्सियां देंगे और बसों के परमिट देंगे लेकिन वे सब तो मंत्री ही ले जाते हैं, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। आज थाने में कोई अपनी दरखास्त देने जाता है तो मुन्शी उसको कहता है कि कुछ खर्चा पानी दे दो और जब वह दे देता है तो दूसरी पार्टी को पकड़ कर लाता है और उसको भी यही कहा जाता है कि कुछ खर्चा पानी दे

दे और तू भी दरखास्त दे दे। आज हरियाण में यह आम प्रथा पड़ गई है। आज प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि पूछो मत। आज कोई भी गलत काम करता है तो उसको राजनैतिक आदमी ही भाह देते हैं। अध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में किटाना और नगुरा दो गांव हैं। वहां के कुछ नौजवान ऐसी हरकतें करते थे कि जब पहले भाराब बंद थी तो वे नौजवान भाराब की सम्गलिंग करते थे और जब भाराब खुल गई है तो लूट खसौट करते हैं। वे नौकरी न मिल पाने के कारण अपने परिवार के तानों से तंग आकर ऐसा काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में राजौन्द में तीन चार दिन के अंदर ही पांच छः डकैतियां हुई हैं। अभी बी दिन पहले राजौन्द के अंदर ही एक बी० जे० पी० के कार्यकर्ता के घर पर चोरी हुई है। पता नहीं चोरी हुई भी है या नहीं लेकिन वह राजस्थान में गया और वहां से लौटने के बाद पुलिस वालों को 1100 रुपये देकर कहा कि फलां गांव के औम नाम के आदमी ने चोरी की है। पुलिस वालों ने जब पूछा कि औम कौन है तो उसने किसी गरीब आदमी का नाम लेकर कहा कि यही औम है। इसके बाद पुलिसवाले उसको ले आए और उसकी इतनी पिटाई की कि वह गरीब बीस पच्चीस दिन से अपने बिस्तर पर से उठ नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, उसको पुलिस वालों ने मुसली लगायी। इससे ज्यादा भार्म की बात क्या हो सकती है? इस वजह से वह गरीब आदमी अपने घर में ही पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य भले ही इस बात को मजाक में ले लेकिन ऐसी बातें वहां हुई हैं ये तथ्य सही हैं। आज इन चीजों के देखते हुए

बिगडती हुई ला एण्ड आर्डर की स्थिती को देखते हुए हरियाणा की स्थिती ऐसी हो गई कि इसने बिहार और यु० पी० को भी पिछे छोड दिया। पहले तो हम बिहार और यू० पी० की हि मिसाल देते थे परन्तु आज हरियाणा के अंदर भी ऐसी ही स्थिती को देखते हुए इसने बिहार और यू० पी० को भी पीछे छोड दिया। लेकिन इसको बिगाडने वाले हम नेता लोग ही है क्याकि हम उनको तरह तरह के नारे तो दे देते है लेकिन उन पर अमल नही होता। अध्यक्ष महोदय, अभी पुलिस की भर्ती हुई है जिसके बारे मे यहां पर कई बार बात आयी है कि डेढ लाख रुपये देकर पुलिस की नौकरी मिलेगी। दो तारीख से यह पुलिस की भर्ती भुरु हुई है और भायद यह तीस तारीख तक चलेगी। लाखो नौजवानो ने इसमें भर्ती होने के लिए फार्म भरे हुए है उनकी इस भर्ती के लिए दौड वगैरह भी हुई है।

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा): स्पीकर साहब, पहले ये भायद हाउस मे नही होंगे इसलिए इनको इस बारे में पता नही है। लेकिन मैने लीडर आफ दी अपोजी इन के एक सवाल के जवाब मे एक बात बडी साफ और क्लीयर कही थी कि हमारी यह पुलिस की भर्ती मैरिट के बेसिज पर हो रही है। मैने उस समय सारे हाउस को यकीन दिलाया था कि आगे भी यह भर्ती मैरिट के बेसिज पर होगी। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर हम यह साबित कर दे या सबूत दे दे कि इसमे गडबड हुई है तो हमने कहा था कि आपका स्वागत है आप सबूत ले आए। लेकिन वैसे ही

खडे होकर कहना ठीक बात नहीं है। अभी तो भर्ती हुई नहीं है। जिस दिन कोई ऐफिडैविट लेकर इस बारे में हमारे पास केस लाएगा या कोई सबूत उसके पास होगा तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। आप कहते हैं कि हमने सारे लोगों को बिगडा दिया। लेकिन इनको हमने नहीं बिगडा बल्कि आपकी पार्टी के राज में ही ये लोग बिगडे। उस समय नौकरियां कही पर 60 हजार रुपये में, कही पर 70 हजार रुपए में बिकी। खैर मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप हमारे सामने इस बारे में कोई केस तो लाइए, हम उस पर कार्यवाही करेंगे लेकिन जो आप लोगों ने नौजवानों को गलत आदत डाल दी है तो आप यह न समझे कि सबकी यही आदत है।

श्री सूरजमल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि मैरिट के हिसाब से पुलिस में बच्चों की भर्ती की जाएगी। मैरिट तो इन लोगों के हाथ में होगी क्योंकि जो बीस नम्बर का बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी मैरिट कौन देखेगा? फिर मैरिट कहां रह जाएगी?

श्री सतविन्द्र सिंह राणा: स्पीकर साहब, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि डेढ़ लाख रुपये ले लिए। मैं यह कह रहा हूं कि जब हम मैरिट की बात करते हैं तो मैरिट उस दिन कही जाएगी जब रेस, कुद दौड़ कराने के बाद मैरिट के आधार पर उसी दिन रिजल्ट निकाल दे लेकिन यह जो

15 नंबर इंटरव्यू के लिए लिखे है इनकी मर्जी है कि कैंडीडेट से जो मर्जी पूछे।

श्री मनी राम गोदारा: मेरे ख्याल से सारे मैम्बर्ज को बताना होगी कि 1995 मे जो भर्ती हुई उस को जब हाई कोर्ट ने रिजैक्ट किया तब हाई कोर्ट ने गाईडलाइन दी कि इनको फोलो करते हेए आगे भर्ती होगी। आप सभी मैम्बर्ज को और जितने भी आदमी सर्विस मे है, उनको यह पता होगी कि Interview is also a part of the examination for merit. (विधन) यह पहल दफा इसलिए हो रहा है कि हाईकोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन और गाईडलाईन्स दी हुई है उन्ही के आधार पर हम भर्ती कर रहे है। (गोर एवं विधन) आप ये बताइए कि कौन सी जगह इन्टरव्यू नही होते?

कैप्टन अजय सिंह यादव: आर्मी में कांस्टेबल का इंटरव्यू नही होता। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सतविन्द्र सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे ये बार बार टोक रहे है। मेरा समय तो इसी मे समाप्त हो रहा है अभी तो मैं अपने हलके के बारे में कुछ भी नही बोला हू। मैं गोदारा साहब से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मैरिट की बात कह रहे है, इंटरव्यू की बात कह रहे है तो जिस जिले मे इंटरव्यू हो लिए है उनकी लिस्ट क्यों नही लगी, पहले ये बताइये, जींद जिले मे इंटरव्यू खत्म हो लिए लेकिन वहां लिस्ट अभी तक नही लगी है।

श्री मनी राम गोदारा: स्पीकर साहब, मैंने बताया है कि इंटरव्यू हो गई, लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने के बाद डाक्टरी मुआयना होगा और उसके पचात् उनके चरित्र की वैरीफिके ान होगी उसके बाद अनाउंस होगी। आपके सामने अनाउंस होगा। आप आना।

श्री अध्यक्ष: सतविन्द्र सिंह जी, आप दो मिनट में कन्कल्यूड करिए।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने तो अपने हल्के की बात भी नहीं कहीं (विघ्न)

स्थानीय स्व ासन मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, सतविन्द्र सिंह जी को अपने भाब्द वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस की भर्ती में एक लाख डेढ लाख तक लिया जा रहा है या लिया गया है, अब ये कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है मेरा मतलब यह है कि लिस्ट नहीं लगाई गई। अध्यक्ष महोदय, ये इस बात की क्लेरिफिके ान दें।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, भर्ती का जो लम्बा प्रौसैस है उसको कम किया जाये क्योंकि नौजवान भाहर में भर्ती होने के लिए जाता है तो चार आदमी उसके साथ जाते हैं कि हमारा लडका भर्ती होगा और इस तरह से रोजना पांच सौ रुपये तक उनके खर्च हो जाते हैं। इस तरह से जो भर्ती हुई उस

पर लोगो ने हजारो रुपया खर्च कर दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, भर्ती की बात मैं नहीं करूंगा। (विघ्न)

Mr. Speaker: I would request you to please conclude within 2 minutes.

श्री सतविन्द्र सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नं० 8 मे भवन और सडको की बात कही हुई है। मेरे हल्के मे सडको का इतना बुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकता। मैं मंत्री जी का भुकगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे गांव की सडक को इतना बढिया और इतना उंचा बना दिया कि जब बारि । हुई तो गांव के सारे धर पानी में डूब गए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उस सडक के साथ साथ एक नाला भी बनाया जाये ताकि जो गांव का पानी है उसकी निकासी हो सके। कल माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इस सरकार ने कई जगह भवन बनाये है लेकिन मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे एरिया मे तो एक ईट भी नहीं लगी है। हमारा बस स्टैण्ड जो अढाई साल पहले बनना भुरु हुआ था उसकी रफतार कछुए से भी धिमी चल रही हैं मैं मंत्री जी से अनुरोध करूं कि उस बस स्टैण्ड की स्पीड से बनाया जाए। इसके अलावा मैं लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे हलके मे एक विश्राम गृह बनाया जाये ताकि माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय आप कभी कभी हमारे हलके में द नि दे सकेंगे। जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग की बात है 1976 मे हमारे गांव मे नहर के पानी की एक डिग्गी लगाई गई थी

आज उसका इतना बुरा हाल है कि हमारे गांव के लडके पानी को ढो ढो कर गंजे हो गए हैं। जिसके कारण उनका कोई रि ता भी नहीं करता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मे जो डिस्पेंसरी है उसमे चार डाक्टरों की पोस्ट सैंक ांड है लेकिन उसमें से एक भी वहां पर पोस्टिड नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक डाक्टर तो वहा पर लगाया जाये। जहां तक सिंचाई की बात है हमारा सारा इलाका टेल पर पडता है एक दो जगह को छोडकर किसी भी नहर की टेल पर पानी नहीं पहुंचता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी टेलो पर पानी पहुंचाया जाये। पहले नहरो में पानी 15 दिन तक चलता था लेकिन अब सात दिन तक चलता है। जहां तक सहकारिता का सवाल है हमारे इलाके मे किसानों को कोओप्रोटिव बैंको से ऋण नहीं मिल रहा है। अगर उनको ऋण मिलता भी है तो या तो वह किसी की सिफारि ा के आधार पर या पर्ची सिस्टम के आधार पर मिलता है। जब हम उन अधिकारियों को मिलते है तो वे कहते है कि आप तो अपोजी ान के एम0 एल0 ए0 है। ये भी कहते है कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम क्या करे? (विघ्न)अध्यक्ष महोदय, अंत मे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किथाना गांव के अंदर हम ने एक को कोओप्रेटिव बैंक खोलने की मांग कर रखी है, मेरी प्रार्थना है कि वहां पर को-ओप्रेटिव बैंक खुलवाया जाए। इसके साथ ही जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं डिमांड न 3, 8 10, 15, 23 वह 25 से संबंधित कुछ बातें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य देश के सभी राज्यों में एक भांति प्रिय राज्य समझा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की आलोचना करने नहीं जा रहा हूँ। लगभग पिछले 26 महीनों में, जब से यह भाजपा-हविषा गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, हरियाणा के जन मानस के अंदर असुरक्षा की भावना पनपी है और बड़ी तेजी से अपराधों का ग्राफ प्रदेश के अंदर बढ़ा है। यह एक चिंतनीय विषय है। इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य यूपी और पंजाब में अपराध होते थे, उसी प्रकार से हरियाणा राज्य में अब अपराध होने लगे हैं। परसों भायद गृह मंत्री जी सदन में पिछले 10 महीनों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे जिसमें यह वर्णन था कि इतने बलात्कार हुए, इतने अपहरण के केस हुए तथा इतने कार वगैरह छिनने के केस हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इन आपराधिक घटनाओं के कारण क्या है और राज्य में इन समस्याओं का हल क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा राज्य में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। हर गांव के अंदर सैंकड़ों बेरोजगार युवा घुम रहे हैं। इसलिए आज एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है, जिसके तहत सभी युवकों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बगैर नौकरियां मिलें

और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। आज मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। कल दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाए जाते थे। इसलिए हम सब को मिलकर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा व पार्टी से उपर उठकर एक ऐसी नीति तैयार करनी चाहिए जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को नौकरिया मिले, चाहे वह पुलिस भर्ती हो, चाहे चपडासी की भर्ती, अथवा किसी अधिकारी की भर्ती। योग्य उम्मीदवार को बिना सिफारिश व पैसे दिए अपना उचित स्थान मिलना चाहिए। सदन में पुलिस भर्ती का जिक्र भी किया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि योग्य उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। कई नौजवान 6 फुट से भी ज्यादा कद वाले हैं। वे भागदौड़ में सबसे आगे रहे हैं लेकिन उनको यथायोग्य स्थान नहीं मिल पाया है। जब यह भाजपा-हविषा गठबंधन की सरकार बनी थी तो वास्तव में ही मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यह सरकार पार्टी के मतभेदों से उपर उठकर कार्य करेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि पुलिस भर्ती में सरकार ने सभी सत्ता पक्षों के विधायकों, मंत्रियों को 15-15 सीटें अलॉट की हैं। हो सकता है, दूसरे भाई इस बात से इनकार करेंगे, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने की कृपा करें। मेरे हल्के के छीमा गांव का एक नरेश नाम का लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने फिजीकल टैस्ट यानि भागदौड़ का टैस्ट पास कर लिया उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो वहां पर जो अधिकारी इंटरव्यू ले रहा था, उस ने मुझसे पूछा कि आप को गाना आता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस भर्ती

के लिए भी गाना गाने की आव यकता पडेगी? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी तो यही गुजारि ा है कि सब लोगो को रोजगार देने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बात ठीक है कि कोई भी सरकार सब को नौकरी नही दे सकती है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा: आप बताएं कि हमने इंटरव्यू के लिए कोई प्रावधान है या नही।

राव नरेन्द्र सिंह: आदरणीय गृह मंत्री इस सदन के सबसे वरिष्ठ आदमी है। मै मानता हू कि नौकरियो मे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रावधान है परन्तु पुलिस विभाग मे गाना गाने का क्या संबंध है?

श्रीमती कमला वर्मा: संगीत जानना भी एक बहुत बडी कला है न कि कोई बुराई।

राव नरेन्द्र सिंह: मै सरकार से कहना चाहूंगा कि सभी भाईयो को नौकरी नही मिल सकती। न आपकी सरकार दे सकती है, न हमारी सरकार दे सकती है और न ही कोई और सरकार दे सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दें।

श्री मनी राम गोदारा: इस पुलिस भर्ती में हरियाणा के अंदर 87000 नौजवानो ने हिस्सा लिया। इनमे से 37000 नौजवान फिजीकल फिट निकले। कोई भी बोर्ड चाहे एस एस एस बोर्ड हो, पब्लिक सर्विस कमी ान हो या कोई और बोर्ड हो, वह अपने

लैवल पर इंटर्व्यू लेते है और अपना काम करते है। हम इसमें अपनी तरफ से नही देखते। (गोर)

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको माध्यम से गृह मंत्री जी जो यहां बैठे है से कहना चाहूंगा कि मेरे मुताबिक बी सीज कैटेगरी के लिए 11 प्रति त आरक्षण है लेकिन जहां तक मेरे नालेज मे आया है महेन्द्रगढ जिले मे यादव, सैनी और गुर्जर इस पुलिस भर्ती मे केवल 7 ही लिए गए। जबकि यादव, सैनी और गुर्जर कैंडीडेटस से फार्म भरवाते समय आरक्षित कैंडीडेट लिखवाया गया।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन नाथ): इनके नोटिस मे भायद यह बात नही है कि 1992 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो बीस ीज और एस सीज कैंडीडेटस मैरिट पर आ जाएंगे, वे जनरल कैटेगरी मे समझे जाएंगे वे रिजर्व कोर्ट मे नही समझे जाएंगे। आपके एरिया मे अहीर या गुर्जर ज्यादा है और वे मैरिट पर आ गए होंगे। (गोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की हिदायतो का वायले तन किया जा रहा है उसको ठीक करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: राव नरेन्द्र जी,आप 5 मिनट मे कनकल्यूड करें।

राव नरेन्द्र सिंह: मुझे छ दिन के अन्दर पहली बार बोलने का समय मिला है। इसलिए मुझे पूरा समय दिया जाए। सबको नौकरिया तो नहीं मिल सकती इसलिए जिन जिलों में सरकारी रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं जैसे महेन्द्रगढ़ जिले में ऐसे जिलों में जो रुरल बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। दादरी भी उसमें शामिल कर लिया जाए। स्पीकर साहब, मेरी नालेज में एक बात आई थी। कल हमारा नारनौल तमाम बंद रहा क्योंकि वहां पर पिछले एक हफ्ते के अंदर तीन घटनाएं हो गई हैं जिनमें से दो आदमी भगवान को प्यार हो गए हैं। उनका मर्डर हो चुका है और एक आदमी सीरियस हालत में है। इसके अलावा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हिसार में एक फाइनेंस कंपनी के मालिक को मार दिया गया उसकी अखबारों में फोटो भी आई थी उसको अपने आफिस में कुर्सी पर बैठे हुए गोली मार दी गई। स्पीकर साहब, हमारे गृह मंत्री जी बहुत तगड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने होम डिपार्टमेंट पर तगड़ी गिरफ्त करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन विभाग के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा राज्य परिवहन की बसे अदर स्टेटस राजस्थान और पंजाब के अंदर जाती थी तो लोग देखा करते थे कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसे देश के अन्दर प्रथम स्थान पर चल रही है आज वही स्थान

किन कारणों से नीचे जा रहा है। अब सरकार की तरफ से सौ किलोमीटर तक के रूट परमिट देने की स्कीम चल रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि 100 किलोमीटर तक के जो रूट परमिट दिये जाएंगे उनमें विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को ही वे रूट परमिट नहीं मिलने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम देखा करते थे कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में अवैध व्हीकल्ज कमाण्डर जीपे चला करती थी वह 50-50 सवारियां ले कर चलती थी। उनमें 50-50 सवारियां बैठी होती थी और उनके एक्सीडेंट्स में हजारों नौजवान मर चुके हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर भी अवैध व्हीकल्ज चलने की बीमारी पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। जो प्रभाव गाली लोग अवैध व्हीकल्ज चला रहे हैं उन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जिन सड़कों की पिछले दो साल से बुरी हालत है, चाहे वह बारिश की वजह से है और चाहे बाढ़ के कारण है, पिछले दो साल में जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाईवे जो धारुहेडा से खेजडी की ओर से अदर स्टेट को जाता है, बजट के अन्दर उसको चौड़ा करने का प्रावधान है, यह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि नारनौल का बाई पास भी जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एस वाई एल नहर हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है। उसके बारे में यह जिक्र आया कि उसको कम्प्लीट करवाने के बारे में

केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मैं कहूंगा कि हलोदरा का भी केन्द्रीय सरकार को समर्थन प्राप्त है इसलिए इनकी तरफ से भी उस नहर को बनवाने के बारे में पंजाब सरकार पर दबाव डलवाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एस वाई एल नहर पूरी होने से दक्षिणी हरियाणा और जिला महेन्द्रगढ़ के भुशुक खेतों को पानी मिलेगा। अब मैं बिजली के विषय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। स्पीकर साहब, 31 मार्च 1990 के बाद ट्यूबवैल्ज के नए बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री महाजन जी सदन में बैठे हैं मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकारी हस्पतालों की व्यवस्था बहुत खराब है अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह सरकारी अस्पताल में जाने की बजाय प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है क्योंकि अगर किसी हस्पताल में कोई अच्छा डाक्टर है तो सरकार उसका तबादला कर देती है। किसी सरकारी अस्पताल में कोई इक्विपमेंट नहीं है। स्पीकर साहब, मेरे हल्के के नसीबपुर गांव में एक भाहीदी स्मारक बना हुआ है। वहां पर 16 नवम्बर को भाहीदी दिवस मनाया गया था उसमें प्रो० राम बिलास भार्मा जी भी गए थे। इन्होंने उसके लिए एक लाख रुपये ग्रांट देने की घोषणा की थी। सीवरेज की वजह से वहां पर गंदगी बहुत हो चुकी है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उस

समय के स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व राव तुला राम, राव मंगल सिंह और कृष्ण गोपाल ने किया। उस दिन वहां पर लोगो ने उसमे बढ चढ कर भाग लिया और वहां पर पार्टी लाइन से उपर उठ कर भाहीदी दिवस मनाया गया उसमे मै भी भामिल हुआ था लेकिन ये माननीय सदस्य उस दिन वहां पर नही आए।

राव नरेन्द्र सिंह: मै माफी चाहूंगा कि किसी कारण से उस दिन मै नही आ सका।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आप जल्दी कन्कलूड करें।

राव नरेन्द्र सिंह: ठीक है जी।

श्री सूरज मल (राइ): अध्यक्ष महोदय आपने बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज पता चला कि सारी डिमांडज आज ही पास हो रही है इसलिए हम भी अपनी बात कह देते है। मै आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आज भेदभाव बरता जा रहा है। जितने भी अपोजी उन के हल्के है उन सब के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। मेरा हल्का और कैलाना हल्का साथ साथ है। वहां पर पानी की सतह भी एक ही तरह की है। कैलाना हल्के मे तो सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू कर दी जबकि मेरे हल्के राई में सरकार ने यह प्रणाली लागू नही की। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार हमारे साथ भेदभाव बरत रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में सड़को की रिपेयर नहीं हो रही कागो में हो रही हो तो अलग बात है लेकिन असल में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। बे एक मंत्री जी मेरे साथ चल कर देख लें, यदि यह बात सही नहीं होगी तो मैं कसूरवार हूँगा। मेरे हलके में किसी भी सड़क का ऐस्टीमेट पास नहीं हुआ। जब ऐस्टीमेट ही पास नहीं हुआ तो सड़के कहां से बनेगी? अफसरों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि अपोजी इन के हल्को के ऐस्टीमेट पास नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में रेत की खाने हैं। वहाँ पर जगह जगह पर खाने खुदी हुई हैं। खान माफिया वहाँ पर खडा हो गया है। वहाँ पर इसी कारण झुण्डपुर में पिछले दिनों कत्ल भी हुआ है। वहाँ पर मनमजी के हिसाब से खुदाई हो रही है। उन पर सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। एक खान चोदने वाला किसी का एक किल्ला खान खोदने के लिए लेता है तो उसको वह पचास पचास फुट की गहराई तक चोद डालता है। इसका नुकसान यह होता है कि साथ वाला मालिक है जिसका साथ लगता है वह उसको देने पर मजबूर हो जाता है। वहाँ पर रास्ते भी नहीं छोड़े गए। हर जगह पर खाने खोद दी गई हैं। वहाँ पर खान माफिया के लोग खानों पर बंदुक लेकर बैठे रहते हैं जिस कारण कोई दूसरा आदमी सेफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भाई को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह वहाँ जाकर देख सकता है। आज मेरे हल्के में रेत की खानों का

बिजनैस सबसे बड़ा बिजनैस है, इससे लोग बड़े परे जान है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पार्टी बाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ अगर आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, बताना मेरा फर्ज बनता है क्योंकि वह मेरा हल्का है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं पंचायती जमीन की करूंगा। मुरथल, खेवडा और नांगल आदि गावों में पंचायत की जमीन बहुत ज्यादा है। बी० डी० ओ० और पंचायत आफिसर पंचायत की जमीन को पट्टे पर देते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन गावों में पंचायत की जमीन को पट्टे पर देते हैं, जिसको चाहा उसको देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव मुरथल में अभी 6-7 महीने पहले 98 एकड़ भूमि 600 रुपये, 700 रुपये के हिसाब से पट्टे पर दी गई जबकि उसका रेट इससे कहीं ज्यादा है। इस बारे में मैंने एक पत्र डी सी साहब को लिखा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, इस तरह से अफसरों की मनमर्जी चलती रहेगी तो इन गावों की पंचायतें बर्बाद हो जाएंगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हम हरियाणा को बिजली ठीक तरह से दे रहे हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके में मुक्ति कल से दो दिन में 4-5 घंटे ही आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बिजली की कमी है इसलिए आप ज्यादा बिजली किसानों को नहीं दे सकते लेकिन जो 4-5 घंटे आप बिजली देते हैं वह तो लगातार दे ताकि किसानों की एक आध एकड़ जमीन की सिंचाई

हो सके। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या कर रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, एस डी ओ और जे ई वहां आफिसों में बैठे हैं, वे किसी का कोई काम नहीं करते। अगर उनको पैसे दे दिये जायें तब तो वे काम कर देते हैं बगैर पैसे किसी का काम नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, किसान परे पान है उनका काम महीनों तक पड़ा रहता है जब वे बिजली वालों को काम करने के लिए बार बार कहते हैं तब वे लोग उनसे पैसे मांगते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, लोगों को बचाने की बजाय उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे पैसे लेकर ही काम करते हैं। **13:00 बजे** जब रिटायर करते हैं तब उनको आपस में बदल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर कोई भाई अपना कोई काम करवाने के लिए जाता है या कोई रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो कोई भी काम पैसा दिए बिना नहीं होता है। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि इस आदत पर थोड़ा अंकुश लगाया जाना चाहिए और स्थिति को कंट्रोल में करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम होता है उसमें थोड़ा टाईम लगता ही है। (घण्टी) स्पीकर साहब, पुलिस भर्ती के लिए इन्टरव्यू वगैरा हुए हैं और उसकी लिस्ट अभी आउट होनी है। यह कहा जा रहा है कि उसमें कोई हेराफेरी या धांधली नहीं है और सिलैब पान मैरिट पर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह लिस्ट लगाएंगे उसी से पता लग जाएगा कि सिलैब पान फेयर और मैरिट के आधार पर हुआ है या नहीं। अगर उस लिस्ट के अन्दर 20-25 आदमी हर जगहों पर होंगे तो यह लिस्ट सत्य है और हम

मानेंगे कि भर्ती मैरिट के आधार पर हुई है लेकिन आदमी बाहर के होंगे तो हम यह बात असत्य मानेंगे। इस बात का पता चल जाएगा कि इंटरव्यू ठीक लिया है या गलत लिया है। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी (घण्टी) इन भावों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। (विघ्न)

श्री रिसाल सिंह (मुलाना, एस० सी०): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला खराब है फिर भी मैं आपके माध्यम से अपनी बात सरकार को कहने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, डिमाण्डज पर तो बात होती ही है लेकिन चर्चा अपने हलके की जाती है। यह चर्चा इसलिए की जाती है कि हर हलके में अपनी अपनी समस्याएँ और मुश्किलें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने हलके की बिजली की समस्या के बारे में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक बिजली की बात है मेरे हलके में बिजली की बुरी हालत है। अध्यक्ष महोदय, केवल दो चार घंटे बिजली मिलती है और वह भी टूट कर मिलती है और बार बार ट्रिपिंग होती है। भाम के टाइम जब बिजली आती है उस समय थाली में रोटी रखी होती है लेकिन तभी बिजली चली जाती है। अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा बातें न करते हुए बिजली के बारे में एक दो बातें जरूर कहूँगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सभी मैम्बरज से दरखास्त है कि वे जब भी बोल रहे थे या बोलेंगे तो उस समय मैं बीच में उनको इंटरप्ट नहीं करता इसलिए

अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी इंटरप्ट न किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव केसरी में एक 33 के0 वी0 का पावर सब-स्टेशन था और उसकी सीधी लाईन भाखडा से जुड़ी हुई थी हमें यह आवासन दिया गया कि उसकी जगह पर 66 के0 वी0 का सब-स्टेशन बना दिया जाएगा जिससे हमारे गांव के लोग बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि अब हमारे गांव में बिजली ज्यादा आया करेगी। लेकिन अब भी वहां पर 33 के0 वी0 का ही सब-स्टेशन है और उसकी भाखडा वाली लाईन से हटा कर अब हमें पानीपत की लाईन से जोड़ दिया गया है। भाखडा वाली लाईन हटाने की वजह से वहां पर आज बिजली की वोल्टेज कम आ रही है और ट्यूबवैलज भी नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं आपको एक भोर पढ़कर सुनाता हूँ:-

जिस खेत से मुयस्सर न हो रोटी,

उस खेत के हर दाने को आग लगा दो।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके में हर जगह पर डीप ट्यूबवैलज है। पता नहीं दलाल साहब और मुख्यमंत्री जी को अम्बाला जिले से क्यों नफरत है? अम्बाला जिले से पांच मैम्बर्ज हैं और उनमें से चार मैम्बर्ज तो इनके ही साथी हैं। उन्होंने सारे हरियाणा में बिजली के जो रेट लागू किए हैं पता नहीं जिला अम्बाला में वे क्यों लागू नहीं किए हैं? मेरे हलके में 100 फीट तक

के 1513, 100 फीट के 150 फीट तक के 908, 150 से 200 फीट तक के 601 और 200 फीट से ज्यादा के 1579 डीप ट्यूबवैल्ज है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पडोस के हलको मे जहां लोगो को राहत मिली है वही मेरे हलके मे 908 ट्यूबवैल्ज पर 10 पैसे, 601 ट्यूबवैल्ज पर 20 पैसे और 1579 पर 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा रेट लिए जा रहे है। यह अम्बाला जिले के साथ न्याय संगत बात नही है। मै एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब इनका फैसला दूसरे जिलो मे लागू हो गया है तो हमारे जिले मे भी यह लागू होना चाहिए। मेरे हलके मे 154 एम0 आई0 टी0 सी0 के ट्यूबवैल्ज है उनमे से 30 कंडम हो गए है, 22 वर्कींग कंडी न मे है ओर जो बाकी 102 है वहां पर भी पानीका लैवल नीचे चला गया है। तो मेरी आपसे विनती है कि वहां पर उनमे नई मोटरे लगाकर उन ट्यूबवैल्ज को चालू करवाएं। इसके अलावा जनाब, मेरे हलके मे जहां तक रोडज की बात है, वहा सिर्फ उन रोडज की रिपेयर हुई है जिन पर सारे मंत्रियो का आना जाना होता है ये मंत्री महोदय रोहतक, हिसार या पानीपत वगैरह जाते है या फिर बहन कमला वर्मा या सुभाश चौधरी जाते है। बाकी जितने मेरे हलके के रोडज है उनकी रिपेयर नही की जाती। बहुत सी रोडज ऐसी हो गयी है जिनमे बहुत खडडे पड गये है यहां तक कि कुछ रोडज की ऐसी हालत है जिन पर स्कूटर या मोटर साईकल पर बैठकर गर्भवती महिलाए चलना पसंद नही करती क्योंकि उनको गर्भपात का डर होता है। आज तक वहां पर किसी भी सडक की रिपेयर नही हुई है। इसकी वजह से सडके

टूट टूट कर जोहड मे गिरने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी रोडज की हालत हमारे हलको मे ही क्यों है? इसके अलावा चार सडके मेरे हलके मे ऐसी है जिन पर अर्थवर्क तो हो चुका है। यह अर्थवर्क तीन साल पहले हो चुका था इन पर मिटटी वगैरह गिर चुकी है और अब रोडी पडनी है। लेकिन वहां आगे काम न होने के कारण वह मिटटी भी बह रही है। इन सडको की तरफ भी ध्यान दिया जाना जरुरी है। सडके न होने की वजह से वहां के लोगो को बहुत परे ानी है इसलिए मेरा कहना है कि पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के मे, गावो मे हरिजन बस्तियो मे या बैकवर्ड बस्तियो में वाटर सप्लाई नहीं हो रही है इसलिए मंत्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होने धीरपाल सिंह द्वारा इस बारे मे कही गयी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। यह तो वही कहावत हुई कि "सारी खुदाई एक तरफ ओर जोरु का भाई एक तरफ" फिर भी मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जहां जहां ऐसी बस्तियां है वहां पर उनको पीने का पानी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो भाराब बंदी हो गयी थी तो हमने सोचा था कि इसके रिजल्टस अच्छे निकलेगे और अच्छे आदमियो को इससे राहत मिलेगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि भाराबबंदी को पूरे तरीके से लागू करवाया जाए। कम से कम मैंने तो पूरी कोशिश की है। जिन लोगो ने भाराब बेचने वालो को उस समय पकडवाया था, उनको ही पुलिस के डंडे लगे थे, उनके ही सिर फुटे। इसलिए इसके फेल होने की

वजह हम नहीं है इसकी वजह या तो सरकार है या फिर भाराब माफिया है या फिर पुलिस है। लोगो को पुलिस द्वारा जब पीटा गया तो उन्होंने इस बारे में पुलिस से रिक्वायत करना बंद कर दिया। इसी तरह से पुलिस में जो भर्ती हुई है उसमें कोई कहता है कि डेढ़ लाख रुपये लेकर होगी कोई कहता है कि फेवरेटिज्म होगा। वह तो जो होगा बाद में पता चल जाएगा लेकिन जैसी घोशणा की गई है कि हर हल्के से 20 आदमी लिए जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हल्के के आदमी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हैं और फिर भी उन्हें नहीं लिया जाता है तो यह उस हल्के के साथ भेदभाव होगा, अन्याय होगा। यह जो कहा गया है एक हल्के से 20 आदमी लिए जाएंगे यह एक झूठी घोशणा होगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान कानून और व्यवस्था की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। रोहतक और सोनीपत जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस हो चुकी है क्योंकि ये दोनों ही जिले यू० पी० और दिल्ली राज्यों के साथ लगते हैं, इसलिए इन में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। भाराबबंदी के वक्त एक भाराब का माफिया जो प्रदेश के अंदर उभरा था, आज भाराबबंदी खत्म होने के बाद भी वह दिन-दहाड़े कत्ल करता है, लूट-खसोट करता है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अंदर बहु-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार को इस की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे हलके में पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने सुखबरा से लाडों वाली सड़क को साढ़े चार फुट उंचा उठा दिया है। वहाँ पर एक कॉलोनी है जिसमें 500 मकान बने हुए हैं। इस सड़क को उपर उठाने की वजह से इस कॉलोनी में पानी खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी यह मांग है कि वहाँ पर नाला बनाया जाए। इसी प्रकार से भालोट से भी पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि विभाग की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर नकली दवाईयाँ और खाद बेची जाती हैं। इससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होता है बल्कि प्रदेश के विकास को भी बड़ा भारी लोस होता है क्योंकि इससे पैदावार कम हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने एक ड्रेन रठाल गांव से मुंढाल तक बनाई थी जिस पर लगभग 50-60 लाख रुपए का खर्च आया था

लेकिन परिणाम यह निकला कि रिठाल गांव से एक लिटर पानी भी नहीं निकला। इसलिए ऐसे अधिकारी जिनको ड्रेनेज का लेवल भी करना नहीं आता है, मैं पूछता हूं कि उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? (घंटी) अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा विभाग की तरफ सदन का थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे सरकारी स्कूला का स्तर नीचे जा रहा है और हर एक गांव में प्राइवेट स्कूलों की दुकानें खुल गई हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं तथा पोस्टे भी सरप्लस हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस आरे कुछ कदम उठाए जाएं ताकि गरीब लोगों को कोई नुकसान न हो। धन्यवाद।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं डिमांड नं० 2 से लेकर 23 तक आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। (विधन) आज से दो सवा दो साल पहले यह सरकार बनी थी। जनता ने पिछली सरकारों से परे जान हो कर चौधरी बंसी लाल जी में अपना विश्वास किया था तथा इनको अपनी सरकार बनाने का मौका दिया था। जनता को बड़ी उम्मीदें थी कि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आने के बाद हरियाणा का विकास होगा। बिजली के बारे में भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। पहले यह कहा जाता था कि बंसी लाल जी हरियाणा के निर्माता हैं। यह बात सच है कि बंसी लाल जी जब पहले मुख्य मंत्री थे उस समय

हरियाणा का निर्माण हुआ था। अब इस सरकार को बने 2 साल 2 महीने हो गए हैं लेकिन जब सरकार बने हुए 6 महीने ही हुए थे तभी लोगो ने अपनी परे गानियां बतानी भुरु कर दी थी। अब उनकी उम्मीदें बेकार चली गई है। ये कहते थे कि हरियाणा के प्रत्येक गांव तक तक सडक पहुंचाएंगे लेकिन इन दो सालो मे सडको का बहुत बुरा हाल है। मैं अपने हलके की सडको के बारे मे बताता हूं मेरे हलके सोनीपत मे 24 गांव है किसी भी गांव की सडक पर आराम से ट्रक नहीं चल सकता, बैलगाडी नहीं चल सकती, यहां तक कि आदमी का भी चलना मुकिल है। अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटी सी मिसाल सडको से पहले बिजली के बारे मे देना चाहता हूं। कल जिस समय मुख्य मंत्री जी बिजली के बारे मे बता रहे थे कि बिजली मे सुधार हुआ, उस समय सोनीपत मे मुरथल से 8 किलोमीटर जाम लगा हुआ था। वह जाम लगभग 10 घंटे इसलिए रहा क्योंकि 8 दिन से बिजली न मिलने के कारण लोगो ने मुरथल से पानीपत तक जाम लगा रखा था। इसका जिक्र आज अखबार में भी है। मेरे हलके के किसी भी गांव मे 8-8 दिन तक बिजली नहीं आती और ये कहते है कि आने वाले समय मे लोगो को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री जी मेरे हलके सोनीपत मे 6 जुलाई 1977 को आए थे इन्होने वहां एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि 31 मार्च 1998 तक सोनीपत मे 220 के0 वी0 का एक सब स्टे इन स्थापित हो जाएगा। वह सब-स्टे इन चालू तो क्या हुआ बल्कि उसका आधा सामान उठाकर रोहतक ले गए। आज सदन मे मंत्री जी द्वारा

आ वासन दिया गया है कि 1999 मार्च तक उस सब-स्टे 11 को चालू कर दिया जाएगा। मैं यह कहता हूँ कि चलो अब ध्यान दिया तो सही लेकिन यह बात आ वासन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज जो बजट रखा गया है वह केवल झूठ के पुलिन्दे बनाकर जनता को उलझाने के लिए रख दिया गया है। आज जनता जागरूक है और वह ऐसे छटपटा रही है जैसे एक मछली बिना पानी के छटपटाती है। जनता अवसर ढूँढ रही है कि इस सरकार को कैसे हटाया जाए और जैसे ही जनता को अवसर मिलेगा। वह इस सरकार को एक मिनट भी नहीं रहने देगी। जहाँ तक कानून और व्यवस्था की बात है, मैं अप्रैल में अस्पताल में दाखिल था, मेरे हलके के कुछ आढती खरखौदा से पेमेंट लेकर आ रहे थे, उनको रास्ते में लूट लिया गया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई और लूटने वालों के नाम भी बताए। पुलिस उन डकैतों को पकड़ कर भी लाई लेकिन वहाँ के किसी मंत्री के कहने पर उन लोगों को छोड़ दिया गया। 2-3 दिन बाद वे आढती दिल्ली में मुख्यमंत्री से मिले। मुख्य मंत्री ने फोन किया और फिर उन डकैतों को पकड़ा गया। इसके बाद उनकी पेमेंट भी वापिस हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हलके सोनीपत के वार्ड नं 2 गढ़ी घसीटा के 17 वर्शिय राके 1 की निर्मम हत्या का जिक्र करना चाहूँगा। जिसमें उसके पिता राम कुमार ने आवेदन किया है कि उसके बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा कर राम निवास ने उसको मार कर रेलवे लाईन पुलिया के बीच डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, उसकी ला 1 26-3-98 को दो टुकड़ों में पाई गई। इस

बारे में जी० आर० पी० सोनीपत में केस भी दर्ज हुआ। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में निष्पक्ष जांच करवाए। अध्यक्ष महोदय, आवेदनकर्ता का यह आरोप भी है कि इस केस में सरकारी तंत्र हत्यारों की मदद कर रहा है। इस बारे में माननीय गृह मंत्री को सूचना भेज रखी है और मुख्य मंत्री जी को भी सूचना भेज रखी है। वह गरीब इंसाफ के लिए भटक रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस वार्ड घसीटा में कुछ भारारती तत्व रात को लगभग 11 बजे से सुबह चार बजे तक मकानों में पत्थर फेंकते हैं जिसके कारण वहां के लोगों के दिलों में दहशत फैली हुई है। मैंने इस बारे में वहां के एस पी को चिट्ठी भी लिखी और फोन भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी उन लोगों के घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान व्यापारियों पर हो रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछली सरकार की तय नीतिके अनुसार मण्डी के लाईसैंस जुदा पुराने आढतियों को ही नई मंडियों में फिक्सड प्राईस पर प्लॉट दिये जाते थे और उन्हें प्लॉट देने के बाद बाकी बचे प्लॉटों की नीलामी की जाती थी लेकिन मौजूदा सरकार ने पुराने आढतियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए करनाल में सभी प्लॉटों की नीलामी की, उस बारे में सभी जगहों के व्यापारियों ने आन्दोलन छेड़ा हुआ है। वहां पर सोनीपत के व्यापारियों ने भी गिरफ्तारी दी है आज भी वह आन्दोलन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का कर्मचारी

वर्ग अपने हको के लिए लडने के लिए अपनी कमर कस रहा है और दूसरी तरफ किसान भाई अपनी समस्याओ से जुझते हुए दयनीय स्थिती मे अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। किसान आत्महत्या कर रहे है। अभी 22-7-98 के इंडियन एक्सप्रेस मे किसानो द्वारा आत्म हत्या किये जाने का समाचार प्रकाशित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की सडको की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सडको के रख रखाव एवं निर्माण हेतु 245 करोड रुपये का प्रावधान बजट मे रखा है।

श्री अध्यक्ष: दीवान साहब आप बैठिये। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट मे अपनी बात को खत्म कर देता हू।

श्री अध्यक्ष: नही नही, अब आप बैठिये।

श्री देवराज दीवान: यदि आप मुझे बोलने के लिए समय नही दे रहे तो मैं अपने कुछ प्वायंटस जो मेरे द्वारा बोलने से रह गए है, आपकी इजाजत से सदन की टेबल पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(इस समय माननीय सदस्य, श्री देवराज दीवान द्वारा कुछ पेपर चेयरमैन साहब की अनुमति से सदन की टेबल पर रखे गए)

श्री देवराज दीवान: परन्तु आज हरियाणा की स्थान स्थान पर टूटी हुई सड़के सरकार की खोखली नीति को जाहिर कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि सोनीपत हल्के की निम्नलिखित सड़के जिनका निर्माण तथा मुरम्मत पिछले वर्ष हो जाना चाहिए था, अभी तक पुरी नहीं हुई है—

- (1) सोनीपत भाहर मे रेलवे फाटक से गोहाना रोड तक
- (2) सोनीपत भाहर मे रेलवे फाटक से मण्डी तक
- (3) सोनीपत बस अड्डा से गांव माहरा तक
- (4) सोनीपत मे गीता भवन चौक से लेकर रैस्ट हाउस—कालूपुर रोड तक सड़क को मजबूत करना, सोनीपत से बहालगढ जी० टी० रोड हाई—वे और सोनीपत से मुरथल जी० टी० रोड, हाई—वे को चौडा करना।
- (5) सोनीपत मे गीता भवन से बस—अड्डा तक कंकीट पेमेंट करना।
- (6) चटाना गांव से खिजरपुर जट माजरा की सड़का का निर्माण।

(7) माहरा गांव से सिटावली गांव तक की सडक की मुरम्मत ।

(8) हुलैडी की सडक के लैवल को उंचा करना ।

गांव कैला ापुर तथा गांव बैयां खुर्द मे जाने का रास्ता नही है । आज तक दोनो गांव के लोग कई सालो से परे ान है । इन गावो को भाहर से जोडने के लिए रास्ता देकर इन गरीब लोगो की परे ानी को दूर किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव चटाला और माहरा मे वर्षा के दिनो मे दो दो तीन तीन फुट तक पानी खडा हो जाता है । जिससे बच्चो को स्कूल मे जाने मे बहुत दिक्कत आती है । मै मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि इस उपरोक्त कार्य को भीध्र पूरा किया जाये ।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मै माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि सोनीपत भाहर की 12 सडको की मुरम्मत के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये गये थे लेकिन सोनीपत के डी0 सी0 महोदय ने यह राशि उस समय अन्य कार्य पर लगा दी जिससे इन सडको की मुरम्मत नही हो सकी । कृप्या इस विशय मे भी जांच करवाई जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि हर आबादी के साथ एक भाम ान-घाट का होना अनिवार्य है । मेरे हलके के गांव

चटाना, जुआं, माहरा, मोहाना, नैना, तितारपुर, खिजरपुर जट माजरा, सांदल खुर्द तथा सांदल कलां आदि गावों में भामान-घाट तक जाने का रास्ता कच्चा है। वर्षा के दिनों में रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है। जिससे मृतक भारीर को भामान-घाट तक ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो अर्धी उठाए हुए लोगों के फिसल जाने के कारण बहुत दिक्कत होती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हलका सोनीपत के सभी गावों के भामान भूमि जाने के रास्ते भी धरपक्के करवाए जायें।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान गांव की चौपालों की मरम्मत और नवनिर्माण की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरे हलके सोनीपत के निम्नलिखित गावों में चौपालों की मरम्मत तथा निर्माण होना है।

गांव मोहाना	वाल्मीकी तथा धानकान चौपाल
गांव सांदल कलां	धानकान चौपाल
चटाना	वाल्मीकी चौपाल तथा बी सी चौपाल
जाहरी	वाल्मीकी चौपाल

ठरु	हरजिन चौपाल
भाहजादपुर	हरिजन चौपाल
उल्देपुर	हरिजन चौपाल
पिनाना	धानकान चौपाल तथा बी सी चौपाल
जुआ नं0 2	बी सी चौपाल तथा हरिजन चौपाल
सांदल खुर्द	बी सी चौपाल
थरिया	बी सी चौपाल

श्री राम जी लाल (सढौरा, एस0 सी0): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम लोगो को रहने के लिए स्वच्छ वातावरण देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हिमाचल से मारकण्डा नदी निकलती है, उसमें हिमाचल की इंडस्ट्रीज का इतना गंद पडा हुआ है कि उसका पानी पीने से आदमी बीमार हो जाता है। यह नदी मेरे हलके के पडोसी राजय मंत्री राज कुमार जी के गांव के नजदीक से होकर गुजरती है। उनके गांव में पीने का पानी नहीं है वे बाहर से पीने का पानी मंगवाते हैं। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, इस नदी के किनारे पर सैंकडो गांव हैं जिनमें पीने के पानी की बहुत कमी है अगर वहां

के लोग नदी का पानी पीते हैं तो लोगो को पीलिया हो जाता है और लोग बीमार हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जिन गावों में नलके लगे हुए हैं उन नलको को चालू किया जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह भी जानना चाहूँगा कि क्या ये मारकण्डा नदी की गंदगी को साफ कराने का काम करवायेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं कानून व्यवस्था के बारे में बताऊँगा। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में किडली माडल टाउन में सतपाल ऐडवोकेट के घर पर डाका पडा था लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के गांव मियंपुर में भी एक आदमी को मार दिया गया जिसका एफ0 आई0 आर0 नं0 26/1-2-98 है, इसी तरह से सुलतानपुर में भी एक आदमी को मार दिया गया जिसका एफ0 आई0 आर0 नं0 49/29-3-98 है लेकिन अभी तक पुलिस इन कातिलो को पकड़ नहीं सकी है और न ही सरकार ने कोई कार्यवाही भुरु की है। अध्यक्ष महोदय, गांव खेताली में एक आदमी को मार दिया गया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आज से 8 रोज पहले एक चलती हुई टैक्सी के मालिक को अज्ञात हमलावरो ने 3-4 गोली मारी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह पी0 जी0 आई0 में आने के बाद बच गया। उन डकैतो को भी सरकार ने आज तक नहीं पकडा है। इसके साथ साथ मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि जब हम सै 1 न में आ रहे थे, तब रास्ते में 12 बजे बरवाला में रामगढ में लोगो ने रोड ब्लाक कर रखी थी, जिसके कारण हमें दो घंटे वहां खडे रहना

पडा। उन लोगो ने बताया कि दो लोगो ने वहां से 45 भैंसे चुराकर बेच दी। उन्होंने दौड़ घूप करके उन चारो को पकडवाया लेकिन पुलिस ने 10 हजार रुपये लेकर उनको छोड दिया। वे लोक कह रहे थे कि हम रास्ता तभी खोलेगे जब पुलिस उन लोगो को सजा देगी। अध्यक्ष महोदय, एस0 डी0 ओ0 साहब वहां मौके पर मौजूद थे लेकिन उनके कहने पर भी उन्होंने रास्ता नही खोला। अध्यक्ष महोदय, मैंने उन लोगो को आवासन दिया कि मैं उन लोगो की बात हाउस के सामने रखुगा तब जाकर उन लोगो ने रास्ता खोला। तीन घंटे तक रास्ता जाम होने से सवारियां बहुत ज्यादा परे गान थी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से बिजली के रेट्स की स्लैब प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने विवालीक बोर्ड की मीटिंग मे भी मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि अंबाला मे खास तौर पर एम आई टी सी के 68 से लेकर 72 तक ट्यूबवैल चौधरी बंसी लाल जी के लगवाये हुए है। इस बारे मे सर्वे करवाने की आवश्यकता नही है। मुख्य मंत्री जी को पता है कि यहा पर एम आई टी सी के ट्यूबवैलो की गहराई 575 फुट है। इसके साथ ही वहां आम आदमी के ट्यूबवैज 350 से 375 फुट गहरे है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन लोगो के ट्यूबवैल गहरे है उन का फिर से सर्वे करवाने की बजाय बिजली के रेटस स्लैब प्रणाली के तहत लिए जाएं क्योंकि सारा रिकार्ड आपके पास मौजूद है। जिनके ट्यूबवैल की 15 हार्स पावर की मोटरे है उसकी गहराई 300 फुट है और जिनके ट्यूबवैल की 10 हार्स पावर की मोटरे है उनकी गहराई 200 फुट है। लगभग

सारी स्थिती आपके समक्ष है इसलिए इसकी दोबारा सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं है। यह रेटस उसी तरह से लागू किये जाये जैसे दूसरे जिलो मे लागू किए गए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ि त्वालिक बोर्ड की कार्यप्रणाली की ओर दिलाना चाहूंगा। वहां पर कण्डी वालो की तरफ से छोटे छोटे बांध बांधे गये है। इसका सारा रिकार्ड मेरे पास है। कण्डी वालो ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है जो कि 30% बांध बंधे है उनके भी लोग 30% पत्थर उठाकर ले गये है। कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कहते है कि हमने ये लगाये है ओर कभी कण्डी वाले कहते है कि हमने लगाये है। इस बारे मे लोग दुविधा में है। लोगो को न तो इनसे कोई राहत मिली है और न ही उन्हे किसी किस्म का फायदा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया भर का पत्थर चोरी करके कभी कण्डी वाले बेचते है, कभी एग्रीकल्चर वाले बेचते है। इसके साथ ही मैं कोओपरेटिव सोसाईटिज और गवर्नमेंट सोसाइटीज के बारे मे भी सरकार को बताना चाहूंगा कि आज की स्थिती मे जितनी भी कोओपरेटिव सोसाईटिज है वे सारी की सारी भंग है और अधिकारी अपनी मनमानी करते है। वे हर सोसाईटी मे 2-2 या 3-3 आदमी एडजस्ट कर रहे है। जब कि वे सोसाईटिज आलरेडी घाटे मे चल रही है। मैंने को ओपरेटिव मिनिस्टर के समक्ष भी अनुरोध किया था और लिखित रुप मे ि ताकायत भी की है परन्तु उस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हिमाचल मे एक पेपर प्रगति मिल लगी है

यह मिल हरियाणा मे जबरदस्ती छोटा मारकण्डा कग्रस करके रास्ता लेनाचाहती है जबकि रास्ता हिमाचल के उपर से हो कर आता है। उसने जबरदस्ती छोटा मारकण्डा से रास्ता बाउंड करके रास्ते पर मिटटी डाल कर पानी हरियाणा की तरफ मोड दिया और 50-60 गावो को नुकसान कर दिया। उन लोगो की जो जीरी की फसल लगी हुई थी वह उस पानी मे बह गई। अब उन लोगो ने दुबारा जीरी की फसल लगाई है। इसके साथ लगते हुए गांव कलौडी, इनजामपुर, राजपुर, नाहर पुर, बीड, माजरा, असगरपुर, डूमावला, पहाडी पुर, बकाला, हवेली, फिरोजपुर आदि है जो कि इस पानी ने लगभग तबाह कर दिये है। वह मिल जगरदस्ती हरियाणा से रास्ता लेना चाहती है और पुल लगा कर पानी उन सारे गावो की तरफ डालना चाहती है। स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पंचायती जमीनो का जो मामला है वह बहुत ही गम्भीर है। सारी पंचायती जमीनो पर नाजायज कब्जे है। सबसे पहले मै आपको अपने गांव की दुर्द ता बताता हूं। मेरे गांव मे 190 एकड जमीन पंचायत की है। सरपंच के खिलाफ मैने कई मर्तबा लिखकर दिया है, इस बारे उसको सस्पेंड भी किया गया था लेकिन फिर डी० सी० यमुनानगर ने उसको बहाल कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मै आभारी हूं कि अपनी माननीय मंत्री बहन कमला वर्मा जी का जो उनकी पु त है और बार बार भाह देकर उसको बहाल करवाती है। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिती यह है कि उस सरपंच ने 15 लाख रुपये की लक्कड 5000 रुपये पर आदमी से लेकर उस गांव की कटवा दी है, लेकिन उसके

खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके बारे में मैंने डी० सी० को भी इन्कवायरी के लिए कहा परन्तु बहन जी ने उसकी इन्कवायरी नहीं होनी दी और न ही अब होने दे रही है। इसके साथ ही साथ हरिजनो के साथ जो इतने अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। (विघ्न) हरियाणा में हरिजनो को जो मकान बनाने के लिए राशि अनुदान के रूप में दी जाती है वह बहुत कम है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 2200-2300 रुपये प्रति हजार तो ईंट आती है इसलिए पांच हजार रुपये की ग्रांट से मकान नहीं बन सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह राशि कम से कम 15 हजार रुपये की जाए ताकि कोई गरीब आदमी लोन ले कर ग्रांट ले कर कम से कम अपना मकान तो खड़ा कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बिजली की कमी के कारण पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक प्रकार से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हरिजन बस्तियों में जहां जहां कुएं लगे हुए हैं उन कुओं की मरम्मत के लिए 15-15 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने की कृपा करें ताकि वे अपने कुओं से पानी निकाल सकें। ऐसी हालत बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की भी है। (घण्टी) बी० सी० के भाईयो को भी वैसी ही सुविधाएं दी जानी चाहिए जैसी एस सीज को दी जाती है। उनकी बस्तियों की गलियों को पक्का करने के लिए ओर कुओं आदि के लिए भी अनुदान दिया जाना चाहिए। बहन जी उठ कर चली गईं हैं। मैं वृद्धावस्था पेंशन की चर्चा फिर कर रहा हूँ। वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति यह है कि

लारे मे रख कर लोगो से पैँ न के फार्म भरवा भरवा कर 7-7 या 8-8 महीने तक चक्कर कटवाते रहते है और आजतक लोगो से चक्कर कटवा रहे है। आज तक जिन लोगो ने पैँ न के लिए फार्म भरे हुए है उनको नई पैँ न नही मिल पाई है। अध्यक्ष महोदय, मै एक बात ि ाक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मैने इस बारे मे ि ावालिक बोर्ड की मीटिंग मे भी चर्चा की थी और यहां पर भी कहता हूं कि मेरे सढौरा हलके मे एक भी गवर्नमेंट कालेज नही है। गवर्नमेंट कालेज तो दूर की बात है वहां पर तो कोई गर्ल्ज कालेज भी नही है। अध्यक्ष महोदय, ि ावालिक बोर्ड के सढौरा एरिया मे कम से क एक गर्ल्ज कालेज तो दे ही सकते है। वहां पर प्राईवेट स्कूलज है लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। यमुनानगर और बिलासपुर मे प्राईवेट कालेज है। ये कृपा करके बिलासपुर के नजदीक एक गवर्नमेंट कालेज तो खोल दे। (घंटी) इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मै सडको के बारे मे जब मंत्री जी से अपना सवाल कर रहा था तो उन्होने कहा कि जवाब सदन की पटल पर रख दिया है। उसमे उन्होने सत् 2001 तक सडको को पूरा करने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, तब तक तो लोग खडडो मे गिर गिर कर मर जाएंगे क्योंकि बहुत ही बुरी हालत उन सडको की है। मंत्री जी कम से कम वहा पर उन सडको के खडडो मे मिटटी डाल कर उनको भरने की कृपा करे ताकि वहां पर लोगो के एक्सिडेंटस कम हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से सर्व श्री नफे सिंह राठी, नफे सिंह जुंडला, राम फल कुण्डु, ओ० पी० जैन, कृष्ण लाल पंवार और रेलु राम ने बोलना है। अब श्री नफे सिंह राठी जी बोलें। (विघ्न)

श्री नफे सिंह राठी (बहादुरगढ): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं० 8, 15, और 23 पर बोलना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं कानून व्यवस्था की चर्चा सदन में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब से झज्जर नया जिला बना है तब से लेकर आज तक जिला झज्जर में जितने भी अपराध हुए हैं उससे पहले उतने अपराध जिला रोहतक में नहीं हुए थे। स्पीकर साहब, इन चार महीनों के दौरान जिला झज्जर में 40 आदमियों की गोली से मार दिया है लेकिन अब तक पूरे मुलाजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक दिन में 21 आदमियों को गोली मारी गई। गोली मारने वाले कैथल में मुख्य मंत्री जी के रि तदार के घर में गए। स्पीकर साहब, यह बड़े ही दुख की बात है कि इस तरह से मुख्य मंत्री जी और इनके रि तदार उनको भाह देते हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री कपूर चन्द भार्मा पदासीन हुए) सभापति महोदय, वहां पर जिस आदमी का कत्ल हुआ था उसका भाई और वहां के लोग मुख्य मंत्री जी से 18-4-98 को मिलने के लिए दिल्ली में गए। जिसका कत्ल हुआ था उसके भाई ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज 12 दिन हो गए हैं लेकिन उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभापति महोदय,

मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से बहादुरगढ के उन लोगो के साथ व्यवहार किया, वह बहुत निन्दनीय है। जब मरने वाले के भाई ने वह बात कही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे 20 मर जाए, मैं कोई तुम्हारा ठेकेदार नहीं हूँ। इस तरह से इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह की बात कहे ये ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यह जो 4-4-98 को कत्ल हुआ उससे एक दिन पहले 3-4-98 को बहादुरगढ में हरिओम नाम के लडके को बीच बाजार में गोली मार दी गई। लेकिन आज तक कातिल नहीं पकडा गया। आज बहादुरगढ को चम्बल की धाटी बना दिया गया है क्योंकि अब वहां पर बहुत बदमाश आ घुस आए हैं और इनको सरकार के मंत्री एवं मुख्य मंत्री के रिश्तेदार भाह देते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि जो ये वहां पर निरंतर घटनाएं हो रही हैं, अगर इन पर काबू न पाया गया तो हरियाणा के लिए बहुत ही दुखदायी समय आने वाला है क्योंकि दिल्ली के साथ लगते एरिया से, यू0 पी0 के साथ लगते एरिया से, बदमाश आकर भारण लेने लगे हैं। पहले बहादुरगढ में बेबी किलर कांड एक दो नहीं बल्कि आठ-नौ हुए। आठ या नौ साल की छोटी छोटी बच्चियो के साथ कांड करने वाले जब नहीं पकडे गए तो वहां के लोगो ने इसके विरोध में आक्रोश में प्रदर्शन किए, धरने दिए। लेकिन इन निहत्थे लोगो पर सरकार ने पुलिस से गोली चलवाने का काम किया। इस गोली कांड में दो लडके मारे गये और कई घायल हुए। इसकी इंक्वायरी तो सरकार करवा रही है लेकिन गोली चलाने वाले अधिकारियो का आज तक वहां

से तबादला नहीं किया गया है। वे आज भी वहां मौजूद हैं। इसलिए यह कैसे संभव है कि उनको न्याय मिलेगा, जांच कैसे निष्पक्ष होगी? जो अधिकारी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, कम से कम सरकार उनका वहां से तबादला तो करना ही चाहिए। इस बारे में मेरे एक दो सुझाव हैं। सरकार को सर्वप्रथम तो बहादुरगढ़ तो अमानत क्षेत्र घोषित करना चाहिए। साथ ही बहादुरगढ़ में पुलिस स्टाफ भी बढ़ाया जाना चाहिए। वहां और पुलिस अधिकारी लगाए जाने चाहिए। सभापति जी, आज भी बहादुरगढ़ सदर थाने में एस0 एच0 ओ0 नहीं है। दो महीने से यह पद खाली पड़ा है फिर कैसे वहां भांति हो पायेगी? इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ विशेष ध्यान देने की वह कृपा करे। इसके अलावा जहां तक परिवहन व्यवस्था की बात है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ से दिल्ली लगभग 15 हजार आदमी डेली पैसेंजरी करते हैं लेकिन इस सरकार ने बहादुरगढ़ से दिल्ली आने जाने वाली हरियाणा रोडवेज की दस बसों बंद कर दी हैं। जब हम इस बारे में अधिकारियों से मिले तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि सी0 एम0 के आदेश हैं। सभापति महोदय, अगर अपोजीशन का हलका होने के कारण इस तरह की यातनाएं वहां के लोगों को दी जाएंगी तो वह निंदनीय कार्य है। ये बस वहां से दोबारा चलाई जानी चाहिए। सभापति महोदय, बहादुरगढ़ में पिछले दिनों जमीन एक्वायर की गई। जहां यह जमीन अधिग्रहण की गई वह इलाका दिल्ली के साथ लगता हुआ है। दिल्ली में जब जमीन अधिग्रहण

की जाती है तो किसानों को 12 या 13 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है लेकिन हमारी इस सरकार ने किसानों को सिर्फ दो या अढ़ाई लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है जो कि बहुत कम है। जो इलाका वहां सड़को के किनारे लगता है केवल उन्हीं दस परसेंट किसानों को चार या पंच लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है लेकिन बाकी 90 परसेंट किसानों को दो या अढ़ाई लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। सभापति जी, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे दिल्ली में किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण करने के बदले में 12 या 13 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है वैसे ही हरियाणा में भी दिया जाना चाहिए। हरियाणा के किसान के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? यह मुआवजा राशि बढ़ायी जानी चाहिए। इसके अलावा जिस किसान की जमीन अधिग्रहण की जाए उस किसान को एक एक प्लॉट भी वहां पर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां रैजिडेंसियल प्लॉट काटे जा रहे हैं? सभापति जी, वहां के किसान बिल्कुल बर्बाद हो गये हैं क्योंकि उनके पास तो थोड़ी थोड़ी जमीन थी वह भी सरकार ने एक्वायर कर ली। वहां जो जमीन नगरपालिका की सीमा के अंदर है जिसकी रजिस्ट्रीयां सरकार 10 या 15 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम पर नहीं कर रही है वहां दो लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जबरदस्ती जमीन खरीद रही है। मेरा यह निवेदन है कि जिनकी जमीन ली गई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, मुआवजा राशि बढ़ाकर दी जाए और

उनको एक एक प्लाट भी दिया जाए। सभापति महोदय, दुख की बात यह है कि 1160 साल पहले बहादुरगढ़ बसा था उस समय वहां एक भामान घाट था उस भामान घाट को भी सरकार ने एक्वायर कर लिया है। मेरी गुजारिश है कि कम से कम भामान घाट को तो एक्वायर न किया जाए उसको तो छोड़ दिया जाए। सभापति महोदय, बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बिजली तो आती नहीं है और बिल कई कई हजार रुपये के आते हैं। बिजली के बिल थामने से पहले दिल थामना पड़ता है। जो ये कम्प्यूटराईज्ड बिल आ रहे हैं वे बिल गलत हैं उनमें गलत आंकड़े दिये जाते हैं। लोगों को इनकी वजह से बिजली बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन कोई ठीक करने वाला नहीं है इसलिए इन कम्प्यूटराईज्ड बिलों को बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्यूबवैज के कनेक्शन भी नहीं दिये जा रहे हैं और सरकार ने आदेश दिया है कि 30 सितम्बर, 1998 तक कोई नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा। हमारे बहादुरगढ़ में बिजली के लोहे के खम्बे काफी समय से गढ़े हुए हैं वे अब नीचे से गल गए हैं और वे खम्बे केवल तारों पर टिके हुए हैं, लेकिन वह भी नहीं बदले जा रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर बदले जाए। सभापति महोदय, पूरे हरियाणा में सड़कों का बुरा हाल है। मैं बहादुरगढ़ उपमंडल की सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा। वहां की सड़कें ऐसी हैं कि लोग सड़कों की बजाय नीचे से चलना पसंद करते हैं। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह जी छारा में गए थे। छारा बहादुरगढ़ उपमंडल का बहुत बड़ा गांव है।

(घंटी) तब वे गए तो रास्ते में सड़क इतनी टूटी पड़ी थी कि कार नीचे से उतर गई और उसका चैम्बर फट गया, पेट्रोल फैल गया। फिर वे जीप में बैठकर गए। आप सरकार से कहे की सड़क जल्दी से ठीक करवाई जाएं।

श्री सभापति: आपका समय हो गया है, आप बैठ जाएं।

श्री नफे सिंह राठी: आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री सभापति: आपको कन्कलूड करने के लिए दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री नफे सिंह राठी: ठीक है जी। सभापति महोदय, कुछ सड़क मार्किटिंग बोर्ड ने बनानी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मार्किटिंग बोर्ड की जो सड़क अधुरी पड़ी है वह सड़क पूरी करवाई जाए। वह सड़क है— कसार से नूना माजरा। (विधन)

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक): सभापति महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, जिन सड़क का ये जिक्र कर रहे हैं पिछली सरकार ने ये सड़क कम्पलीट करवाकर इनकी पेमेन्ट भी कर रखी है। हमने इनका सारा रिकार्ड तैयार कर रखा है और इस मामले की जांच करवा कर कार्यवाही की जाएगी।

श्री नफे सिंह राठी: अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच करवाई जाए। सभापति महोदय, मेरे हलके में सब्जी मंडी को ट्रांसफर किया जाये। सभापति महोदय, पानी की भी वहां बहुत गम्भीर समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि गुडगांव कैनाल का पानी माईनर के द्वारा बहादुरगढ़ को 30 जून, 1998 को मिल जाएगा लेकिन आज तक उस माईनर का काम भुरु नहीं हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस माईनर का काम जल्दी से भुरु किया जाये ताकि लोगो को पानी की समस्या से निजात मिल सके और पीने को पानी मिल सके। जैसा कि यहां पर पंचायत की भामलात भूमि पर नाजायज कब्जो का जिक्र आया। सौली गांव में 28 एकड़ भूमि को सरपंच ने बिना मुनादी करवाए कोडियो के भाव दस हजार रुपये के पटटे पर दे दिया जिसमें 20-25 लाख रुपये का गबन किया गया है। जबकि भाव डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ था और दिया गया छ हजार प्रति एकड़। इस मामले की जांच की जाये और दोशी सरपंच या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। सभापति जी, जकोदा गांव से कसार गांव का रास्ता नाजायज तौर से बन्द कर दिया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस रास्ते को खुलवाया जाये। (घण्टी) सभापति जी, हम तो नये नये चुनकर आये हैं बोलना भी सीख लेंगे। मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करता हूँ। सभापति जी, सरकार की जो खेलो से संबंधित नीति है उस पर पुनर्विचार किया जाये। खेलो का नौकरियो में जो कोटा घटा दिया गया है मेरा सरकार से निवेदन है कि उस कोर्ट को बढ़ाया जाये। सभापति जी बहादुरगढ़ क्षेत्र के

नौवामाजरा गांव की प्राइमरी स्कूल की फुटबाल टीम लगातार तीन सालो से प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है परन्तु उन खिलाडियो को कोई सुविधा सरकार की तरफ से नही दी गई है। उनको कोई आने जाने का खर्चा भी सरकार की तरफ से नही दिया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि खेलो के प्रति पुनर्विचार करके खिलाडियो को उचित सुविधा दी जाये। (विघ्न) सभापति जी, पिछले साल रेल मंत्री जब बहादुरगढ आये तो लोगो ने उनके सामने डिमाण्ड रखी थी कि रेलवे लाईन के पार जो 30 हजार के लगभग आबादी है उसके आने जाने की सुविधा के लिए रेलवे लाईन पर एक पुल का निर्माण किया जाये तब उन्होने कहा था कि अगर राज्य सरकार आधा खर्च पुल के निर्माण के लिए दे दे तो आधा खर्च रेल मंत्रालय दे देगा। अभी पता चला है कि रेल मंत्रालय मे अस्टिमेट तैयार हो चुका है तथा उस पुल के निर्माण पर लगभग 40 लाख रुपये लगेंगे। अगर राज्य सरकार 20 लाख रुपये रेल मंत्रालय को दे दे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पैसे को देने की व्यवस्था की जाये ताकि लोगो को रेलवे लाईन के पार आने जाने मे सुविधा हो सके। धन्यवाद।

श्री नफे सिंह (जुण्डला, एस0 सी0): सभापति महोदय, आपने मुझे डिमाण्ड नं0 2 पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वर्तमान सरकार ने चुनावो के समय बडे बडे वायदे लोगो से किए थे कि बेरोजगारो को पैट्रोल पम्प या गैस एजैन्सी के परमिट दिला देंगे, जुगाड के रेहडो को

लाईसैंस दिला देंगे, 24 घण्टे बिजली देंगे, 24 घंटे के अंदर टयूबवैल कनैक इन देंगे। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद बेराजगार युवको को रोजगार तो नहीं दिया लेकिन न गारबन्दी की आड में ट्रक और टैंकर भर भर कर नौजवान युवको से दारु बेचने का धंधा जरूर करवाया है जिससे लाखों रुपये उन बेरोजगार युवको ने गलत तरीके से बनाए। सरकार ने गाराब की आड में उन युवको को गलत रास्ते पर लगाया। सभापति जी, जब हरियाणा में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस में इनकी इतनी बुरी हालत हो गई। उसके बाद इनको गाराबबंदी को खोलने का काम करना पडा। इनकी नाक कटी हुई। (विधन) जहां तक बिजली की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आज लोग त्राहि त्राह कर रहे हैं। लोगो को बिजली मिलती नहीं है। दिन रात खेतों में लोग बिजली का इंतजार करते रहे हैं। आज हरियाणा में बिजली न आने की वजह से हर आदमी दुखी है। सभापति जी, पिछले सत्र के दौरान भी मैंने अपने हल्के की सडको को संबंधित एक सवाल किया था। मेरे हलके में बढोता से जुण्डला वाया खेडीनरु से पिचौलिया वाया जानी, नई सडके बननी थी लेकिन मेरे हलके का विपक्षी सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व करने की वजह से उस की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये गांव आज भी सडको से जुडे हुए नहीं है। सभापति जी, मेरे हलके में निसिंग और जुण्डला में पी0 एच0 सीज0 है। मैंने पिछले सत्र में भी एक सवाल किया था कि इन पी0 एच0 सीज0 की बिल्डिंगज की दीवारे गिर रही हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। मवे ती उन में घुमते हैं।

मैने कहा था कि उनकी दीवारे बनाई जाए लेकिन आज तक इस बारे में कोई गौर नहीं की गई है। इसी प्रकार से मेरे हलके में जुण्डला से बुढनपुर, खेडीनरु से करनाल, निसिंग से कतलाहडीवाा ओगंद, निसिंग से सांभली, निसिंग से गोंदर, जलमाना से रतक वाया उपलाना, जलमाना से उपलानी और जलमाना से ठरवा माजरा की सडको की इतनी बुरी हालत है कि इन में गढढे बने हुए हैं और इन पर गुजरने वाले व्यक्ति को यह फैसला करना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन से गढढे से होकर गुजरे जिससे कि सुरक्षित निकल जाएं। करनाल से श्री भागिपाल मेहता जी सदस्य हैं वे अब सदन में बैठे नहीं हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि करनाल भाहर में रेलवे ओवर ब्रिज और डब्ल्यू० जे० सी० के बीच में जो कैथल रोड है तथा करनाल में जो मेरठ रोड है, उनकी इतनी बुरी हालत है कि जब भी थोड़ी सी बूँदा-बूँदी हो जाती है तो ये सडके तालाब का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन सडको की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री रामफल कुण्डु (सफीदो): सभापति जी, सर्वप्रथम मैं अपने हलके से संबंधित दो मांगों पर बोलना चाहूँगा। एक तो मैं ड्रेन के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछले साल सरकार द्वारा 6-7 ड्रेनें स्वीकृत की गई थीं लेकिन आज तक एक ड्रेन पर भी कार्य भुरु नहीं किया गया है। बिटानी लिंक ड्रेन भी पिछले साल स्वीकृत की गई थी, लेकिन इन दो सालों में किसी भी नई ड्रेन

की खुदाई नहीं हुई है तथा न ही काम भुरु हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो ड्रेन स्वीकृत की गई थी, कम से कम उन पर तो कार्य भुरु करवा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ड्रेनो की खुदाई के बारे में है। बाहर के अंदर से एक सफ़ीदो ड्रेन गुजरती है, इसको बनाने की बात हुई थी। इसको आगे व पीछे से 700 फुट तो पक्का किया जा चुका है लेकिन बाहर में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है परिणामस्वरूप बाहर में पानी घुस जाता है। मेरी यह मांग है कि इस को खुदवाया जाये। जब तक वह ड्रेन पक्की न हो तब तक मेरी प्रार्थना है कि बाहर के अन्दर सफ़ीदो ड्रेन का जितना पोरान गुजरता है, उसको जल्दी पक्का किया जाये और जहां से उसकी खुदाई भुरु होती है, जहां पर ये टेल बनती है मैं इस बारे में अनुरोध करूंगा कि उस पर जो अवैध कब्जे हैं, उनको उठवाकर उस ड्रेन को खुदवाया जाए। इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि हांसी ब्रांच के साथ सफ़ीदो में जो डिच ड्रेन है, वह भी बन्द पडी है उसमें आज तक एक कस्सी मिटटी भी नहीं निकाली गई है। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि उस डिच ड्रेन की सफ़ाई का कार्य करवाया जाए। इसी तरह से बम्भेवा ड्रेन है उसमें इस साल सफ़ाई के लिए ट्रैक्टर लगए गए थे, उन ट्रैक्टर वालों की 35000 रु की पेमेंट बकाया है वह उस पेमेंट के लिए बार बार हमारे से कह रहे हैं कि आपके कहने के बाद हम उस कार्य में लगे थे लेकिन महकमा उनकी कोई पेमेंट नहीं दे रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि बम्भेवा ड्रेन पर कार्य करने की जो ट्रैक्टर वालों की पेमेंट रहती है, वह दी जाए। उस ड्रेन की खुदाई तो

कर दी लेकिन जहां रास्ते बंद थे और जो अभी वहां पाइप पडे है उन पाइपो का भी तक तक कोई फायदा नहीं जब तक उनके साइफन नहीं बन जाते। जब तक उन पाइपो को निकाल ठीक ढंग सं सैट नहीं किया जाता तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। ड्रेन खोदने से पहले रास्तो का होना बहुत जरूरी है। कई जगह ड्रेन की सफाई का कार्य दिखाया जाता है, ड्रेन की खुदाई दिखाई जाती है परन्तु आगे रास्ता ब्लाक होने की वजह से पानी आगे नहीं जा सकता। यह बात खास ध्यान रखने की है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बम्भेवा ड्रेन आगे िवाणा मोड से होकर जाती है उसमे मेरे खयाल से जमींदार 6-7 जगह बांध बनाकर, नाली बनाकर पानी अपने खेतो मे ले जाते है। कृपा करके उनके उन बांधो को वहां से खोला जाए। इसी प्रकार एक कालवा कैलाना ड्रेन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस साल तो कोई खास बरसात नहीं हुई है। लेकिन इस बार भी कालवा भराण गांव के खेतो मे पानी भरा हुआ है और जब हम ने उस पानी को निकालने के लिए मोटर लगाने के लिए कहा तो अधिकारी कहने लगे कि 15 सितम्बर के बाद ही मोटर दी जाएगी लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 15 सितम्बर तक तो फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं अनुरोध करुंगा कि आप हुक्म करे कि जिस एरिया मे भी पानी भरा हो उस वक्त उस पानी को निकालने के लिए मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रबंध किया जाए। यही हालात रजाणा कलां, रजाण खुर्द, बुढा खेडा, गावो के खेतो मे होती है। हमारे द्वारा चीफ इंजीनियर, डी0 सी0, एस0 पी0 से बार बार अनुरोध करने पर

वे मौके पर जरूर चले जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। ये आवासन देते हैं कि कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह से सभापति जी, बजट में नई नाला ड्रेन की खुदाई के काम पर खर्च दिखाया गया है। सफ़ीदो ड्रेन से नई नाला ड्रेन निकलती है उसका कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ है। यह बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि जब ये गठबंधन सरकार बनी थी तो बनते ही इन्होंने पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था लेकिन आज तक गवर्नमेंट कालेज, सफ़ीदो में पंजाबी के लैक्चरर की पोस्ट भी सैंक इन नहीं हुई है। जो बच्चे दाखिले के समय पंजाबी विषय लेना चाहते हैं, उनको मना कर दिया जाता है। मेरे इलाके में सरदार बहुत हैं वे पंजाबी पढ़ना चाहते हैं लेकिन उस कालेज में पंजाबी विषय की क्लासे न होने के कारण वे दाखिले से वंचित रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि वहां यह गवर्नमेंट कालेज सफ़ीदो में संस्कृत विषय की दो पोस्टें सैंक इन हैं और दोनों ही खाली पड़ी हैं। बच्चों को वहां पर इस भाँति पर एडमिशन दिया जाता है कि अगर संस्कृत का लैक्चरर आ गया तो पढ़ा दिया जायेगा वरना आपको ये सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 17 तारीख को गवर्नमेंट कालेज, जींद गया था। जो लड़के वहां 10+2 के बाद फसर्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए गए, उन में से कुछ लड़कों का एडमिशन करके यह कहकर आगे एडमिशन बन्द कर दिया कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। यह हालात सफ़ीदो के कालेज की हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति जी: यदि हाउस की सैन्स हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री सभापति: हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री रामफल कुण्डु:सभापति जी, मैं गवर्नमेंट कालेज सफ़ीदों में गया तो वहाँ मुझे यह कहा गया कि अगर आप लिख कर दें कि आप यहाँ पर लैक्चरर भिजवा देंगे तो हम बच्चों को एडमिशन कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर लैक्चरर भिजवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे इस तरह कहने के बावजूद भी लड़कों को एडमिशन नहीं दिया। फिर मैं दोबारा वहाँ गया तो फिर वे कहने लगे कि अगर आपके अपने हल्के के दो चार लड़के हैं तो बता दें हम उनका एडमिशन कर देंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो लड़के पढ़ना चाहते हैं उनको एडमिशन जरूर मिलना चाहिए और जो लड़के एडमिशन से वंचित रह गए हैं उनके लिए एडमिशन की डेट बढ़नी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को एडमिशन जरूर मिलना चाहिए। सभापति जी, अब मैं लड़कों के बारे में एक बात कहना

चाहता हूँ, जामनी अडडे से पील्लू खेडा मंडी तक की सडक की वाइंडिंग जरूर होनी चाहिए क्योंकि उस सडक पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लोड रहता है और उस सडक पर देहात के लोगो का बहुत आना जाना रहता है। इसी तरह से सफीदो से ले कर हाट गांव तक जो कम से कम 10-12 लिंक रोड जाते है, उस सडक के बारे मे मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस सडक की भी वाइंडिंग होनी चाहिए। जो भाहर के अंदर सडके है उनको बार बार अनुरोध करने के बाद भी ठीक नही किया गया है। चाहे वे सडक पीलुखेडा मंडी मे है और चाहे सफीदो में है। उन मंडियो की सडको के बारे मे मैने यह रिक्वेस्ट की थी कि उन पर कच्चा रोडा डाल दिया जाए ताकि वे सडके चलने योग्य हो जाए। मेरा अनुरोध है कि उन सडको को जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये। जो लिंक रोड है उन पर पैच लगा देते है ह पता नही लगता कि वह पैच मिटटी से लगता है या बजरी से लगता है या रोडे से लगता है। महकमे वाली सडको पर मिटटी डाल जाते है और उसका जवाब आता है कि पैच लगा दिया गया है। मे अनुरोध करुंगा कि उन सडको को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए। अब मे एग्रीकलचर मिनिसटर साहब से कहना चाहंगा कि खातला से लीकलाबाद और डउवाला से मलिकपुर जो मार्किट कमेटी की सडक है वह अधूरी पडी है उस सडक को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार पीलुखेडा मंडी से तलोडा गांव मे एक 66के0 वी0 का पावर हाउस लगा हुआ है उसको 132 के0 वी0 का अपग्रेड किया जाए। सभापति जी, कल मुख्य मंत्री जी ने सदन के

अंदर बिजली के बारे में काफी कुछ बताया था कि इतने ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे, इतनी लाईने चेंज की जाएगी लेकिन उसमें जींद डिस्ट्रीक्ट का कोई जिक्र नहीं था कि उस जिले की कहीं कोई लाईन बादली जाएगी या नहीं वहां के लिए कोई ट्रांसफार्मर खरीदा जाएगा या नहीं और न ही यह जिक्र किया गया कि वहां पर किसी पावर हाउस की अपग्रेडिंग की जाएगी या नहीं की जाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जींद जिले में बिजली देने का पूरा प्रबंध किया जाए क्योंकि जींद जिले के गावों में तीन-तीन दिन और चार-चार दिन तक बिजली नहीं आती है। सभापति जी, मैं एक बात और कहूंगा कि भूगर फ़ैडरे इन ने एक फ़ैसला लिया कि जींद भूगर मिल से साढ़े तीन करोड़ रुपये भूना भूगर मिल को दे दिये जाएं, लेकिन उस बारे में किसी सतेवान ग़ोवर नाम के आदमी ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया उसके बाद भूगर फ़ैडरे इन ने फ़ैसला लिया कि हम साढ़े तीन करोड़ रुपये वहां पर नहीं भेजेंगे। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने 11-7-98 को अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में यह फ़ैसला लिया कि हम हमारे क्रेडिट पर भूना भूगर मिल को यह लोन दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वह साढ़े तीन करोड़ रुपये जींद भूगर मिल से निकल गया तो वहां के कर्मचारियों के लिए और वहां के जमींदारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि भूना भूगर मिल के लिए सरकार पैसे का किसी और सोर्स से प्रबंध करे और जींद भूगर मिल से वह पैसा न निकाले। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पैसा भी किसी लिमिट के तहत वहां से

निकाला जाये। लेकिन मुझे पता चला है कि वह पैसा जींद भूगर मिल को गिरवी रख कर वहां से निकाला जा रहा है। सभापति जी, हमारे जिले के जो मंत्री है उनका भी इस बारे में फर्ज बनता है क्योंकि वे भी कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं यह बात उनके ध्यान में भी आनी चाहिए थी। सभापति जी, मैं अब एक और बात सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। जब यह बजट सै इन होता है तो यह हमें 11 फरवरी और मार्च के एंड में होता है इसलिए यह बजट बजट सै इन फरवरी मार्च के एंड में चलना चाहिए था। आज कल तो मानसून सै इन होता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि आइंदा सरकार इस बात का ध्यान जरूर रखे। सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा जब मैं सफीदो के गवर्नमेंट कालेज में गया तो मुझे पता लगा कि जिस किसी लडके का किसी एक सब्जैक्ट में कम्पार्टमेंट है और जो स्कूल से जाता है उसको तो एडमि इन मिल जाता है। जो लडका प्लस टू के स्कूल में दो सब्जैक्ट्स में फेल हो जाता है उसको एडमि इन नहीं मिलता है लेकिन जो लडका वोके इनल करके जाता है उसकी दा सब्जैक्ट में कम्पार्टमेंट होती है तो उसको एडमि इन मिल जाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए यह सुविधा स्कूल में पढने वाले बच्चों के लिए भी होनी चाहिए या प्लस टू वाले बच्चे को भी यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए उनसे भी वापिस ली जाए। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में जिक करना चाहूंगा। मैंने इस बारे में सफीदो के लिए एक क्वै चन भी किया था। हमारा सफीदो भाहर काफी पुराना है और वहां पर जो

सी० एच० सी० की बिल्डिंग है वह भी काफी पुरानी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सी० एच० सी० को सामान्य अस्पताल में बदला जाये। वहाँ की आबादी भी 30-35 हजार है। वहाँ पर इस वक्त न पोस्टमार्टम की सुविधा है और न एक्स-रे मीन है। मैं चाहूँगा कि सरकार वहाँ पर जरूरियात की सारी चीजे उपलब्ध करवाये।

सभापति महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर तीन चार महीने पहले एक पटवारी और कानूनगो 4 लाख 65 हजार 12 रुपए लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक मारुति कार में बदमाश आए और बंदूक की नोक पर वह सारा पैसा छिन कर ले गए। यह वारदात पीलू खेडा की है। वहाँ पर उन लोगों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं चाहूँगा कि सरकार उनको व्हीकल्ज उपलब्ध करवाये और साथ ही सिक्योरिटी का भी इंतजाम करे। इसी प्रकार से इसी महीने मैं इन बांटने के लिए मैं इन बांटने वाले 1 लाख 15 हजार रुपये ला रहे थे वह भी छिन लिया गया। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी गहराई में जाए और उनकी सुरक्षा व गाडी आदि की व्यवस्था करे।

सभापति जी, इसी प्रकार से सफीदो के अंदर 4 करोड रुपए अब तक अनाज मण्डी बनाने पर खर्च हो चुके हैं। मेरी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवा कर चालू करवाने की कृपा करे। धन्यवाद।

श्री औम प्रका 1 जैन (पानीपत): सभापति महोदय, आपने डिमांड पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। पानीपत भाहर एक प्राचीन भाहर है। मेरी कान्स्टीच्यूएंसी पानीपत भाहर है। यह एक औद्योगिक नगरी है। वहां से बड़ा भारी सामान एक्सपोर्ट होता है जिससे हमे फोरन एक्सचेंज प्राप्त होता है। वहां की म्यूनिसिपल कमैटी के लोग काफी परे ान है। जिसकी वजह से पानीपत भाहर का बहुत बुरा हाल है। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैली हुई है। वहां पर पानीपत म्यूनिसिपल कमैटी के जो चेयरमैन और दूसरे साथी हैं उन्होंने पानीपत भाहर की जमीन लूटा दी है। इस कमैटी ने यह जमीन लूटाते समय किसी की परमि ान नहीं ली चाहे वह सरकार की हो, डी0 सी0 की हो या खुद रैजोल्यु ान पास करके देने की हो, किसी की कोई एप्पुवल नहीं ली और न ही परमि ान ली। यह मामला वहां की ग्रिवेंसिज कमैटी के सामने भी आया। वहां की म्यूनिसिपल कमैटी के सामने भी आया। वहां की म्यूनिसिपल कमैटी ने पौने चार सौ प्लॉट जिनकी कीमत अरबों रुपयों में थी, मिट्टी के भाव बेच दिए। यदि वह इन प्लॉटों को ठीक ढंग से बेचते तो म्यूनिसिपल कमैटी को अरबों रुपया प्राप्त होता जिससे वहां की डिवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकती थी। उदाहरण के तौर पर मैं एक प्लॉट का जिक्र करना चाहता हूँ। यह प्लॉट चावला नाम के एक व्यक्ति को सस्ते भाव पर दे दिया गया। इसको देने से पहले न तो डी0 सी0 की परमि ान ली गई और न ही म्यूनिसिपल कमैटी ने स्वयं इसका रैज्योल्यु ान

पास किया। इस तरह से प्लाट देने के मामले में वहां पर बहुत भारी अनियमितताएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई कार्यवाही करे। सभापति महोदय, पानीपत एक औद्योगिक भाहर है। यहां पर उद्योग ज्यादा होने की वजह से यह भाहर पानीपत से काफी बाहर जाकर बस गया है, काफी बाहर तक फैल गया है। यहां से काफी माल बाहर भी भेजा जाता है इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि पानीपत भाहर की जो म्यूनिसिपल कमेटी है उस कमेटी की सीमा बढा दी जाये। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा बढाने से कमेटी की इन्कम भी ज्यादा होगी और भाहर का विकास भी होगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि इस म्यूनिसिपल कमेटी की सीमा बढा दी जाये। सभापति महोदय, पानीपत भाहर मे पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, पानी की जो सतह पहले खराब हो चुकी है जिसके कारण वहां पानी की समस्या बहुत गंभीर बनती जा रही है। सभापति महोदय, पिछली सरकार के वक्त में 8-10 ट्यूबवैल एम एल ए और एम पी की ग्रांट से वहां लगे थे। ट्यूबवैल तो लगा दिये लेकिन उनको चालू नहीं किया गया। सभापति महोदय, वे ट्यूबवैल चुनाव के वक्त लगाये गये थे, लेकिन बाद मे उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, इ बारे मे भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन ट्यूबवैल को चालू कराये ताकि पानीपत के लोगो को पीने का पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से अनुरोध करुंगा कि वे पानीपत की कुछ

बस्तियों में नये ट्यूबवैल लगवा दे ओर पीने के पानी का प्रबंध करे वरना पानीपत भाहर का पीने का पानी के मामले में बुरा हाल हो जायेगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे पानीपत भाहर भाहर में जी० टी० रोड पर एक हस्पताल है लेकिन उस हस्पताल की चार दीवारी टूटी हुई है जिसके कारण कुछ लोग वहां पर जबरन कब्जा करने में लगे हुए हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उस हस्पताल की चार दीवारी बना दी जाए ताकि कम से कम उस हस्पताल की जमीन की तो रक्षा हो सके। सभापति महोदय, पानीपत भाहर में पानीपत रैस्ट हाउस के सामने एक पुल है, वह पुल बहुत तंग है, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए उस पुल को दो तरफा बनाया जाये ताकि वहां से लोग आसानी से गुजर सके ओर एक्सीडेंट्स भी न हो। सभापति महोदय, इसमें कोई भाक नहीं है कि हरियाणा सरकार पानीपत में मिनी सचिवालय बनाना चाहती है, लेकिन जहां पर सरकार जमीन लेना चाहती है वह जमीन डिफेंस की है। जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री से वह जमीन नहीं मिलेगी तब तक पानीपत में मिनी सचिवालय नहीं बन सकता। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सचिवालय के लिए सैक्टर 11 या सैक्टर 17 में जमीन ले लें और वहां पर यह सचिवालय बनवा दें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि पानीपत में मिनी सैक्टरियेट जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अगर वहां पर जगह नहीं मिल पा रही है तो हुड्डा ने जो जमीन छोड़ी हुई है उसको ले लिया जाए ताकि डी० सी०, तहसीलदार या दूसरे

अफसरों के जो दफतर अभी तक अलग अलग जगह पर हैं वे सब एक ही छत के नीचे इकट्ठे काम कर सकें और लोगों को अपने काम करवाने के लिए कुछ राहत मिल सकें। मिनी सैक्रेटरी के इलावा हमारे यहां फ्लोअर ओवर बनाने की भी मांग थी परन्तु मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर फिलहाल फ्लोअर ओवर नहीं बन सकता है। मैं यह चाहूंगा कि वहां पर जो बाईपास बनाया जाना है उस बाईपास के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दिया जाए। सभापति महोदय, आपने मेरी डिमाण्ड को सुना (विधन) सभापति महोदय, आज जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उन्होंने किसी भी एम एल ए के कहने पर एक भी क्लर्क या चपडासी की भर्ती नहीं की, कोई सिपाही की भी भर्ती नहीं की है। जो भी क्लर्क, चपडासी या सिपाही भर्ती हुए हैं वे सब मैरिट के आधार पर सिलैक्ट हुए हैं किसी की सिफारिश पर उनका सिलैक्टेशन नहीं हुआ है। सभापति महोदय, इन भावों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (विधन)(इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री कृष्ण लाल (असन्ध, एस0 सी0): उपाध्यक्ष महोदय, हविषा और भाजपा की सरकार बनने के बाद करीब अठारह वर्षों के बाद आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं० 1 से लेकर 25 पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पावर के बारे में बोलना चाहूंगा। हविषा भाजपा सरकार बनने से

पूर्व खासतौर से हविपा ने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोशणाएं की थी कि हमारी सरकार आने के बाद 24 घण्टे गावों को बिजली मिलेगी, 24 घण्टे में बिजली का कनेक्टान मिलेगा, 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर रिप्लेस होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसान की क्या हालत है यह इस सरकार को ठीक प्रकार से पता है लेकिन सरकार वास्तविक तथ्यों को छिपाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जाता है। इस बारे में बिजली बोर्ड का कोई सकुलर नहीं है लेकिन अगर एक ट्रांसफार्मर पर 10 किसान आते हैं और उनमें से 2 ने बिल जमा नहीं करवाया तो उन बाकी के आठ किसानों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि वे मजबूर करते हैं कि उनसे बिल भरवाया जाए और जब तक बिल भरवाया नहीं जाता तब तक ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं होता है। क्या मुख्य मंत्री जी इस स्थिति में कोई सुधार करेंगे? (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से मुझे भी इस बार बोलने का मौका मिला है। (विधन) मेरा नाम तो लिस्ट में होता था लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आज जो बोलने का समय मिला है उसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब तक 10 के 10 किसानों का बिजली का बिल जमा न हो जाए तब तक उनको नया ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है। दूसरी बात स्पीकर साहब, डोमैस्टिक प्रणाली चालू की गई थी। सलैब प्रणाली में 1 से 40 यूनिट तक बिजली के चार्जिज 52 पैसा प्रति यूनिट, 41 से 80

यूनिट तक 62 पैसे प्रति यूनिट, 81 से 140 यूनिट तक 75 पैसे प्रति यूनिट और 140 से उपर एक रुपया प्रति यूनिट की इर से बिजली दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी कल कह रहे थे कि उन्होंने 6 लाख ऐसे बिजली कन्ज्युमर्स का पता लगाया है जिनको सरकार एक से चालीस यूनिट तक बिजली कम रेट पर सप्लाई करेगी। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा कौन सा सर्वेक्षण करवाया है? अध्यक्ष महोदय, अगर दो बलब और एक पंखा चले तो ये 40 यूनिट्स 10-12 दिन में ही कन्ज्युम हो जाते हैं सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वह बिल्कुल गलत दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या वह आदमी 10-12 दिन के बाद अपना मीटर बंद कर देगा? वैसे तो हरियाणा में बिजली आती ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज हविपा और भाजपा गठबंधन की सरकार हो, हमारे से पहले और अब तक 15-20 सालों में किसी ने भी बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया है। मैं यह रिकार्ड की बात बता रहा हूँ। 1997 में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे। तब ही पानीपत के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट नम्बर 1 और 2 का काम शुरू हुआ था और 1997 के अन्दर इन यूनिट्स ने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। इस समय के मौजूदा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने आकर के पानीपत के थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का उद्घाटन किया था। कुछ समय के बाद दूसरे यूनिट ने भी प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार से वहाँ का जो पांचवा यूनिट है उसका 1987 में काम शुरू हुआ था। इस बारे में मुख्य मंत्री जी उद

माना है कि अगर कोई प्लांट का काम भुरु हो तो उसको कम्पलीट होने में तीन साल लग जाते हैं। 1987 में वह काम भुरु हुआ था और 1990 में उस प्लांट ने प्रोडक्शन देना भुरु कर दिया था। यह रिकार्ड की बात है कि उस टाइम के इम्पलाईज को इन्सैंटिव भी मिला था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक छठे युनिट की बात है, इसके लिए 1989 में चौधरी देवी लाल जी के समय में 159.6 करोड़ रुपये के वर्क के आर्डर किए गए थे। मुख्य मंत्री जी ने कल अपने जवाब में भी इस बात को माना है कि 80 करोड़ रुपये का सामान आ चुका था और वह रेलवे स्टेन पर पड़ा रहा। हमारी सरकार पने जाने के बाद कांग्रेस की जो भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार आई थी उसने उस सामान को नहीं छुड़वाया। उस पर डैमरेज पड़ता रहा। उसके बाद उसके रख रखाव के लिए बी उच इ एल ने दो करोड़ रुपये मांगे थे। अध्यक्ष महोदय, वह सामान डैमरेज हो जाएगा। कुछ सामान मिट्टी में पड़ा है और कुछ रेलवे स्टेन पर पड़ा है। लेकिन उस सरकार ने उस सामान को नहीं छुड़वाया था। अध्यक्ष महोदय, छठे युनिट का काम 100 प्रतिशत भुरु हो गया था। आज यह सरकार केवल वहां से पानी निकलवा रही है। स्पीकर साहब, इतना ही नहीं चौधरी देवी लाल जी ने अपने भासनकाल में जितने भी बिजली के उपभोक्ता थे, उनको 24 घंटे बिजली दी थी। लेकिन इन जनाब की सरकार के वक्त में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद बिजली का निजीकरण करने की बात आई। एच बी पी और बी जे पी की सरकार इसके लिए दोषी है। वैसे इसके लिए कांग्रेस की सरकार

भी दोशी है। 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नीरा नाम की अमरीकन कम्पनी को दो करोड रुपए देकर इस बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई थी। बिजली का निजीकरण कांग्रेस पार्टी भी करना चाहती थी और इसके बाद इस सरकार ने भी बिजली का निजीकरण किया है जो कि प्रदेश के हित में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद चाईना से 5 लाख बिजली के मीटर मंगवाए गए। ये मीटर घरों में लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे बिजली बोर्ड की वर्क गैप में बहुत से मीटर पड़े हुए हैं लेकिन इन्होंने चाईना से मीटर मंगवाने पर पैसा खर्च किया है उस पैसे से वर्क गैप में पड़े मीटरों को रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तो मौका देखती है कि किस कम्पनी से पैसा मिल सकता है और कहां कहां से पैसा मिल सकता है ताकि उसके साथ सौदा किया जा सके। अब मैं पी0 डबल्यू0 डी0 की बात करना चाहता हूँ। मेरा असंध हलका है वहां पर 1993 में भी और 1995 में भी फलड आया था। दोनों बार मेरा हलका फलड की वजह से अफैक्टिव हुआ था। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त में हम और आप अपोजीशन में बैठते थे। हमने पूरे रुकके मार मार कर अपनी बात कही थी लेकिन उस वक्त भजन लाल जी ने हमारी बात नहीं सुनी और इसी तरह से आज हविषा और भाजपा की सरकार भी हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अध्यक्ष महोदय, 1993 और 1995 में दो बार फलड आने के कारण आज तक मेरे हलके में जितनी भी रोड्स टूटी हुई थी, वे रिपेयर नहीं हुई हैं।

सरकार यह बताए कि मेरे हलके में नई सड़कें और जिन सड़कों पर पैच वर्क किया है, उन पर अब तक कितना पैसा खर्च किया गया है? स्पीकर साहब, असंध एक सब डिविजन है सरकार इस बारे में सर्वे करवाए। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां की सड़कों को ध्यान में रखकर उनकी रिपेयर करवाए। स्पीकर सर, एक समय वह था जब देवीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और यदि उस समय ओलावृष्टि होती थी तो किसान से पहले चौधरी देवीलाल उसके खेत में नजर आते थे और एकदम घोशणा कर देते थे कि इतना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। इसी तरह स्पीकर सर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। असंध में जो कि सब डिविजन है, न ही कोई 10+2 का स्कूल है और न ही वहां पर कोई कालिज है, न ही वहां पर कोई पोलिटैक्नीक कालेज है। वहां पर सब डिविजन होते हुए भी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार ने पहले कहा था कि अगर आप वहां पर जमीन उपलब्ध करवा दें और दो तीन कमरे बनाकर दें तो हम वहां कालेज खोलने की मंजूरी देंगे। लेकिन हम तो जमीन देने के साथ साथ कालेज की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा भी देना चाहते थे इसलिए अब सरकार को वहां कालेज मंजूर कर देना चाहिए। स्पीकर साहब, सतलौडा गांव है लेकिन वहां पर भी बीस की.0 मी.0 तक कोई स्कूल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आप वासन दिया था कि आप अढाई एकड़ जमीन दें और दो कमरे बनाकर दें तो हम वहां के स्कूल को अपग्रेड कर देंगे। हम सरकार को जमीन भी देने को तैयार हैं और चार कमरे भी बनाकर देने को तैयार हैं

लेकिन आज तक भी सरकार की तरफ से कोई जवाब इस बारे में नहीं आया है। इसके अलावा मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे वहां सैंट परसैंट फसल खराब हो गयी थी। उस समय इन्होंने पम्प तो लगावाए थे लेकिन चार पांच ड्रेने ऐसी हे जिनकी सफाई नहीं हुई। ये ड्रेने बारि 1 के साथ ओवर फलो हो जाती है। इन गावों में पूरी कनक की फसल बर्बाद हो गयी थी और बिजार्ड भी नहीं हुई थी। कंवल सिंह जी, जो ग्रिवेंसिज कमेटी के चेयरमैन थे, के सामने लोग पे 1 हुए थे और उन्होंने यह समस्या इनके सामने रखी थी तब इन्होंने इरीगे 1न डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आदे 1 दिया था कि इन ड्रेनों की सफाई करवायी जाये। लेकिन इनके कहने के बावजूद भी उनकी सफाई नहीं हुई। स्पीकर साहब, मंत्री जी आदे 1 दे और फिर भी काम न हो तो फिर कैसे किसानों का काम चलेगा? इनके आदे 1 के बाद भी डिपार्टमेंट ने वक काम नहीं किया। स्पीकर साहब, अब मैं वन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। वन विभाग के अंदर बहुत धांधलियां हुई हैं। अब सरकार प्लांटे 1न की बात करती है तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि प्लांटे 1न करने के लिए जो अढाई या तीन फुट गडडे खोदने चाहिए, उनके बजाए वे आधा फुट ही गडडे खोदते हैं। इन गडडों में 19 किलो मैटीरियल जैसे गोबर आदि आना चाहिए लेकिन वे इतना मैटीरियल नहीं डालते हैं और ऐसे ही प्लांटे 1न करते हैं। उस गांव के लोगों ने करीब 500 या 600 एकड जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां पर 400 एकड जमीन पर प्लांटे 1न हुई थी लेकिन उसको उन्होंने

डिमोलि 1 कर दिया है। वहां एक हफते के अंदर ही 500 या 600 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। स्पीकर साहब, पूरे प्रदेश 1 के अंदर ऐसा ही हाल है। मैं मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उनको इस प्रकार के नाजायज कब्जों को तुरंत रोकना चाहिए। सर, इसी तरह से मैं अब स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। इस विभाग का भी बहुत बुरा हाल है। सारे प्रदेश 1 में पी0 एच0 सीज0 और सी0 एच0 सीज0 का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। मेरे गांव के अंदर ही एक पी0 एच0 सी0 हैं सरकार ने पहले आवासन दिया था कि उसकी चारदीवारी और उसके अंदर मिट्टी भर दी जाएगी लेकिन आज तक भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से बारिश 1 के दिनों में वहां पर पानी भर जाता है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से जो रुरल एरियाज के अंदर पी0 एच0 सी0 या सी0 एच0 सी0 हैं वहां पर पूरे प्रदेश 1 में कोई भी लेडी डाक्टर नहीं है। अगर इनमें दूसरे डाक्टर भी हैं तो वहां जाते नहीं हैं इसलिए मंत्री जी को इस बारे में तुरन्त ध्यान देना चाहिए। सर, अगर आप चाहे तो पूरे प्रदेश 1 में इस बारे में सर्वे करवा ले कि क्या कोई डाक्टर हैडक्वार्टर में नटेन करता है या नहीं? गांववासियों को इससे बड़ी भारी दिक्कत होती है। इसके बारे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह आवेक यह कार्यवाही करे। (विधन) दूसरी बात मैं परिवहन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। जो रोडवेज के रुट्स पहले चलते थे, वे प्राइवेटाइजेशन करने के बाद बंद कर दिए गए हैं। बाद में इन रुटों पर प्राइवेट बस चलती थी। प्राइवेट ओपरेटर जितने पैसे

कवर करना चाहते थे, वे कर नहीं पाए तो अपनी मर्जी से उनहोने रुट चेंज कर लिए। अब रोडवेज वाले कह रहे हैं कि वहां प्राइवेट बसे चल रही हैं इसलिए हम इन रुट्स पर बसे नहीं चला सकते। इससे सवारियों को बड़ी भारी परेशानी का सामान करना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप कोई ऐसे रुट्स बताएं जहां पहले रोडवेज की बसें चलती थीं और प्राइवेटाइजेशन के बाद वह बंद हो गईं हो?

श्री औम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, एक रुट पर तो जनरली ऐसी परिणामकारी है।

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर सर, छोटे छोटे रुट्स पर तो ऐसा आम हो रहा है। इससे सवारियों को बड़ी भारी दिक्कत है।

श्री विरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कानून में यदि इस तरह की कोई कमी है तो उसके लिए ये अमैडमेंट लेकर आए। इससे लोगों को बड़ी परेशानी है। वह रुट जो 25-25 किलोमीटर वाइटल प्वायंट पर जाकर मिलते हैं वहां से उन्होंने अपनी बसें विदर्रा कर ली। वहां पर अब कोई बस नहीं चला सकता क्योंकि कोर्ट ने इस बारे में स्टैट दिया है इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।

बागवानी एवं विपणन राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह मलिक): यह कब से है?

श्री धीर पाल सिंह: यह लास्ट ईयर से है।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर सर, अब मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। हाउस में हर रोज पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर की ओर से यह कहा जाता है कि हर एक गांव में पीने के पानी का कनेक्शन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूनक खेडी मेरे हलके का एक गांव है वहां आज तक वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है। इसी प्रकार से डेरा फूला सिंह, डेरा गुजराखियां, डेरा पंढोरिया जोकि सिखो के डेरे हैं, वहां भी वाटर सप्लाई के लिए कोई प्रबंध नहीं है। जो पानी ये दे रहे हैं उसके भी हमने कई गांवों के सैम्पल भरे हैं। उसमें पाया गया है कि पानी चाहे कैनल से आता है या पम्प से आता है उसमें ये डोजिंग पम्प नहीं लगाते जबकि इनको डोजिंग करनी चाहिए क्योंकि प्रदेश के लोगों को पीने को पानी अच्छा मिल सके। (धंटी) अब मैं सहकारिता विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो कि आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा विभाग है। मेरे से पहले बोलने वाले साथी ने कहा था कि एम0 सी0 एल0 बनने के बाद चाहे किसान है या गरीब आदमी है जो ऐप्रोच करवा लेते हैं तो लोन मिल जाता है दूसरों को नहीं मिलता है इसलिए इस पर सहकारिता मंत्री विशेष ध्यान दें। हमें आम लोग को अधिकार देना चाहते हैं यह बहुत भारी समस्या है इसको सिरियसली लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात है, मेरे हलके के एक मंगतराम नाम के आढती से थाने से 100 मीटर की दूरी पर 85 हजार रुपये दो मोटर साईकल सवारो ने छिन लिये। आज तक पुलिस द्वारा उनको पकडने के लिए कोई प्रयास नही किये गए है। इसी प्रकार एक वकील श्री सतपाल त्यागी की कार छीन ली गई जिसका आज तक कोई अता पता नही है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत एक औद्योगिक भाहर है जिसके साथ यू0 पी0 का एरिया लगता है। पानीपत भाहर मे माल को लाने के लिए बाहर से लोग आते जाते है क्योंकि पानीपत मे हैंडलूम का काफी मात्रा मे होता है जिसका एक्सपोर्ट भी होता है। इस प्रकार की वारदाते पानीपत भाहर मे काफी मात्रा मे होती है। समाचार-पत्रो मे भी आपको सप्ताह मे दो चार वारदाते पानीपत की ही मिलेगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि पानीपत भाहर की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिती की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि व्यापानी लोग अपना धंधा ठीक प्रकार से कर सके। धन्यवाद।

श्री रेलूराम: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने का समय दें।

श्री अध्यक्ष: रेलूराम जी बैठिये, मैने सभी सदस्यो को आ वासन दिया था कि जिस भी माननीय सदस्य को बोलने के लिए समय नही मिला है, उसको बोलने के लिए समय अव य दिया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended for one Hour.

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Time of the sitting is extended for one hour.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि पिछली सरकार ने ये प्राइवेट बसों के रूट्स परमिट दिये थे। उनमें से कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन पर लोगों को दिक्कत है, परिवहन मंत्री यह इंग् योर करायें कि जो प्राइवेट रूट्स दिये हुए हैं यदि प्राइवेट बसें वहाँ पर नहीं चलती हैं तो उनके परमिट कैंसिल किये जायें तथा वहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें चलाई जायें ताकि वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत न हो।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): जैसा कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की जिज्ञासा है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस संबंध में कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई हुई है जिसमें चौधरी मनीराम गोदारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मैं भी उस सब कमेटी में हूँ। हमने काफी एक्ससाईज की है और जो सुझाव

चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने दिये हैं, उनको भी हम एग्जामिन कर लेगे तथा जो भी इंकारपोर्ट होगा वह हम अव य करेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेकर आये और सारे मुद्दे उसमें होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: बीरेन्द्र सिंह जी, इस बारे में सब कमेटी बनी हुई है और उसमें सारी बातें एग्जामिन हो रही हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो स्टेट सब्जैक्ट है इस पर तो सरकार अपनी पॉलिसी लेकर आ सकती है कि प्राइवेटाईजेशन की क्या पोजीशन है, कितने रूटों का निजीकरण करेंगे, कितने रूटों को छोड़ेंगे ताकि लोग कोर्ट में न जायें। लोग कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि उनके परमिट कौंसिल न हो। लेकिन इन बातों ने लोगों को परेशानी में जरूर डाल रखा है। इम्पोर्टेंट रूट्स पर तो बसें चलती नहीं हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जो सब कमेटी बनी हुई है वह सभी बातों को ध्यान में रखकर रूटों के मामले को एग्जामिन कर रही है और जा भी सब कमेटी की रिपोर्ट होगी वह हम एक महीने के अंदर इस महान सदन में प्रस्तुत कर देंगे।

श्री सूरजमल: अध्यक्ष महोदय, कुछ रूट्स खाली पड़े हुए हैं वहां पर प्राइवेट बसों वाले नहीं चलते जिसके कारण सुबह और शाम स्कूली बच्चों को काफी मुश्किल का सामान करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन रूटों पर हरियाणा रोडवेज की

बसे सुबह और भाम चलाई जाये ताकि बच्चो को आने जाने मे तकलीफ न हो ।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि प्राईवेट रुट्स वालो ने कोर्ट से स्टे ले रखा है, इसलिए उन रुट्स पर रोडवेज की बसे नही चलाई जा सकती है ।

श्री बीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी) अध्यक्ष महोदय, मै वर्ष 1998-99 की बजट अनुदान मांग सं० 2 से लेकर 25 पवर बोलना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलने के लिए 15 मिनट मिलेंगे ।

श्री बीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत देंगे तो मै बोलूंगा । नही तो मै 6 दिन से यहां पर बैठा हुआ हूं और बोला नही हू । सर, सबसे पहले तो मै बिजली के बारे मे बोलना चाहूंगा । जैसे कि कल मंत्री महोदय ने बताया कि बिजली का हम ने काफी सुधार किया है । जहां तक बिजली के सुधार की बात है, मै कहना चाहूंगा कि अगर कोई लोन देने वाली कंपनी इस सुधार को बताती है, या सरकार की प्रोत्साहना करती है तो इससे बडी बात सरकार के लिए नही हो सकती है । किसी प्रदेश की जनता के हितो की अनदेखी करके ही किसी लोन देने वाली संस्थान को खुलासा किया जा सकता है । इसलिए इस बात से जाहिर होता है कि बजट के अंदर जो आंकडे प्रोत्साहित किए गए है, वे जनहित मे नही है तथा जनता की समस्याओ की तरफ कोई

ध्यान नहीं दिया जाता है। ये प्रॉप्स करने वाले अगर गांव में जाकर इन लोगों की प्रॉप्स करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि न तो प्रॉप्स करने वाले और न ही सरकार के ये आदमी वहाँ से सुरक्षित वापिस आ सकते हैं क्योंकि बिजली का गावों में इतना बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बजट नहीं बल्कि कर्जों का लेखा-जोखा है। इसमें कम से कम यह तो बताया जाना चाहिए था कि हरियाणा प्रदेश की जनता पर कितने करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ाया गया है और प्रतिदिन उनसे कितने करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। यह भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार सिर्फ कर्ज लिए जा रही है और इन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, इस बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिस हिसाब से कर्ज लेकर यह सरकार खुद हो रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि यह वर्ष 1998-99 का बजट नहीं है बल्कि यह आने वाले उन सभी सालों का बजट है, जब तक यह सरकार रहेगी। सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसिज की भाँति बेधडक होकर मान रही है। अगर ऐसा होता रहा तो यह वास्तविक बजट न होकर उन लोन देने वाली एजेंसिज का बजट ही कहा जाएगा। इस बजट में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

पिछले दो सालों से नौजवानों को बहकाया गया। जिस वक्त प्रदेश में भाराबबंदी लागू थी तो लोगों को भाराब की स्मगलिंग करके पैसा कमाने की छूट दे रखी थी। वह अब बंद तो

हो गई है लेकिन आज उन लोगों के पास हथियार भी हो गए हैं और पैसा भी हो गया है। आज उनकी वह नाजायज आमदनी बंद हो गई है। आज सभी पढ़े लिखे नौजवान अपराध कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा? वह पढ़ा लिखा है, ताकतवर है, उस में जो भी है। वह सरकार की कमियों के कारण दुखी होना पसंद नहीं करेगा बल्कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा। तो वह चोरी करेगा, डाका डालेगा, कत्ल करेगा और दूसरे सभी अपराध करेगा। इसलिए सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि इन अपराधों को रोके। आज नौजवानों को रोजगार नहीं दिये जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की बात तो दूर रही, जो रोजगार के पुराने साधन थे, उन में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जहां तक अध्यापकों की बात है, आज प्रदेश में 6500 के करीब तदर्थ अध्यापक लगे हुए हैं। 1988, 1991, 1994 व 1996 में जिन कर्मचारियों की दो साल की सर्विस हो गई थी, उन की सर्विस नियमित कर दी गई थी लेकिन आज इन अध्यापकों को नियमित न करके उनकी छुट्टी की जा रही है। कुछ कला अध्यापकों को हटाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हालात यह हैं कि एक तरफ तो अध्यापकों को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ नए अध्यापकों से अधिक होने पर भी उनको रेगुलर नहीं किया जाता बल्कि ये नए अध्यापकों की भर्ती की बात करते हैं। इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए इस प्रकार के भ्रष्टाचार को

बढावा दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, उसी तरह दूसरी भर्तियों में भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर चारों तरफ आग लगी हुई है। किसानों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। व्यापारी परेशान हैं और सारे-सारे कर्मचारी आन्दोलन में हैं। लेकिन सरकार खुश होकर, चुटकी ले लेकर यह कह रही है कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। आज तक पूरा प्रदेश जल रहा है और ये हंस रहे हैं तथा विपक्ष के विरोधी सदस्यों के ऊपर ताने-कस रहे हैं। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि यह जो वित्त मंत्री की बजट स्पीच है इस में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें काफी फर्क है। इस हाउस के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जनता के हित में नहीं लेकर ऐसे ढंग से लिया जाता है कि एक-एक करके हर नेता सत्ता का गुलाम बनता जा रहा है। यह सरकार कोई जनहित के कार्य नहीं कर रही। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। जहाँ तक किसानों की बात है सरकार ने खुद माना है कि नवम्बर, दिसम्बर 1997 और जनवरी 1998 में 111.57 लाख टन अनाज पैदा किया गया। बरसात के कारण जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी पंजाब सरकार ने उन किसानों को फसलें खराब होने का मुआवजा दिया। दिल्ली में भी इसी तरह का मुआवजा किसानों को दिया गया लेकिन हरियाणा सरकार ने एक नया पैसा भी नहीं दिया। हरियाणा का किसान कहाँ जाए? जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

आज देा की जो सबसे बडी समस्या है जो देा के सारे संसाधनो को निगलती जा रही है, वह है जनसंख्या वृद्धि की। इस बजट के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के उपर कोई ध्यान नीह दिया गया। एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने समय की हाई कमान को खुा करने के लिए, इंदिरा गांधी को खुा करने के लिए इस प्रदेा के लोगो पर अत्याचार करवाए लेकिन उसके बाद हटकर इन्होने दोबारा ऐसा काम करने का नाम नही लिया। इसका मतलब यह नही कि वह मुद्दा गलत था। वह मुद्दा ठीक था। समस्या उस समय भी थी और आज समस्या उससे भी ज्यादा बढी हुई है लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नही है। सरकार ने बजट मे भी इसके लिए पैसे का कोई प्रावधान नही किया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वह सरकार के संरक्षण मे पनपता जा रहा है। मेरे पास ऐसे उदाहरण है जहां मुख्यमंत्री को एफीडेविट दिया गया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई। आयुर्वेदिक विभाग मे वहा के डाक्टर ने बंगलौर बेस्ड फर्म से पेटेण्ट मैन नामक दवाईयां 25 लाख रु की खरीदी। जबकि यह परम्परा रही है कि यह दवाई मुिकल से 10 प्रतिात खरीदी जाती है। वहां 80 लाख रुपये की दवाईयां खरीदी गई, 34 लाख रु की दवाईयां खरीदी गई जिसमे से 25 लाख रुपये की डायफोन नामक दवाई खरीदी गई जो डायरिया और डायसैन्टरी के ईलाज के लिए इस्तेमाल होती है। उस बारे मे एफिडेविट देने के बावजूद मुख्य मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नही की है। उस कम्पनी ने स्पष्ट लिखा है कि:-

“That medicine having the same component and in same quantity, I am ready to supply to your department on 8 lacs rupees only which is less than 16 lacs.”

He further stated-

“(a) Whether this medicine has been demanded by Govt. Ayurvedic College Hospital or Ayurvedic Dispensaries functioning in the State of Haryana.

(b) Whether the ratio of Diarrhoea and other diseases patients of 1997 has been collected before sending the proposal to the Govt. for the purchase of this particular medicine in such a huge quantity being used to cure only Diarrhoea patient.

(c) That 1/3 of the total budget has been spent i.e. 24 lacs, to purchase this medicine and how to provide the other medicines to cure the patients of other diseases in the State.

(d) In the year 1996-97 the medicine to cure the Diarrhoea and Dysentery was purchased only with the cost of less than one lac whereas now spent the 25 times more money on the medicines of these diseases without any justification.

(e) That the medicine namely Diacone had never been purchased by the department. Now which circumstances has compelled to purchase such a huge quantity of this medicine at one time which has never been used before this year by this department}

स्पीकर साहब, इसके अलावा न गामुक्ति कैपूल और टेबलेटस खरीदे गये। उनके बारे में भी सरकार इन्कवायरी कराए। न गामुक्ति कैपूल और टेबलेटस पांच लाख रुपये के खरीदे गए लेकिन वे चार गुणा ज्यादा रेट पर खरीदे गए। इनको खरीदने के लिए जो लाएस्ट रेट कोट किया गया था, वह 315 रुपये प्रति हजार कैपूल और 135 रुपये प्रति हजार कैपूल था लेकिन खरीदे गए 1080 रुपए प्रति हजार कैपूल और 930 रुपये प्रति हजार टेबलेटस। इनके बारे में जिन चार पांच फर्म्ज का लोएस्ट रेट था, उसको इग्नोर करके ये दवाईयां खरीदी गईं। कहां 315 रुपए प्रति हजार का रेट और कहां 1080 रुपये प्रति हजार का रेट यानि 8-9 गुणा ज्यादा रेट दिये गए। इसी तरह से स्पीकर साहब, एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट में हर ब्लॉक के अन्दर दवाईयां खरीदी गईं हैं। एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट में दवाईयां खरीदने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की दवाईयो की कीमत के बारे में जो सैंकॉड लिस्ट है और उन कंपनज की जो प्राइस लिस्ट है उनकी अनदेखी की गईं हैं यानि एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट में 6-7 गुणा ज्यादा रेट पर दवाईयां खरीदी गईं हैं। उस डिपार्टमेंट के हर ब्लॉक के अन्दर हर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा वे दवाईयां खरीदी गईं हैं। इसलिए उस विभाग के हर ब्लॉक के अंदर करोड़ों रुपये घपला हुआ है। सरकार इस बारे में इन्कवायरी कराए।

अब मैं सडको के बारे में कहना चाहूंगा और खास करके अपने हल्के बेरी की सडको के बारे में कहना चाहूंगा। आज

तक मैंने जितनी सड़को की चर्चा की है उन सड़को को बनवाने के बारे में मंत्री जी ने हां भरी है और कुछ सड़को पर काम भुरु भी किया गया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस सड़क को बनाने का काम जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी दूसरी सड़क को बनाने का काम भुरु न किया जाए क्योंकि एक सड़क पर रोड़ी डाल दी जाती है और उसको छोड़ कर दूसरी सड़क का काम भुरु कर दिया जाता है। यदि किसी सड़क पर मिट्टी डालने का काम कर दिया है तो उसको पूरा करने से पहले ही दूसरी सड़क को बनाने का काम भुरु कर दिया जाता है। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अपने हल्के की बात कह रहा हूँ। मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। स्पीकर साहब, एच० आर० डी० एफ० ने गवर्नमेंट को ग्रांट लोन दिया था। उस पैसे से सरकार ने किसी भी अपोजी इन के विधायक के हल्के में आज तक कोई सड़क नहीं बनाई। उस पैसे से सारे के सारे काम सत्ता धारी पार्टी के विधायको के हल्के में हुए। हम किसी अधिकारी से जा कर किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वह अधिकारी कहता है कि आप तो विपक्ष के विधायक हो, इसलिए आपके इलाके में सड़क नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सरकार की तरफ से वर्बल हिदायतें हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं रेलेवैन्ट बोल रहा हूँ। (घंटी) मैं अपने हलके की समस्या बता रहा हूँ। नाबार्ड से सड़के बनाने के लिए 22 करोड रुपये सैंक इन हुए हैं। पता चला कि इन 22 करोड रुपये से जो 25 सड़के बननी है उनमें से अकेले 22 सड़के भिवानी में बनायी जायेंगी। यदि यह सही बात

है तो यह बिल्कुल गलत होगा। मैं चाहूंगा कि ये सडके सारे हरियाणा में बराबर बनाई जायें। अध्यक्ष महोदय अब मैं गुरु जम्हे वर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलना चाहता हूँ *****

Mr. Speaker: What is being said now by Shri Virender Pal is not to be recorded. Please take your seat, now?

श्री रेलू राम: स्पीकर साहब, इस दो साल के अर्से में मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जो भी बात कहूंगा, वह अन्दर की आयेगी, बाहर की नहीं आयेगी। अब तक पढ़े लिखे सदस्य बोले हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ लेकिन जो बात कहूंगा वह सही कहूंगा। यहां पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा में कुछ घरेलू झगडों की वजह से या जहरीला दवाई आदि खा कर मर गए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि वो क्यों मरे? हमारी स्टेट में ये चीजे होती जा रही हैं। आज हमारी स्टेट में नौकरियों के लिए छोकरो से पैसे लिये जाते हैं। जो मंत्रियों के वर्कर हैं या जो उनके एजेंट हैं, वे गांवों में घुमते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम पैसे का प्रबन्ध कर लो हम नौकरी लगवा देंगे। गांव के लोग नौकरी के चक्कर में पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं और अपनी औरत की टूम गिरवी रखते हैं। ऐसे काम करके पैसे लोगो ने दिया। कुछ तो नौकरी लग जायेंगे और कुछ रह जाएंगे। जो रह जायेंगे उनके बूढ़े बाप कहेंगे कि मैंने तेरे को पढ़ा लिखा दिया और ब्याह दिया। एक आध किल्ला जो उसके हिस्से का आएगा दे देगा और कहेगा कि तु अब कमा और खा।

लेकिन जिसके पैसे गए हैं वो उनको लेने के लिए इधर उधर के चक्कर काटेगा। जिसको पैसे नहीं मिलेंगे वह अपनी बहू को कहेगा कि ला अपनी टूम दे दे मैं दिल्ली जा कर और नौकरी देख लूंगा। फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती। अब फिर वह आढती की दुकान पर बैठता है। आढती सोचता है कि चौधरी का लडका आया है वह दो चार दिन उसको चाय पिलाएगा फिर उससे वह छुटकारा चाहता है। फिर वह लडका किसी चाय की दुकान पर बैठेगा चाय वाला भी दो चार दिन सोचेगा कि यह तो रोजना आकर बैठ जाता है। बेकार है, वह भी उससे पीछा छुडवाना चाहेगा। उसके बाद वह वापिस घर आकर रहता है। वह दुखी होकर या तो फांसी खाएगा या जहर खाएगा या बीमार हो जाएगा। उसके बाद आस पडोस के लोग उसको डाक्टर के पास ले जाते हैं। डाक्टर से अपने लडके का ईलाज करवाने के लिए किसान अपनी बची हुई जमीन भी गिरवी रख देता है। किसान के सारे पैसे डाक्टर ले लेता है लेकिन उसका लडका फिर भी मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, उस गरीब आदमी के पास न तो जमीन रहती है और न ही लडका। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी कहते थे कि हम 6 महीने के अंदर 24 घंटे बिजली दे देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक हरियाणा में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसान को अपना बिल ठीक करवाने में 2-3 दिन या इससे भी ज्यादा दिन लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने दिन किसान को बिजली का बिल ठीक करवाने में लगते हैं उतने दिन के किसान

को पैसे मिलने चाहिए। सरकार को दिनों के हिसाब से किसान को पैसे देने का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि बिल में तो 100 रुपये, 200 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये ही कम होते हैं। जबकि किसान के इस काम में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके 2-3 दिन का काम रुक जाता है जिससे उसको इससे कहीं ज्यादा नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, एक किसान अपने सिरी को 20 किलो बीज देता है और कहता है कि इस 20 किलो बीज की 20 किल्लो में बिजाई कर दो लेकिन वह सिरी 18 किलो बीज बेच देता है और केवल 2 किलो में बिजेगा तो उन किल्लो में फसल नहीं उगेगी बल्कि घास उगेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव है कि यह सरकार भी उस सिरी की तरह काम कर रही है। उस पर 50 पैसे भी नहीं लगते हैं सारा पैसा खा जाते हैं। (विधन एवं भाोर) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पर 3400 करोड़ रुपए का भार पडा है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष: रेलू राम जी, आप बैठ जाइये। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री रेलू राम: अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। (घंटी) एक बात मैं चौधरी जगन्नाथ जी के महकमे के बारे में भी कहना चाहूंगा (घंटी) अगर इनके महकमे में कोई काम करवाना हो तो 2% जे0ई0, 2% एस0 डी0 ओ0 और 2% एक्सीयन को दिया जाता है यह पैसा पूरा मिलेगा या नहीं, यह

भी सरकार बताने की कृपा करे। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डिमाण्ड नं० 4 पर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सन् 1986 में जब मैं रैवेन्यू मंत्री था और चौधरी साहब मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी यह सोचा गया था कि किसानों के लिए पास बुक्स बनाई जाएं। 1991 में रैवेन्यू डिपार्टमेंट फिर मेरे पास था। उस समय भी किसानों के लिए पास बुक का केस फिस भुरु हुआ था और पहली नवम्बर 1993 से रोहतक से इनका डिस्ट्रीब्यूशन भुरु होना था लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस कारण से उस समय नहीं हो पाया। पास बुक बन जाने से किसानों को बहुत फायदा है। इसके होने से किसानों को गिरदावरी करवाने के लिए और फर्द के लिए बार बार पटवारी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास बुक दिखा कर किसान को बैंक से लोन भी मिल सकेगा। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस पास बुक को किसानों के लिए जल्दी से जल्दी भुरु किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरे नम्बर पर मैं डिमाण्ड नं० 8 जो कि रोडज के बारे में है, बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा हलका हरियाणा में सबसे बड़ा है जिसमें पिलखनी, इस्माइलपुर, दानापुर धमतौर का 77 किलोमीटर का एरिया है। यहां पर 350 किलोमीटर रोडज का जाल फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह एरिया फलड एफैक्टिव एरिया है इसलिए जो रोडज बनाई जाती है वे हर साल टूट जाती

है। अध्यक्ष महोदय, टांगरी नदी पर एक पुल बनना था इस पुल के लिए एडमिनिस्ट्रटिव एप्रूवल भी हो गई थी। इस पुल के बनने से पटियाला से लेकर हमारे एरिया तक बहुत बड़ा एरिया एक हो जाएगा। यह मेरे हलके की सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद मैं एजूके इन और उसके साथ ही स्पोर्ट्स के विषय में भी बोलना चाहूंगा। हमारे पूरे हरियाणा में भाहरो की बजाय गावों में पढाई का स्तर बहुत ही नीचा है और खास कर बच्चों को पढाने वाले टीचर्स का स्तर बहुत ही नीचा है। टीचर्स को पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या पढाना है और कैसे पढाना है जिसके कारण हरियाणा के बच्चे कम्पीटी इन में पिछड़ते जा रहे हैं। जहां तक इस बारे में सरकार का ताल्लुक है सरकार द्वारा टीचर्स की जो पोस्टे खाली पडी हुई थी उनको भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद मैं डिमाण्ड नं० 15 पर बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बिजली के स्लैब सिस्टम के लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हरियाणा में बिजली का स्लैब सिस्टम लागू किया। मुख्यमंत्री जी सबको एक नजर से देखते हैं। इस स्लैब सिस्टम के बारे में विरोधी पक्ष के भाईयों को नाराजगी थी।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। *****

श्री अध्यक्ष: यह जो भागी राम जी ने कहा है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ भेद-भाव किया जा रहा है। ये जो मर्जी कह लें। हम कुछ कहते तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार के भेदभाव की मिसाल देना चाहता हूँ। हमारी गैलरी में तो पीने का गर्म पानी है और इनकी गैलरी में ठण्डा पानी है।

श्री अध्यक्ष: भागी राम जी, आप रुलिंग साईड की गैलरी से भी पानी पी सकते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री निर्मल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह स्लैब सिस्टम लागू करने से कोई सरकार लोन नहीं माफ कर सकती है क्योंकि नाबार्ड, आर बी आई, और बाकी दूसरे बैंकस को ऐतराज है। इस सरकार ने स्लैब प्रणाली लागू करके किसानों को काफी फायदा पहुंचाया है। जहां पहले हमारे इलाके में किसानों को बिजली के बिल के रूप में 13-13 सौ रुपये देने पड़ते थे वही अब उनको 400 रुपये ही देने पड़ेंगे। मुख्य मंत्री जी का यह बहुत ही सुझबुझ वाला कदम है। हमारे एरिया में जो ट्यूबवैलज है, वे 400 400 फुट गहरे हैं पहले इनका 600-600 रुपये का बिल आ जाता था। इस स्लैब प्रणाली के लागू होने से सढोरा, अम्बाला और नारायणगढ के इलाके में किसानों को बहुत ही फायदा हुआ है। इस बारे में हूँ भी पहले कंफयूजन था लेकिन अब नहीं है। स्पीकर सर, पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने पुराने स्लैब रेट उठाकर बिजली विभाग को दे दिए लेकिन चौधरी साहब ने आदे 1 कर दिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इस बारे में दोबारा सर्वे करें।

इसके लिए हम चौधरी साहब के बहुत ही आभारी हैं। स्पीकर सर, वैसे तो सरकार ने हमारे हलके के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न किया है और कई स्कीमज वहां के लिए बनाई हैं। हमारे यहां से एक नहर गुजरती है, उसमें जब तक साईफन नहीं लगाया जायेगा तब तक पानी टांगड़ी नदी में नहीं गिरेगा। जब तक ऐसी नहीं होगा तब तक हमें रिलीफ नहीं मिलेगी। हम चौधरी साहब के नोटिस में यह बात लेकर आए थे कि जो फ्लडज एफैक्टिव एरियाज हैं उनमें किसानों के लिए कोओपरेटिव डिपार्टमेंट से तालमेल करके लम्बी अवधि के लोन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको आठ या दस साल तक की अवधि के लम्बे कर्ज देने चाहिए ताकि उनका गुजारा चलता रहे। इसके साथ ही उनके खेतों में प्लांटेंशन भी होनी चाहिए। ऐसा होने से उनको फ्लड से बचने में भी सहायता मिलेगी और उनके खाने पीने का काम भी चलता रहेगा। जब आठ या इस साल के बाद यह प्लांटेंशन कट जाएगी तो इससे उनको इंकम भी होगी और वे अपना लिया हुआ कर्ज भी लौटा सकेंगे। इसलिए इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से यहां पर एव0 वाई0 एल0 कैनल की चर्चा आयी थी। स्पीकर सर, एस वाई एल कैनल हम हरियाणावासियों के लिए एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसके हम सब पोलिटिकल पार्टियों को रानीति से उपर उठकर कोऑऑरेट करनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमें कोई पोलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। स्पीकर साहब, कोओपरेटिव एग्रीकल्चर या फौरेस्ट डिपार्टमेंट का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। आज नये बीजों को बढ़ावा दिये

जाने की जरूरत है। ऐसे उन्नत किस्मों के बीज लाने चाहिए ताकि पानी की भी खपत कम हो और पैदावार भी बढ़े। इसी तरह से प्लांटों को भी पूरी हरियाणा में बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इससे जमीन ताकतवर होती है। चौधरी साहब ने नंगल इरीगेशन स्कीम अम्बाला जिले को दी। जब बरसात होती थी तो फलड उस एरिया में बहुत नुकसान करती थी। इसी तरह से टांगडी और मारकंडा नदी के पानी की भी बात यहां पर आयी थी। हम इनका पानी आज तक कंट्रोल नहीं कर सके हैं। इस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर कई जगह लिफ्ट करके बांटा जा सकता है और दो या ढाई महीने पानी की जरूरत पूरी की जा सकती है। आज भी टांगडी नदी में पानी चल रहा है लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से एक मसूरपुर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है जिसके लिए सरकार ने एक करोड़ रुपया तो दिया लेकिन मैं चाहूंगा कि बाकी पैसा भी इसके लिए मिलना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि यह स्कीम जल्दी ही भुरु हो जाएगी। स्पीकर सर, बिजली के बारे में हमारे विपक्ष के साथियों में जो कंप्यूजन है उसको चौधरी साहब ने दूर करने की कोशिश की है। इनकी बात का सारा हरियाणवी विचार वास भी करते हैं। वे जानते हैं कि चौधरी साहब जिस बात को कहते हैं वह पूरी करते हैं। कल जो स्पीच चौधरी साहब ने दी और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो एक एक आंकड़ा यहां हाउस में दिया, वह बहुत ही काबिले तारीफ था। इसके बाद उन्होंने सभी विपक्षी साथियों का कंप्यूजन दूरी किया। हमें आशा है कि इसके बाद अम्बाला जिले में भी एक

या डेढ साल बाद पूरी बिजली आनी भुरु हो जाएगी। लेकिन स्पीकर साहब, आज वहां फिक्वैन्सी और ट्रांसमिशन का सिस्टम कमजोर है। टेकडा और मोडा मे दो बिजली घर सरकार ने बनाने मंजूद किए है मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको एक साल मे ही कम्प्लीट किया जाए ताकि आने वाले समय मे वहां के लोगो को बिजली का सही रुप मे फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट के द्वारा काफी समय पहले मेरे डिस्ट्रीक्ट मे पौलीक्लीनिक मंजूर हुआ था लेकिन किन्ही कारणवत वह दूसरे जिलो मे ले जाया गया। उसके लिए वहां की पंचायत ने जमीन भी दे दी और वह जमीन ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट के नाम भी चली गई है अतः मेरा निवेदन है कि इस पौलिक्लीनिक को पूरा किया जाए। अब मै ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे मे अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे से पूर्व बोलते हुए बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही, उससे भी मै इस बारे मे सहमत हू। मेरेल हल्के नन्यौला मे भी 5 बसो को रुट परमिट दिए गए थे लेकिन अब केवल दो रुटस ही रह गए है और उसमे भी कोई बस खराब हो जाए तो सवारियो को बडी भारी परे पानी हो जाती है क्योकि एक तरफ तो वहां सवारियो बहुत ज्यादा है और केवल दो रुटस है तथा दूसरी तरफ रोडवेज वाले मजबूर है कि वहां बस नही भेज सकते है। मेरा भी वीरेन्द्र सिंह जी की तरह निवेदन है कि इस बारे मे लॉ मे कोई अमैडमेंट होनी चाहिए, कोई बिल इस बारे मे आना चाहिए ताकि रोडवेज वाले भी वहां बसे चला सके और लोगो की परे पानी दूर

हो सके। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हू।

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी माननीय सदयो से निवेदन है कि मैने आपको आ वासन दिया था कि अभी तक किसी भी सदस्य को यदि बोलने का उचित समय न मिला हो तो मै उसे बोलने का पूरा मौका दूंगा। अब यदि विपक्ष या पक्ष का कोई भी सदस्य यह महसूस करता है कि उसे समय नहीं मिला तो I invite him to speak. अगर अब तक किसी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है तो he is invited.

श्री मनीराम: अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष: मनीराम जी, आप बैठे आपको बोलने का मौका दिया जा चुका है। कट मो इन पर I request Shri Khurshid Ahmed to speak.

श्री खु र्शद अहमद (नूंह): स्पीकर सर, जितनी भी डिमांडज है उन पर हमारे बहत से साथियो ने कट मो इन दिए हुए है इसलिए इनके बारे मे सभी मैम्बर्ज को बोलने का थोडा थोडा समय दिया जाए जिससे वे अपनी बात कह सके और उनका नजरिया हाउस के सामने आ जाए। वैसे अब बोलने के लिए रह तो कोई नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष: सर, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हमारे सामने डिमांडज आई है। मै सबसे

पहले इंडस्ट्रीज की डिमांड को रैफर करुंगा। डिमांड नं0 16 मे भारु मे जब यह असैम्बली इलैक्ट हो कर आई थी, उस वक्त मैने प्वायंट उठाया था कि स्टेट की इंकम को मोपअप किया जए और उसे सरकार अपने हाथ मे ले तो हमारे बहुत से टैक्सेज जो हमने लोगो पर लगाए है, वह बच जाए। जो हमारे हाथ मे उस दिन सोर्सिज थे, बजाय इसके कि कोई यह कहे कि पिछली सरकारो ने यह किया, मौजूदा सरकार की चाल उनसे भी ज्यादा टेढी निकली है, मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक दफा माइंज और मिनरल्ज के बारे मे यह बात आई थी तो मैने कहा था कि माइंज एण्ड मिनरल्ज मे बहुत बडा सकैण्डल चल रहा है और बिल्कुल निराधार तरीके से बडे बडे लोगो को लीजिज मेजर मिनरल्ज के नाम पर दी गई है। माइंज-मिनरल्ज को लम्बी अवधि के लिए लीज पर लेने का तो बहाना है। मेजर मिनरल्ज वहां नही है। वहां किसी भी चीज का नाम लेकर लाइसेंस दिया गया है चाहे वह सिलका के नाम पर दिया गया हो या चाईना के नाम पर दिया गया है। इनमे भाब्दो का अंतर है। वास्तम मे उनके नाम पर लम्बी अवधि की लीज दी गई है। जबकि वहां पर निकलता है सिर्फ स्टोन मैटल्ज लोकि लोक निर्माण मंत्री जी के विभाग की सडके बनाने के काम आता है। स्टोन क्वै र वालो के काम आता है या बजरपुर वालो के लिए पत्थर से बजरी बनाने के काम आता है। सरकार की एक संस्थान एच0 एल0 एल नाम की थी जो मिनरल्ज का काम करती थी जिससे स्टेट को काफी आमदनी होती थी। परन्तु उस संस्थान के साथ भी अन्याय हो रहा है। वहा पर

प्राइवेट लीज होल्डरो ने कब्जा किया हुआ है। उसकी एक मिसाल मैं सदन के सामने रखता हूँ। (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, 1996 में जब यह सरकार बनी, उस समय एक प्राइवेट लीज होल्डर ने फरीदाबाद में एक डिसम्ब्यूट डाल दिया कि मेरी डिमारकेन दोबारा कराई जाये। उसकी लीज तो 1983 में हुई थी लेकिन उसको रिडिमारके इन के लिए 1996 में जरूरत महसूस हुई। रिडिमारके इन उस एरिया से कराई गई जहां से बजरपुर निकल सकता था और एच0 एम0 एल0 को आमदनी होती थी। झूठी डिमारके इन बनाकर एच0 एम0 एल0 की डिमारके इन को रद्द कर दिया गया। जब एच0 एम0 एल0 की तरफ से चैलेंज किया गया कि यह डिमारके इन गलत की गई है क्योंकि इसमें फरीदाबाद और वल्लभगढ़ का एरिया दिल्ली में दे दिया गया है। जहां पर बजरपुर निकलता था, उस सड़क को हरियाणा में दे दिया गया है। फरीदाबाद और वल्लभगढ़ की सड़क हरियाणा में होने की बजाय दिल्ली में दे दी गई। एच0 एम0 एल0 ने जब कहा कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और जब दोबारा डिमारके इन हुई तो गुडगांव और फरीदाबाद के रास्ते में एक फ्लॉग उपर जाकर हरियाणा का रकबा दिल्ली में चला गया। 1997 में दिसम्बर में जब रिडिमारके इन हुई तो यह बात इस सरकार के सामने आई कि एच0 एम0 एल0 को कब्जा नहीं दिया गया इसलिए कि वह सारी डिमारके इन के बेसिज पर था और इससे प्राइवेट लैसी की आमदनी पर फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है कि जिस दिन डिमारके इन हुई थी उस दिन एम0 एम0

एल0 की रिटर्न 170016 मीटिक टन बजर पुर सैंड थी और जब 1996 मे कब्जा हुआ तक घटकर 341980 मीट्रिक टन हो गई। अब यह घटती ही जा रही है। अब यह घटकर 57299 मी0 टन हो गई है। पडोसी लैसी की रिटर्न जब तक उस पर कब्जा नहीं हुआ था उस समय 1464768 मी0 टन थी जो एक साल के लिए थी फिर जब यह कब्जा हो या तो पहले साल मे उसकी आमदनी लैंड एक्सकावेजन का वेट बढ़ने से 14 लाख से बढ़कर 1759475 मी0 टन हो गई है और आज बढ़कर 2086479मी0 टन तक पहुंच गई है। प्राइवेट लैसी की आमदनी 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है जिसमे हेराफेरी हुई हैं और उसको एक ट्रक पर 1500 रुपये बचते है। इस हिसाब से देखा जाएतो मै बता देता हूं कि वह ***** एम0 पी0 है। (विधन) मेरा जिगरी मित्र और आपका परम मित्र है। आज जब दोबारा डिमारके इन होकर आई है, जो पिछले साल दिसमंब मे ही हो गई थी, अब तक उस का कब्जा नहीं लिया गया है। अब मैने लेटैस्ट बात सुनी है कि इन दोनो के बीच रिकंसीलिए इन के लिए डायरैक्टर आफ कंसोलिडे इन की ड्युटी लगाई गई है। वह तय करेगा, इसके एक साल के लिए अगर वह ले गया तो फिर आप देखिये कि एच0 एम0 एल0 को उस मे कितना मुनाफा अथवा नुकसान होगा। पिछली सरकारो के स्कैंडल छोटे पड जाते है जब इतने बडे बडे स्कैंडल इस सरकार के समय मे हो रहे है। जो डिमारके इन की गई हे उसको मेरे पास लेटैस्ट नक्शा है, अगर आप इजाजत दे तो मै रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 107

के तहत उसको आपको दे देता हूँ। आप इसकी वैरीफिके तान करा सकते हैं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। खु र्फिद अहमद जी बहुत वरिष्ठ नेता है। ये पार्लियामेंट मे भी रहे है और विधान सभा मे भी रहे है। कई मरतबा ये मंत्री रह चुके है। चूंकि *****इस सदन मे उपस्थित नही है। वे इस वक्त लोकसभा के सदस्य है। (विघ्न) रिकार्ड कलीयर हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस की खु र्फिद अहमद जी बात कर रहे है उनका बडा भाई प्रताप सिंह पिछले 35 सालो से कायदे कानून के मुताबिक यह कार्य कर रहा है।

श्री खु र्फिद अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैने यह नही कहा कि लीज नही ले रहे है। लीज तो 1983 से ली गई है।

श्री राम बिलास भार्मा: उपाध्यक्ष महोदय, ***** का नाम सदन की कार्यवाही से डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि वे सदन मे उपस्थित नही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह जो नाम श्री खु र्फिद अहमद ने लिया है, उसे सदन की कार्यवाही से डिलीट किया जाए।

श्री खु र्फिद अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैने तो इन का नाम लेना ही नही था। मुझे तो नाम लेने के लिए इन्होने मजबूर किया है। (विघ्न) इस हाउस मे एक ए योरेंस भी दिया गया था

कि इस निगम को कैसे बचाया जाएगा? इसके लिए हाउस की एक सब कमेटी भी बनी थी तथा उस कमेटी में वही लोग लिए गए जिन की वजह से यह आमदनी घट रही है। उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है वह आज तक गुप्त रखी गई है। उस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हाउस को भी पता नहीं है। वह प्राइवेट लैसी जिसको एडवांटेज मिला है, भी उस कमेटी का एक मੈबर था। (विघ्न)

श्री करता सिंह भडाना: उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ खु रीद अहमद जी ने हाउस के अंदर बताया है उसमें कुछ सच्चाई तो है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे सरकार का रैवेन्यू का लौस हुआ हो। इस बारे में मुझे ज्ञान है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक रैवेन्यू की बात है वह अब 3 गुना हो गया है लेकिन डिमारके इन का काम तो रैवेन्यू विभाग का है, इसको वह देखेगा। इस में सरकार का कोई काम नहीं है। (गोर)

श्री खु रीद अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मूल बात का तो समर्थन किया है कि उसमें औकुपे इन व डिमारके इन का झगडा है, कही न कही कुछ गडबड है और इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि यह तो रैवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। यह रैवेन्यू विभाग श्री सुरजपाल जी के पास है, इसलिए यह भी तो सरकार का काम हो जाता है कि जितनी जल्दी हो सक एच0 एम0 एल0 को इन लोगों से बचाने की कोर्ि । । करे, उसका हम उसे दिलाए, उसकी आमदनी जो 7 लाख टन से

धटकर 57 हजार हो गई है उसको वापिस करवाएं और जो लाभ लीज होल्डर ले रहे हैं वे किसी भी तरीके से रैस्टोर होने चाहिए। मेरी रैवेन्यू मिनिस्टर से भी और सरकार से भी दरखास्त है कि जल्दी से ये एच0 एम0 एल0 को रैस्टोर करवा दें। दसमे पिछली सरकार का कोई हाथ नहीं है। यह एक ऐसा धब्बा है जिसको आपकी सरकार धो सकती है।

श्री करतार सिंह भडाना: जो डिमारके 1 न है वह सैन्टर गवर्नमेंट का मसला है और इसमे स्टेट गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। हमारी सरकार का चाहे वह रैवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है इसमे किसी का दोश नहीं है। हाई कोर्ट ने आदे 1 किए कि इसकी सैन्टरल गवर्नमेंट डिमारके 1 न करेगी।

श्री राम पाल माजरा (पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमाण्डज पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हू। मैं सर्वप्रथम डिमाण्ड नं0 17 पर कहूंगा। हमारा प्रदे 1 कृषि प्रधान प्रदे 1 है। जिस प्रदे 1के किसान दुखी हो वह कैसे तरक्की कर सकता है। कर्ण सिंह दलाल को सबसे ज्यादा इस बात को महसूस करना चाहिए कि पंजाब में बिजली के बिल माफ है अगर वहां टैक्टर खरीदने जाते हैं तो सैलज टैक्स 2 प्रति 1त लगता है। जबकि हरियाणा में यह साढ़े चार प्रति 1त है, हिमाचल प्रदे 1 में डेढ प्रति 1त और चण्डीगढ में 2 प्रति 1त सैलज टैक्स लगता है। अगर टैक्टर का कोई स्पेयर पार्ट खरीदना चाहे तो हरियाणा में 10 प्रति 1त, पंजाब में 2 प्रति 1त और राजस्थान में 4 प्रति 1त सैलज टैक्स

लगता है। हरियाणा के किसानों को ट्रैक्टर के रेट पर 5000 से 7000 हजार की सबसिडी मिल जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। हरियाणा में वाटर लैवल भी नीचे चला गया है। जब किसान कुएं में मोटर का पट्टा डालने के लिए नीचे जाते हैं तो जहरीली गैस के कारण या बिजली का करंट लग जाने से वे मर जाते हैं। कई किसानों के नौजवान बच्चे इसलिए भी मर जाते हैं कि किसी को सांप काट जाता है या किसी पर आसमानी बिजली गिर जाती है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसे किसानों को पुरा मुआवजा देने का कोई बिल पास करे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री कल एक लिस्ट पढ रहे थे कि किसान कर्जदारी के वक्त में कैसे मरे उन्होंने बताया कि इनमें से बहुत से जाट थे। जगननाथ जी बड़े खुश हो रहे थे कि जाट हैं ये तो मरेगे ही। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजकुमार पुत्र मामन, जाति हरिजन, वासी सीवन, उम्र करीब 30 साल ने बयान दिया है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ और मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। मैं भादी जुदा हूँ। मेरे पास एक लडका और एक लडकी यानि दो बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी से मेरा घर का खर्चा नहीं चलता इसलिए मेरे पास काफी देनदारी हो गई थी। देनदारी वालों की टोका टोकी से मैं तंग आ गया था अतः मैंने आत्महत्या करने के लिए गेहूँ में रखने वाली गोलियाँ जो कि मैं काफी पहले कैथल से लाया था और जिन्हे मैंने घर में छुपा कर रखा हुआ था, खा ली। उपाध्यक्ष महोदय, जो मेहनत करता है वह किसान है लेकिन जो वह हरिजन मरा है वह किसान से भी आगे है। आप कह रहे हैं

कि वह किसान नहीं है। इसने भी आत्महत्या की है। यह मेरे पास इसकी पोस्टमार्टम और उसकी डाईंग डिक्लेयरे इन की रिपोर्ट्स है। क्या हरिजन इंसान नहीं होता क्या हरिजन मरने के लिए है? उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत बुद्धिमान शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 1991 को गैसस के मुताबिक हमारे प्रदेश में लिट्रेसी रेट बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, 1991 को सेंसेस के मुताबिक वि. व. का लिट्रेसी रेट 77.4 परसेंट है, भारतवर्ष का 92.21 परसेंट है, हरियाणा का 54.85 परसेंट है चण्डीगढ़ का लिट्रेसी रेट 77.81 परसेंट है और दिल्ली का 79.25 परसेंट है। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट स्कूल का प्लस टू का एक छात्र प्रथम स्थान पर आया है। मैं उनको कहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मिडिल स्कूलों के परीक्षा परिणामों की 10 स्कूलों की लिस्ट मेरे पास है। इन स्कूलों में एक भी बच्चा प्रथम नहीं आया। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे माननीय सदस्य श्री निर्मल सिंह जी ने कहा था कि शिक्षा को टी0 बी0 के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने गांव के स्कूलों में टी वी दिए थे लेकिन बहुत से स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है वहां पर टी वी क्या काम करेगा? ये टी वी टीचर्स के घरों में रखे हुए हैं। मैं इस बात को मान कर चलता हूँ कि हमारे शिक्षाविद मंत्री जी शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। आज हर गांव की चौपालों में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इसलिए सरकारी स्कूलों में कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं

जा रहा है। जबकि प्राइवेट स्कूल के मास्टर की तनखाह कम है और उस प्राइवेट स्कूल में दूसरी सहूलियतें भी नहीं हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में मास्टरों की तनखाह भी ज्यादा है और सहूलियतें भी ज्यादा हैं लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर बंदी लगाए। किसी प्राइवेट स्कूल की 62 हजार साल की फीस है और किसी की 21 हजार रुपये महीना है। आज बच्चों के अभिभावक यह समझते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, हमें मम्मी डैडी कहना सीख जाए इसलिए वे प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फीस देकर अपना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब प्रदेश की तरफ पर हमारे यहां पर भी आप पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दें ताकि बच्चों का पब्लिक स्कूलों की तरफ यानि प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान कम हो और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वे भी गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर अंग्रेजी पढ़ने का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिन गवर्नमेंट स्कूलों के परिणाम बहुत नीचे चले जाते हैं उनका बी० डी० ओ० और डी० पी० आई० कभी भी जाकर निरीक्षण नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करवाएं और शिक्षा में सुधार लाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ज्यादा फुर्ती के साथ काम नहीं कर रहा है। देखने में आया है कैथल में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन

पर रातो रात दुकाने बन गई। इसी तरह से वहां पर मार्किट कमेटी की पुरानी अनाजी मंडी के अंदर 12 दुकाने रातो रात आ गई। यदि फुर्ती के साथ काम किया जाता तो कोई नाजायज काम नहीं होते। वह करोड़ों रुपये की जमीन है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

कैप्टल अजय सिंह यादव (रिवाडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं मांग नं० 15 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। उस वक्त की सरकार द्वारा 1977 के अंदर थीन डैम से गोविन्द सागर में 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी डालने की बात कही गई थी। यह पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए आना था। उस वक्त लोक दल की सरकार थी। हमें एस० वाई० एल० कैनाल का 1.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना था लेकिन वह पानी हमें देने की बजाय सिरसा की तरफ ले गए, हिसार की तरफ ले गए जबकि हमारा इलाका उसका हकदार था। यह इलाका इस पानी से वंचित हो गया। इस पानी की वजह से सिरसा व हिसार जिलों में तो सेम हो गई जबकि हमारे यहां पर जो डिस्ट्रिब्यूटरीज है, उनकी टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंच पाता। खाले बना दी गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज बना दी गई लेकिन पानी नहीं दिया गया। हमारा इलाका सूखा पड़ा है। हमारे वहां पर पीने के पानी की समस्या है। मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 111 करोड़ रुपये की लागत से एक ड्रेन बनाएंगे और इसके द्वारा फालतू पानी इधर लाएंगे। मैं बताना

चाहूंगा कि आज महेन्द्रगढ़, पटौदी, मेवात या उस तरफ का दूसरा जो एरिया है उसमें पानी नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो वायदा चुनाव में किया था उसके बारे में इनको कुछ सोचना चाहिए। सरकार इस काम के लिए 1858 करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है। जबकि हमारे सर छोअँ रापम जी ने इसलिए बनियो की बहिया फडवा दी थी उनको जलवा दिया था क्योंकि उन्होंने हमारे जमींदारों को कर्ज दिया हुआ था। जबकि ये कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। जो ये कर्ज ले रहे हैं उसका 14 परसेंट इंटरस्ट के हिसाब से 350 करोड़ रुपया इनको ब्याज देना पड़ेगा जबकि पानी से फिर भी हम वंचित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नरवाना ब्रांच, भाखडा ब्रांच, मेन लाईन जो है इसमें से हमें 2700 क्यूबिक पानी कम मिल रहा है, हमारे इलाके को कम पानी मिल रहा है, उसकी डिसिलिटिंग नहीं हो रही जिस वजह से कुछ पानी तो पंजाब ले जाता है और कुछ पानी हिसार या सिरसा की तरफ चला जाता है। पानी का सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि हिसार व सिरसा में तो सेम आ रही है जबकि हमारे यहां पर लिफ्ट की जो कैनाल है उसमें पानी नहीं आ रहा है। चौधरी बंसी लाल जी लिफ्ट कैनाल की बात करते हैं, 1.8 मिलियन एकड फीट पानी की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश से पानी लाने की बात करते हैं। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारे यहां पर लिफ्ट की जो स्कीम थी, उनकी 30 प्रतिशत से ज्यादा मीटर खराब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। हमारे यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं

उनमे टेल एण्ड तक पानी नही जाता। उनमे गादड ब्या गये है। उनकी पूरी तरह से सफाई नही हो रही है। मै चाहूंगा कि इन डिस्ट्रीब्यूटरीज की मौके पर जा कर निरीक्षण की जाये और उनकी सफाई कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज के लिए हमारे लोक दल के इन भाईयो ने करोडो रुपये लगाकर हजारो एकड जमीन एक्वायर की और उस जमीन पर दिल्ली को बचाने के लिए मसानी बैराज बनाया गया। चौधरी बंसी लाल जी जो विपक्ष मे बैठा करते थे तब कहा करते थे कि मै कुशणावती, दोहान और साहबी नदियो का पानी हरियाणा मे लाने के लिए, हरियाणा सरकार को राजस्थान सरकार से बात करनी चाहिए। लेकिन आज ये स बारे मे कोई बात नही कर रहे है। उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान मे नदियो का पानी ज्यादा हो जाता है तो वे इस पानी को हमारे इलाके मे छोड देते है, जिससे हमारे इलाके की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा इसी हाउस मे आ वासन दिया गया था कि हम मसानी बैराज पर भाटर्ज लगायेंगे, लेकिन अभी तक वहां पर भाटर्ज नही लगे है, उसका पानी वहां पर तबाकी मचाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बैराज के बनाने के लिए जो जमीन किसानो से ली गई थी उसके लिए उन्हे मुआवजा भी नही दिया गया है। इस बैराज की एक 6 फुट उंची दीवार बना दी है जिसके कारण उन बेचारे किसानो के मकान और खेत डुबे पडे है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय गंगा का पानी हरियाणा मे लाने की बात कर रहे है, लेकिन मै तो इनसे यह कहता हूं कि आप गंगा के पानी की बात तो छोडिये, आप एस0 वाई0 एल0

कैनाल बनाकर ही हमें हमारी हिस्से का पानी दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इस बजट के अंदर एस0 वाई0 एल0 कैनाल के बारे में बहुत ही मामूली तरीके से बात कही गई है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्गव): उपाध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज मेरे लायह दोस्त कैप्टन साहब के इलाके में है, इस बैराज में भाटर्ज तो तभी लगाये जा सकते हैं जब इसमें पानी आता हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कैप्टन साहब से पूछता हूँ कि क्या ये मसानी बैराज को एप्रूव करते हैं, क्या इसके बनने के बाद से उसमें कभी पानी आया?

कैप्टन अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, 1995-96 में मसानी बैराज में पानी आया, लेकिन इस बार अब तक उसमें पानी नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री हर्ष कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, साहबी नदी पर बांध बनने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस नदी पर 3 बांध पीछे बना लिये, इसलिए उधर का पानी तो इधर आता नहीं है। यह जो मसानी बैराज बना है चाहे किसी भी सरकार के दिमाग की उपज हो, इसका कोई भी उपयोग नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जब राजस्थान में पानी फालतू हो जाता है तो ये अपने इलाके को तो डूबने नहीं देते, बल्कि उससे पहले ही अपने

उन बांधो को तोड़ देते हैं। उनके बांध कच्चे बने हुए हैं जिसके कारण हमारे इलाके में बाढ़ आती है। मैं इरीगे टन मंत्री से कहना चाहता हूँ कि जब बरसात के दिनों में जमुना और जे० एल० एन० कैनल के अंदर ज्यादा पानी होता है तब आप इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जे० एल० एन० कैनल का एक छोटा सा हिस्सा भी मसानी बैराज में जोड़ दें तो यह फालतू पानी मसानी बैराज में जा सकता है और वहाँ इसका उपयोग हो सकता है। उसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा।

श्री धीरपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट इरीगे टन मंत्री की रिप्लाइंके बारे में कहना चाहता हूँ कि 1977 या इससे पहले साहबी नदी में कई बार 30-40 हजार क्यूबिक फुट पानी डेली आता रहा है। मंत्री जी को उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बाहली, झज्जर, रिवाडी और पटौदी वगैरह का जो इलाका है उस में इस नदी से भयानक तबाही होती थी लेकिन उन लोगों को बचाने के लिए मसानी बैराज की आवश्यकता महसूस की गई। लेकिन इसको बनाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी इस नदी पर अपने यहाँ बांध बना लिये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, चौधरी बंसी लाल जी तो इस समय बैठे नहीं हैं लेकिन जब ये विपक्ष में हमारे साथ बैठते थे और उधर चौ० भजन लाल जी बैठते थे तो ये बार बार कहते थे कि राजस्थान सरकार पर दबाव डालकर जो राजस्थान की भूमि पर उनहोंने बांध बनाये हुए हैं, उन बांधों को

हटवाया जाये और इस साहबी नदी के पानी मे हमारा जो हिस्सा है, वह हमें दिलवाया जाये। लेकिन अब इन्होने पानी का वह हिस्सा तो लिया नही और बेवजह की गुमराह करने वाली बातें कर रहे है। (इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की स्लैब प्रणाली का संबंध है, इस बारे मे मै कुछ कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब आप दो मिनट मे कन्कलूड करें। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैने तो अभी बोलना भुरु ही किया है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, स्लैब सिस्टम पहले सरकार ने खत्म किया और फिर उसको दोबारा लागू भी किया गया है। सरकार यह बताए कि यदि इस सिस्टम को दोबारा लागू करना ही था तो किसी किस्म को कोई सर्वे करवाया है? अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय राम बिलास भार्मा जी यहां पर बैठे हुए है इन्हे उस इलाके के बारे मे पूरा ज्ञान है कि वहां पर जो ट्यूबवैल लगे हुए है वे 70 या 80 फुटकी गहराई पर स्टार्ट होते हैं हमारे इलाके की समस्या यह हैकि उन इलाके के साथ ईक्वेट कर दिया गया है जहां पर चार चार फसले साल में होती है। हमारे इलाके मे तो सारे साल मे एक ही फसल होती है। (घंटी) हमारे यहां पर नहरो का पानी लगता है और लोग वहां पर

सिंचाई के लिए ट्यूबवैलो पर ही निर्भर करते हैं। जहां पर नहरे हैं वहां पर आबियाना 20 रुपये है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय कैप्टन साहब ने स्लैब सिस्टमके बारे में भायद पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले के लोगो ने कहा है कि यह सिस्टम किसानो के लिए बहुत लाभदायक है। अध्यक्ष महोदय महेन्द्रगढ और लोहारु के एरिया के किसानो को बिजली बोर्ड से चिठ्ठीयां आई हैं कि जिन लोगो ने बिल ज्यादा जमा करवाए है या जिन्होने जितना अधिक बिल पे किया है, वे अब उसबिल को या तो अगले बिल में एडजस्ट करवा ले या फिर अगर वे चाहे तो पैसा उनको वापिस मिल सकता है। इस स्कीम से किसानो को बहुत लाभ हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय जिस सर्वे की ये बात कर रहे हैं वह भी हो रहा है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,*****

Mr. Speaker: Now, I request Capt. Ajay Singh to take his seat. (interruption) Nothing is to be recorded.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, मैंने बजट डिमाण्डज 1998-99 में डिमाण्ड नं० 2, डिमाण्ड नं० 4, डिमाण्ड नं० 8, डिमाण्ड नं० 10, डिमाण्ड नं० 15 और डिमाण्ड नं० 21 पर कट मो एन्ज दी हुई है। इन डिमाण्डज पर मैं दो दो

मिनटस अपने विचार रखना चाहूंगा। स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में कट मोशन पर बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय 1977 में जब हम पहली बार विधान सभा में चुन कर आए थे, उस वक्त तनख्वाहों पर टोटल बजट का 36 पैसे का खर्च होता था।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by 30 minutes.

Voices: Yes.

Mr. Speaker: Time of the sitting is extended by 30 minutes.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, उस वक्त इम्प्लोइज् की सैलरी पर तथा जो भते हम उनको देते थे, पर टोटल बजट का 36 पैसे इस मद पर खर्च होता था। लेकिन आज फिगर रिवर्स हो गई है। आज यह फिगर 36 की बजाय लगभग 63 हो गई है। मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन मेरा अनुमान है कि यह फिगर लगभग 63 हो गई है। इरीगेटिव डिपार्टमेंट ने जो पैसा डिवलपमेंट के काम के लिए रखा गया है वह बहुत ही कम है क्योंकि उस पैसे का 72 प्रतिशत हिस्सा तो तनख्वाहों में ही चला

जाता है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। आज आप किसी भी दफतर मे जाकर देख लें, एक आदमी की जगह पर 4-4 आदमी काम के लिए लगा रखे है। कोई एक आध आदमी ही सिरियसली किसी दफतर मे काम करता होगा वरना तो कई ऐसे है जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे मिलेंगे। उनमे से अगर किसी को कोई काम कह दिया जाये तो वह कहेगा कि यह मेरा काम नहीं है यह फलाने का काम है और किसी दूसरे पास जाओ। जब दूसरे के पास जाओगे तो वह भी यही कहेगा कि यह मेरा काम नहीं है। आज कोई भी सिरियसली काम नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, आई० ए० एस० के कैडर मे 64 पोस्टे ऐसी है जो एच० सी० एस० से प्रमोट करके भरी जाती है लेकिन आज इनमे से 30 भरी हुई है और 34 खाली पडी हुई है। कांस्टीच्युए ान में मैंडेटरी है कि हर साल डी० पी० सी० की मीटिंग होनी चाहिए और जो सीनियर एच० सी० एस० है उनको पदोन्नति मिलनी चाहिए। पिछले चार साल से जिसमे दो साल भजन लाल जी की सरकार के थे और अब दो साल इस सरकार को आए हुए हो गए है, इस बारे में इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ये जो पोस्टे खाली पडी हुई है उसके बारे मे सरकार कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह सरकार एफिंटे एडमिनिस्ट्रे ान तभी दे सकती है जब यह सरकार उन आफिसर्ज पर भरोसा करे। सरकार के जो मुखिया है जो सरकार चलाते है ऐसे करीब 30 से उपर एफ० सीज० और सैक्रेटरी रैंक के आफिसर्ज है। उनमे से 16 आफिसर्ज तो ऐसे मिलेगे जिनको ऐसी जगह पर लगा रखा है जहां पर कोई काम नहीं है। उनको

कहते हैं कि आओ, बैठो चाय पियो और अपने घर चले जाओ। जबकि किसी किसी आफिसर को तो चार चार आदमियों का काम दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, सभी आफिसर एफिंटेड होते हैं हर कोई अच्छा काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 32 सालों में हरियाणा बनने के बाद हमारे यहां पर एक सिस्टम डवलप हुआ है कि हम अधिकारियों को ग्रुप के हिसाब से देखने लग गए हैं कि फलाना अधिकारी किसी खास के साथ जुड़ा हुआ है और फलाना आदमी उसके साथ है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि प्रॉमोशन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर अधिकारी पर विवास करना पड़ेगा। जो अधिकारी धोखा देता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और उसके खिलाफ जो भी सजा बनती हो वह उसको दी जाए। यह तो मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने खर्चों को कम करने के लिए भी एक कमेटी बनाएं। फोरचुनेटली लीडर आफ दी हाउस भी यही बैठे हैं। आज सैन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से 60 साल तक कर दी है। मैं यह बात साफ करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर सरकारी अधिकारियों के रिटायर होने पर कम से कम 25 हजार नौकरियां उनकी जगहों पर दी जाती हैं। अगर सरकार यहां भी इस उम्र को बढ़ा देती है तो बहुत से नौजवान नौकरियों से वंचित हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय 58 साल की उम्र के व्यक्ति को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह में तीन नए नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी तो हम सरकार से

यह आवासन चाहेंगे कि इन परिस्थितियों को देखते हुए जबकि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही हो तो सरकार 58 साल से 60 साल उम्र बढ़ाने में कोताही बरतेगी और केन्द्र सरकार को इस मामले में फोलो नहीं करेगी। स्पीकर साहब, बहुत सी स्टेट्स ने इस बारे में मना कर दिया है कि हम यह उम्र 58 साल से 60 साल नहीं करेंगे ताकि नौजवानों को नौकरियों मिल सकें। इसके अलावा मैं इरीगेशन के बारे में अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में नरवाना डिवीजन और हिसार डिवीजन से सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध होता है। इनमें से एक डिवीजन का एस0 ई0 कैथल में बैठता है। हमारे यहां पर एक ही डिवीजन के अंदर दो तरह के सिस्टम हैं जैसे अभी यहां पर स्लैब सिस्टम की बात आयी थी। वैसे तो हमारे यहां भी दो तरह की सिंचाई की व्यवस्था के सिस्टम हैं, स्पीकर साहब, पिछले साल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और लीडर आफ दी हाउस ने मेरी बात को ठीक मानते हुए यह कहा था कि हम इसको दिखवाएंगे। स्पीकर साहब, एक रजवाहा तो हमारे यहां महीने में आठ दिन चलता है और 21 दिन बंद रहता है और इसी के साथ साथ दूसरी नहरों में पानी 15 दिन चलता है और 15 दिन बंद रहता है। मैंने यह कहा था कि हमारे साथ यह डिस्कमिनेशन पिछले आठ नौ साल से हो रहा है।

श्री बंसी लाल: तब आपकी ही सरकार थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अगर हमारी सरकार ने कोई गलती की है तो हम अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसको ठीक करें। अगर आप भी उनको ठीक नहीं करते तो हम समझेगे कि हममें ही कोई कमी है या हमने कोई गुनाह किया है। स्पीकर साहब, उस रोटे इन सिस्टम को ठीक किया जाय और दूसरी नहरों की व्यवस्था की तरह हमारे यहां की नहरों में भी 15 दिन पानी चलना चाहिए और 15 दिन बंद रहना चाहिए। स्पीकर साहब, हमारे यहां धमातन और सुदकन दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं इनमें से एक नरवाना विधानसभा क्षेत्र को फीड करती है और दूसरी उचाना विधान सभा क्षेत्र को फीड करती हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस गलती को ठीक किया जाये ताकि किसानों को वहां पर पूरा पानी मिल सके और किसान वहां दो फसल ले सकें इससे किसान वहां अन्न भी ज्यादा पैदा कर सकेंगे। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब टांगडी, मारकंडा या घग्गर नदी पर हम बैराज बनाने की बात करते हैं तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि पिछले लोकसभा के चुनावों में दडबा कलां कांस्टीच्युएंसि में कम से कम दो दर्जन गावों वालों ने इन इलैक्ट्रिक इन का बायकाट किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि हम किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहां के 24 गावों में पिछले कई सालों से सेम की समस्या गंभीर होती जा रही है लेकिन अब तक किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। स्पीकर साहब, यह समस्या राजस्थान के सूरतगढ़ में बड़ा भयंकर रूप धारण कर रही है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे यह सबमिशन

है कि एक तरफ तो हम सेम की समस्या सिरसा, हिसार के इलाको मे पैदा कर रहे है। यदि आगे राजस्थान के लोगो ने इस पानी को रोक दिया तो हमें इसको संभालने के लिए जगह भी नही मिलेगी वहीं दूसरी तरफ हम टांगडी, मारकंडा और घग्गन जैसी नदियो पर बैराज बनाने की तरफ भी ध्यान नही दे रहे है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेम की समस्या के समाधान हेतु टांगडी, मारकंडा और घग्गर नदियो पर बैराज बनाने की इस स्कीम को भुरु करना चाहिए। स्पीकर साहब, इसके अलावा मै यह भी कहना चाहूंगा कि इरीगे इन डिपार्टमेंट एक तरफ तो एम0 आई0 टी0 को सक्लटन के रुप मे रखना चाहता है वही दूसरी तरफ स्थिती यह है कि जो किसानो के पक्के खाले बने हुए है वे आज टूट रहे है। इन पक्के खालो को तो आप मिटटी से ठीक नही कर सकते। इनकी रिपेयर तो आपको करवानी ही पडेगी।

श्री बंसी लाल: बरसौला माईनर किस क्षेत्र में है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: बरसौला माईनर उचाना, जींद और नारनोंद के कुछ गांवो को इरीगेट करेगा लेकिन मैने तो इस माईनर का जिक्र नही किया। अगर आप कुछ काम करेंगे तो हम आपका दाद देंगे, आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम पिछले 25 सालो से चिल्ला रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी बात नही सुनी। जब कभी भी हमारी सरकार बनती थी तो हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे पडोसी उसी महकमे के मंत्री होते थे। आपने यह काम बहुत अच्छा किया है और वहां

के लोग आपकी इस बात के लिए बहुत आभारी है। (घटी) अब मैं ऐगिजस्टिंग चैनलज के बारे में कहना चाहूंगा। उनमें डिसकिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कम्युनिटी डिवैलपमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले 30-32 साल में बल्कि देश की आजादी के बाद कम्युनिटी डिवैलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर गांव में बहुत असेट्स डिवैलप किए हैं। इस डिपार्टमेंट ने हरिजन चौपाल, बी0 सी0 चौपाल, पंचायत घर के अलावा स्कूलों की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की, गलियों को पक्का किया, जिनकी बहुत वैल्यू है लेकिन कोई पंचायत उनकी मैन्टेनेंस के लिए कुछ नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप वह स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाये हैं वे आने वाले 10 साल में धरा गही हो जाएंगे और फिर लोग डिमांड करेंगे कि पंचायत घर बनाओ, पटवारखाने बनाओ, चौपाले बनाओ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा फौजियों का इलाका है। हर गांव में अच्छी संख्या में आपको एक्स-सर्विसमैन मिलेंगे। उनकी आप लैंड फोर्स बनाएं और जिन गावों में ये असेट्स किए गए हैं उनको मेन्टेन करने की जिम्मेदारी उनको दी जाए। अगर वे पंचायत घर से हटकर हों तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरह से मैं पी0 डबल्यू0 डी0 मिनिस्टर से कह रहा था कि इसी तरह की जिम्मेदारी आप वहां लगाओ जैसे कि किसी गांव में बीच में से सड़क निकली है, उस सड़क की रेजिंग के हिसाब से दोनों तरफ नाली बनें। इनका कहना ठीक था कि नाली का रख रखाव नहीं होगा तो उनके रख रखाव का काम भी लैंड

फोर्स कर सकती है इससे जो करोडो अरबो रुपये के असैट्स खडे कर दिये है, उनका रख रखाव कर सकने मे हम सक्षम हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब आप बैठ जाइए।

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर मुझे एक मिनट का समय और दे दें। मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी कहना चाहूंगा। प्र न काल के दौरान मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ ऐसे बड़े गांव जिनकी आबादी 5 हजार से उपर है, को टेकअप कर रहे है। जिन वाटर वर्क्स से इनको पानी मिलता है आप उसकी मात्रा बढ़ाएं। अगर वहां पानी की मात्रा बढ़ेगी तो हम प्राईवेट कनैक्टन भी देंगे। यह अच्छी बात है लेकिन अगर आप ने उस पानी की निकासी का पूरा इंतजाम नहीं किया तो वे गांव नर्क बनकर रह जाएंगे। आप देखे कि जहां भी टूटीयं लगी हुई है, स्टैण्ड पोस्ट लगे है हां गलिया सडती है। मेरा सरकार से यह कहना है कि आप जिस गांव को भी इस लेवल पर टेकअप करो ओर यदि उसके पानी को 70लीटर से 100 लीटर में परिवर्तित करना हो तो उसका कंपोजिट प्लान होना चाहिए। हर गांव में दो लाख रुपये मंत्री महोदय दे आते है कि गलियां बनाओ। अब उस गांव के सरपंच की मर्जी है कि वह किसी गली को बनाने के लिए छांटता है। वह उपर से गली बनाना भुरु कर देता है इससे जो पिछली गली बनी हुई थी, वहा सारा पानी खडा हो जाता है। जैसे आपने सौ गांव, पचास गांव या पांच सौ गांव छांटे है तो उसका टोटल कंपोजिट मास्टर प्लान तैयार करना पडेगा। जिसमें स्ट्रीट लाइट,

गलियो को पक्का करना, सीवरेज की फ़ैसिलिटी देना और स्कूलो को कुछ करना चाहिए। राम बिलास जी बैठे नहीं है मैं उनहे कहना चाहता हूं कि राम पाल माजरा जी जो बात कही है वह ठीक है आज लोगो का रुझान पब्लिक स्कूलो की तरफ है। हमारे सिस्टम मे कोई कमी है क्योंकि स्कूल का जो टीचर होता है वह साल मे पांच महीने पढाता है और सात महीने छुटटीकरता है। उस टीचर के ये सात महीने युटीलाईज करने के लिए या तो उसको कोई रिफ्रे र कोर्स कराया जाये या फिर कोई ओरिएयटें इन कार्स कराया जाये ताकि वह अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन बच्चो को दे सके। मेरे अपने गाव मे जो स्कूल है उसमे विद्यार्थी तो 95 है लेकिन टीचर 22 है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चो को पब्लिक स्कूलो मे दाखिल करा रहे है। सरकारी स्कूलो मे तो सिर्फ वह गरीब ही अपने बच्चो को पढाते है जो पब्लिक स्कूलो की फीस अदा नहीं कर सकते। चाहे सरकारी स्कूलो मे एजुके इन की क्वालिटी कुछ भी हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह स्कूलो को अपग्रेड करने की बजाय एजुके इन की क्वालिटी मे सुधार करे क्योंकि डिग्री देने मात्र से प्रदे 1 मे बेरोजगारो की संख्या को बढ़ाना है। बढ़िया एजुके इन देने से रोजगार के साधन बढंगे। इनही भाब्दो के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाशण समाप्त करता हू। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by one hour.

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by one hour.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान
(पुनरारम्भ)

श्री संपत सिंह: स्पीकर सर, मैंने डिमाण्ड की कट मोशन पर नोटिस दिया हुआ है। (विघ्न)

Mr. Speaker: No please you are requested to take your seat.

Shri Sampat Singh: Speaker sir, I want your ruling.

Mr. Speaker: I would not allow you to speak now. You have already spoken today.

Sh. Sampat Singh: it is against the Rules Speaker sir, *****

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय आपने खुद कहा है कि डिमाण्ड पर अगर कोई सदस्य बोलने से रह गया हो तो वह बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष: मैंने यह कहा है कि जिस सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है, वह बोल सकता है। मैं अब भी इस बात पर स्टैंड करता हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। पहले हालात कुछ और होते थे क्योंकि पहले डिमाण्डज पर चर्चा 2-3 दिन तक होती थी लेकिन अब डिमांडज पर चर्चा एक दिन ही रखी गई है। The Speaker has the privilege to apply guillotine. प्रोसीजर यह है कि पहले ग्लोटीन आती है, उसके बाद डिमांडज पर चर्चा होती है। लेकिन यहां तो ग्लोटीन आने से पहले ही चर्चा खत्म कर दी गई है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को स्मरण करना चाहता हूँ कि 1993-94 की डिमांडज अलग थी और इस वर्ष 198-99 की डिमांडज अलग है। भुरु मे ही आपने सारे सदन को यह कहा था कि जो माननीय सदस्य एक बार भी सदन मे नहीं बोला हो, आज चाहे रात हो जाए, लेकिन उस को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। इन्होंने ही डिमांडज पर बोलना प्रारंभ किया था।

Sh. Birander Singh: if you put any demand to the vote of the House then you would also put the motion and on the opportunity we should be allowed to speak. That is the practice.

श्री अध्यक्ष: आप भी कट मो इन और डिमांडज दोनो पर बोल चुके है।

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी सम्पत सिंह बोल रहे है, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनी राम गोदारा: अध्यक्ष महोदय, संपत सिंह जी अगर नहीं माने तो बात और है लेकिन आपने तो इनको पहले यह कहा था कि ये जितना समय लेना चाहते है वह चाहे कट मो इन पर ले लो या डिमांडज पर ले लो।

श्री अध्यक्ष: संपत सिंह जी, आप अपनी पार्टी के समय को टोटल कर के देखे तो पता लगेगा कि आप लोग कितने समय बोल चुके है।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, किसी सदस्य को बोलने के लिए अनुमति देना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आप चाहे तो लिखे हुए को भी कटवा देंगे। आप तो कानून बनाने वाले है। हम आपकी रुलिंग चाहते है। आप अपने फैसले को फौरन बदल देते हो। हम आपकी रुलिंग चाहते है कि जिन लोगो ने कट मो इन दिए है, क्या आप उनको बोलने देंगे अथवा नहीं? आप तो कानून बनाने वाले है। (विघ्न)

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कट मोशन पर बोलने की बात कर रहा हूँ।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ये डिमाण्डज पर बोल चुके हैं। जब कट मोशन आएंगी तो वोटिंग करा लीजिए।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम तो टैक्नीकल बात में पड़ गए हैं। पांच माननीय सदस्यों के कट मोशन पर ही है। उनकी डिमाण्डज पर एक रुपये का कट लगाने की बात थी। इन पांच सदस्यों में खुर्शीद अहमद, रामपाल माजरा व श्री अशोक कुमार भी थे। जिन में से 4 माननीय सदस्य तो कट मोशन पर बोल चुके हैं। (विधन) आप सब डिमाण्डज व कट मोशन पर इकट्ठे बोले हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, आज डिमाण्डज पर बड़ी संजीदा बहस हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। सम्पत सिंह जी बहुत अधिक तैयारी से बोले हैं। उन्होंने हमारी बात की ताईद की है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में आज के दिन 863 मैगावाट बिजली अतिरिक्त उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। सतविन्द्र राणा जी ने कानून और व्यवस्था की बात की। खुर्शीद अहमद जी द्वारा भी कल बेरोजगार नौजवानों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। मैंने पहले भी बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने मनीराम गोदारा जी की अध्यक्षता में इस बारे में एक कमेटी बनाई हुई है। जिसके सदस्य ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हम हैं। काफी एक्सरसर्ज करके सदन में जो बातें आई हैं उनको ध्यान में रखकर हम जल्दी ही इसका निर्णय करने

जा रहे हैं। राव नरेन्द्र सिंह ने अटेली के बारे में बात कही। रामपाल माजरा ने शिक्षा के संबंध में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि शिक्षा का स्तर है उसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यह बात सही है कि जब तक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी और तब तक बच्चे की आगे की पढ़ाई में रुचि नहीं बनेगी। पहले हमने प्राथमिक शिक्षा 4 जिलों में चलाई जब तक उन 4 जिलों में प्राथमिक शिक्षा की अच्छी परफॉरमेंस आई तो तीन अतिरिक्त जिलों में हमने प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। कुछ साथियों ने एक बात कही कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से पढ़ाने का प्रावधान किया जाए। यह एक मौलिक सी बात है। मैं शिक्षा के संबंध में ऐसा मानता हूँ कि बच्चे को भुरु में अपनी मातृ भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। अब तक जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या जो शिक्षा के संबंध में चिंतक और दार्शनिक हुए हैं उन सब की भी यही मान्यता है कि पहले 5-6 साल बच्चे को मां के दुध की भाषा में शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो वह बच्चा सरलता से और प्राकृतिक रूप से उनको ग्रहण करता है। यह प्रकृति का नियम है। आजादी से पहले यह गलत फहमी नहीं थी लेकिन आजादी के बाद देश में जो टाई-फाई हुई है उसके बारे में बड़े बड़े लोगों में गलत फहमी बैठ गई है कि अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक लोगों की भाषा है। इसलिए अंग्रेजी अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। जबकि यह गलत धारणा है। क्योंकि गौरवाच्योव अंग्रेजी नहीं बोलता था, जापान में

अंग्रेजी नहीं बोली जाती। जर्मनी के रेलवे स्टे 1न या बस स्टेण्ड पर आप भुखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे यदि आप वहां पर अंग्रेजी में पानी मांगेंगे क्योंकि कोई भी आपको पानी नहीं देगा। अंग्रेजी में रास्ता पूछेंगे तो कोई आपको रास्ता नहीं बतायेगा।
(तोर)

श्री वीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: डा. वीरेन्द्र पाल जी, आप पहले बताएं कि प्वायंट आफ आर्डर किस चीज पर होता है उसके बाद ही आप प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना। (विघ्न) डा0 साहब आप बैठें।

श्री राब बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, डा0 वीरेन्द्र पाल जी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से प ु चिकित्सा में डॉक्टरेट किया है। ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। शिक्षा का मामला हर आदमी के बस का नहीं है। यह बहुत गहन बात है। जहां तक बच्चों के मनोविज्ञान की बात है वह बहुत सूक्ष्म होता है, बड़ा कम्पलीकेटिड होता है, बड़ा डैलीकेटिड होता है। इसके बारे में पूरी दुनिया में बहस चल रही है और विचार किया जा रहा है कि बच्चों के बस्तों का बोझ कैसे कम किया जाए। भारत की जो गुरुकुल प्रणाली की पद्धति थी, आज पूरी दुनिया उस पर विचार कर रही है। आज स्कूलों में भी नर्सरी, के0 जी0, यू0 के0 जी0 की कक्षाएं भुंरु कर दी जाएं तो इससे बच्चों का मूल विकास रुक जाएगा। पब्लिक

स्कूलों में नर्सरी, के जी, यू के जी की क्लासिज भुरु करने से बच्चों का मूल विकास रुक गया है। आज पूरी दुनिया मानने लगी है कि बच्चों को पोनी बना दिया गया है इसलिए हम इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए इस बात को पसंद नहीं करते कि पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी पढाई जाए। हम हरियाणा प्रदेश में बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी पढाने के हक में नहीं हैं

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं राम बिलास भार्मा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले दिन से ही यह अनाउंस कर दिया था कि हम पहली जमात से बच्चों को अंग्रेजी पढाने का समर्थन नहीं करते तो यह बात आपकी बी० जे० पी० के लिए कम्पलीके टन किएट करेगी क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने प्रदेश में पहली जमात से बच्चों को अंग्रेजी पढानी भुरु कर दी है और वहाँ पंजाब सरकार का बी० जे० पी० समर्थन कर रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, पंजाब की बात पंजाब वाले जानें लेकिन हरियाणा प्रदेश में पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी पढाने का हमारा विचार नहीं है। स्पीकर साहब, राजीव गांधी ने पहली कक्षा से अंग्रेजी पढी थी इसलिए वे अणु विस्फोट नहीं कर सके लेकिन हमारे प्रधान मंत्री वाजपेयी जो गुरुकुल में पढे थे इसलिए उन्होंने अणु विस्फोट कर दिया। स्पीकर साहब, हम अपनी शिक्षा प्रणाली को अपनी संस्कृति को दुनिया की शिक्षा प्रणाली से हीन नहीं मानते। स्पीकर साहब, सदियों से भारतवर्ष

ज्ञान विज्ञान का केन्द्र रहा है। जो नालन्दा ओर तक्षशिला अखण्ड भारत के विविध विद्यालय थे उनमें पूरी दुनिया के आदमी पढ़ने आते थे। चीन के भी हांगसांग और फिहांगदा निक यहाँ पर आए थे उन्होंने लिखा है कि इस देव भूमि को देखने का हमारा 20 साल की जिंदगी का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने भारत के बारे में जो इतिहास लिखा, वह अलग बात है। हम प्राचीन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हरियाणा प्रदेश में बच्चों पर पहली कक्षा से अंग्रेजी नहीं थोपना चाहते। जो मौजूदा पढाई है यदि उसको पढ़ लिया जाए तो बहुत है। स्पीकर साहब, मेरे कुछ साथी जिनमें रिसान सिंह जी एवं हुडडा जी थे, ने एक बात कही कि सोसायटियों की रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी गई है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। रामपाल माजरा जी ने कूलों के निरीक्षण की बात कही। हमारे सभी अधिकारी चाहे खण्ड शिक्षा अधिकारी हो, सब डीविजन शिक्षा अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो या प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हो सभी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। हमने उनको आदेश दिए हुए हैं कि उनके अंतर्गत जितनी संस्थाएँ आती हैं उनका छः मास के अंदर एक बार निरीक्षण अवश्य करें और उसकी रिपोर्ट करें। हमारे यहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा देने बारे जब भी बातचीत होती है तो उसमें हम खण्ड शिक्षा अधिकारी तक को शामिल करते हैं और उस समय इन सारी बातों पर विचार होता है। एक साथी ने सढौरा में 10+2 का स्कूल बनाने की बात कही क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर प्राइवेट

संस्थान ही है। असंध मे भी इसी तरह का स्कूला बनायेजाने की बात यहां पर कही गयी। एक दो जगह से और भी इस तरह की मांग आई। मैने उनको कहा कि 10+2 का स्कूल अपग्रेड करने के लिए कुछ भारते होती है अगर आप उनको पूरा करवा दे तो हम आपकी इन बातो पर विचार कर लेंगे। यहां पर कुछ साथयो ने जिनमे वीरेन्द्र पाल जी भी थे यह भी कहा कि वि बैंक से कर्जा क्यां ले रहे है। विकास के लिए सरकार भारत सरकार से कर्जा लेती है कोई किसी और संस्थान से कर्जा लेता है। कर्जा देने वाला भी देने से पहले यह देखता है कि जिसको कर्जा दिया जा रहा हैक्या वह वापस चुकाने की स्थिती मे है या नही? तभी जाकर वह कर्जा देता है। हमने वि व बैंक से एच0 एस0 ई0 बी0 के लिए जो कर्जा लिया उसमे वि व बैंक ने देखा कि यह बोर्ड कर्जा चुकाने की स्थिती मे है या नही। इसके बाद ही उसने कर्जा दिया। वे इस बात को अच्छी तरह से देखते है कि कर्जा लेने वाला ईमानदार है और सिंसियर है या नही इसके बाद ही वे कर्जा देते है। यहां पर किसानो को पास बुक देने की बात भी कही गई। इसबारे मे हमारे राजस्व मंत्री जी कह रहे है कि इसे जल्दी ही लागू करेंगे। खु र्फिद अहमद जी ने कहा कि रामचन्द्र बैन्दा को सरकार ने कुछ लीज पर जमीन दी है। हमने उनको कुछ लीज पर नही दिया। उनका 30 साल पुराना करोबार है। यहां पर मसानी बैराज की बात कही गई। इसी प्रकार से दोहान एवं कुशणावती नदियो की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि रिवाडी के इलाके के और उसके आसपास के इलाके को पानी नही मिल पा

रहा है और इन नदियों में 15 वर्षों से पानी बिल्कुल नहीं आया। कुछ साथी कहते हैं कि इनमें पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि राजस्थान वालों ने इनमें बांध बना लिये। इस बारे में 2-3 बार हमारी उनसे बातचीत हुई है। भैरो सिंह जी से मेरी भी बात हुई है। वे कहते हैं कि हमने इन नदियों पर कोई पक्का बांध नहीं बांधा। इसलिए आप एक बार जाकर मौके पर देख लें कि कहां कहां पर बांध बनाए हुए हैं, फिर उन पर बैठकर एक ज्वायंट मीटिंग कर लेंगे। इस ज्वायंट मीटिंग के बारे में तो सी० एम० साहब ही बतायेंगे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा संबंधी जो मुद्दे यहां पर उठाये गए थे, उनके बारे में मैंने आपके सामने निवेदन कर दिया है, धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, डिमांडज के उपर आज जिन जिन बातों पर चर्चा हुई उनमें से चौ० संपत सिंह जी ने भाष्य एक बात यह भी कही कि पानीपत थर्मल प्लांट में 210 मैगावाट का छटा प्लांट जो हम लगाने जा रहे हैं उसका इ बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय बजट में इसका प्रोविजन इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली बोर्ड अपने साधन खुद जुटाता है। इसके उपर 634 करोड़ रुपये लगेंगे जिसमें से 320 करोड़ रुपये का लोन पावर फाईनैस कारपोरेट्स को जुटाता है और 117 करोड़ रुपये पब्लिक से लोन की भावना में बिजली बोर्ड ने रोज कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, चौ० संपत सिंह और इनकी सरकार 1989 में जब मीनरी खरीद के डाल गये थे तो इसके

बक्से को इनकी खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि पैसे लगते लेकिन उस मीनरी को अब हमने खोला है। उस मीनरी की कीमत 82 करोड़ रुपये थी और उसके उपर उन्होंने 90 करोड़ रुपये ब्याज मांग लिया। हमने उनसे कहा कि इसका ब्याज कम कर दो। उनकी बहुत समय से पेमेंट रुकी पड़ी थी और कोई पेमेंट वापिस नहीं कर रहा था इसलिए उन्होंने कहा अगर आप लोग ब्याज की रकम एक साथ दे देंगे तो हम यह ब्याज कम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने उनको 82 करोड़ रुपये रकम और 35 करोड़ रुपये ब्याज के एक साथ दिये। यह पैसे हमने पब्लिक से रेज करके दिया। इसके अलावा जो बाकी कसर रहेगी, वह भी बिजली बोर्ड पब्लिक से ही रेज करके पूरी करेगा, इसलि बजट मे इसका प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि इस छठे प्लांट पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के इन भाईयो मे थोडी सी गडबड है कि ये चीज के नजदीक से निकल जाते है और वह चीज इन्हे दिखाई नहीं देती तो इसमे मेरा क्या कसूर है? अध्यक्ष महोदय, इस प्लांटका कुलिंग टावर बनने लग रहा है उस पर बडी तेजी से काम चालू है और बी० एच० ई० एल० वालो ने मौके पर टरवाईन और बायलर पर काम चालू कर दिया है, एम० आई० टी० सी० भी टावर्ज पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्लांट पर 14 टावर्ज बनने है और हर टावर की उंचाई 110 फुट होगी। इनमे से 4 टावर 110—110 फुट उंचे बनकर तैयार हो गये है लेकिन अगर चौ० संपत सिंह को ये दिखाई नहीं देते तो मै

इसमें क्या करूं, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिविल वर्क भी इस प्लांट प बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। (विघ्न)

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय 1988-89 के एच० एस० ई० वी० के जो एनुअल फाईनें ियल स्टेटमेंट बजट अस्टीमेटस है, इसमें आप बताये कि क्या आपने एक भी नये पैसे का प्रोविजन इसके लिए रखा है? चाहे आप पब्लिक से लोन ले, चाहे पब्लिक फंड रेज करे या चाहे बाहरी इंस्टीच्यु ांज से फंड ले अगर आपने ओन गोइंग स्कीम में कहीं पर भी छठे यूनिट का जिक्र किया है तो आप बतायें? (विघ्न)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ये सुनेंगे तो ही मैं बताऊंगा, आप इन्हे कहे कि ये ध्यान से सुनें। अध्यक्ष महोदय, हम आ ाा करते हैं कि हमारा यह छटा यूनिट अगले साल दिसम्बर तक पूरा हो जायेगा। इन्होंने यह भी कहा कि युनिट एक से चार तक 100 करोड रुपये में ठीक होकर तैयार हो जाते हैं मगर एच० एस० ई० ने इसका 400 करोड रुपये का ठेका दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने यह ठेका बड़ी छानबीन करके दिया है। इसके लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई और उस सब कमेटी ने सबको बुलाया। इसमें एच० एस० ई० वी० को भी बुलाया, दूसरी सब कंपनीज को भी बुलाया। यह एक ग्लोबल टैंडर था। बाद में यह टैंडर जर्मनी की ए० बी० बी० कंपनी को दिया गया है। इसमें 300 करोड रुपये के करीब खर्चा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें

इसका मोर्डेनाईजे इन भी हो जायेगा, रिफर्निंसिंग भी हो जायेगी, लाईफ एक्सटें इन भी हो जायेगी यानी सब काम हो जायेंगे। जब से चारो प्लाट्स हमारे तैयार हो जायेगे तो यह 300 करोड रुपये का खर्चा हमारा एक साल मे ही पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अब ये चारो प्लाट्स 26 से 30% प्लांट लोड फ़ैक्टर पर चल रहे है लेकिन ए0 बी0 बी0 की कंपनी हमको मिनीमम 80% प्लांट लोड फ़ैक्टर पर इनको चलाकर देगी। इस तरह हमारी बिजली 250 से 270 मैगावाट बढ जायेगी। इसके अलावा 110-110 मैगावाट के हमारे जो 4 प्लांट्स है वे 18-118 मैगावाट के हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैने आपको बताया कि यह काम ग्लोबल टैंडर से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्होने कहा कि यमुना के प्रोजैक्ट के लिए इस साल बजट मे कोई प्रावधान नही रखा गया। (विधन)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैने यह कहा था कि कम रखा गया है। मैने भायद 22 या 28 करोड बताया था जो कि कम है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैने इंडिपेंडेंट तौर पर ग्लोबल टैंडरज मांगे है और ग्लोबल टैंडरज की कार्यवाही अब से पहले भुरु हो चुकी है। कण्डी इनज के मुताबिक ग्लोबल कार्यवाही भुरु हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से चौधरी संपत सिंह जी ने कहा कि किसानो के 12 हजार ट्यूबवैल्ज के कनैक्ट इनज घट गए है। अध्यक्ष महोदय, इससे भी दो तीन बातें

है। कुछ आदमी तो इन भाईयो के चक्कर मे आ गए और बिजली के बिल जमा नही करवाए जिसके कारण उनके कनेक 1न्ज कट गए। अब ये उन्हे कहते है कि कुण्डी लगा कर काम चलाओ। दूसरी बात इनके घटने की यह है कि कुछ लोग डीजल के इंजन लेकर आए और वे डीजल के इंजर पर डिपेंड हो गए क्योंकि हमारे यहां बिजली कम मिल रही हैं और तीसरे इनमे घटने की वजह यह भी है कि कुछ ऐसे किसान है जैसे कि अहीरवाल के एरिया के लोग है उनहे पूरे साल बिजली की जरूरत नही होती है उन्हे भी अब मिनिमम पैसा देना पडेगा, वे लोग 3-4 महीने बिजली इस्तेमाल करते है। अध्यक्ष महोदय अब हम उनको सुविधा दे रहे है कि मर्जी आए तो मीटर लगवाओ मर्जी आए तो मीटर कटवा लो हम फसल के समय उनको दोबारा मीटर लगा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ कनेक 1नज इस लिए भी कट गए है।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अहीरवाल मे झज्जर जिले का कुछ एरिया हे और मेरा हलका बादली भी सेम से अफैक्टिड एरिया है। झज्जर सब डिवीजन कोसली का इलाका सेम से प्रभावित है वहां पर सेम की जमीन है। (विधन) मै यह चाहता हूं कि जिस जिस इलाके मे मार्च और अक्टुबर के बीच मे बिजली की खपत नही है, वहां पर भी यह सुविधा प्रदान करें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय इन इलाको मे भी हम सुविधा दे रहे है। अगर किसान अपने ट्यूबवैल के लिए मीटर लेना चाहता है तो उसको मीटर लेने की सुविधा है इसमे हमें कोई

ऐतराज नहीं है और मीटरज लगाए भी जा रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, हमारा ट्रांसमी लन तथा डिस्ट्रिब्यू लन का सिस्टम बहुत कमजोर है उसको स्ट्रेंगथन करने के लिए मैंने आपके जरिये कल भी सदन को बताया था, आज फिर उसको दोहरा देता हूं। 1999-2000 तक टयूबवैल के कनेक्शन देने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौधरी संपत सिंह जी ने कहा था कि लाईन लोसिज 60% है (विघ्न) मगर हमारे लाईन लोसिज 33% है। अध्यक्ष महोदय जब पूरी सप्लाई चालू हो जाएगी तो इसमें सुधार हो जाएगा। हमने कन्ज्यूमर्ज की चैकिंग का कम्पैन चलाया हुआ है और हमने 655615 कन्ज्यूमर्ज की चैकिंग की है। इनमें भी हमने ज्यादातर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र की चैकिंग की है जहां पर थैफ्ट ज्यादा होती है। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया है कि लाईन लोसिज 33% है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद माना है कि बिजली के मामले में किसानों का कनेक्टिड लोड 29% है जबकि इन्होंने इस साल 43% बिजली की खपत दिखाई है। 29 प्रतिशत हमारा कनेक्टिड लोड है लेकिन उसके बाद हम उसको इस्तेमाल नहीं करने देते हैं क्योंकि रेट बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक बी० एच० पी० पर एक ऐडिशनल हार्स पावर की मोटर मिल जाए तो उसको पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है। स्पीकर साहब, इसका मतलब है कि वह

कनैक्टिड लोड से फालतू बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वह पकडा जाता है तो 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना उसको लगा दिया जायेगा। स्पीकर साहब, इस तरह से उसके एक तिहाई दिन ऐसे होंगे जो अन-यूटिलाईज हो जाएंगे और दो तिहाई दिन ही यूटिलाईज रहेंगे फिर तो अपने आप ही बिजली की चोरी होगी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने थैपटके 14566 केसिज डिटेक्ट किए है जिमे 11782 केसिज मे एफ0 आई0 आर0 लाजें की है। हमने 14 करोड 87 लाख रुपये की पैनल्टी इम्जोज की है। मई 1996 से मार्च 1998 तक हमने दो लाख बिजली के नए मीटर्ज इन्सटाल किए है और अगले 2 सालो मे साढे चार लाख और नए मीटर्ज हम लगा देंगे जोकि थैपट प्रूफ होंगे। हम मोटे तौर पर लाईन लोसिज का ब्रेक अप लगाते है। हाई टैन् इन लेबल पर 10 प्रति ात टैक्नीकल लोस,लो टैन् इन पर 8 प्रतिशत लोस और थैपट से हम 15 प्रति ात टैक्नीकल लोस लगाते है। जो यह थैपट का टैक्नीकल लोस है वह 15 प्रति ात से बढकर 18 प्रति ात हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी संपत सिंह जी ने एक बात कही है कि मै इनके वक्त मे केवल 55 मैगावाट बिजली ही छोड कर गया था बाकि तो सब इन्होने ही लगाई है। इस बारे मे मै इनको बता देता हू। अध्यक्ष महोदय, 18-4-79 को 8-8 मैगावाट के दो हाईडल प्रोजैक्टस चालु हुए थे जो कुल मिलाकर 16 मैगावाट बनते है।इसके अलावा इनके वक्त मे पानीपत

थर्मल प्लांट का 210 मैगावाट का पांचवा यूनिट आया था जिसका प्रोडक्शन चौधरी भजन लाल के वक्त में शुरू हुआ था और मेरे वक्त में भी चलता रहा था। इसके अलावा इनके टाइम का मुझे और तो कुछ मिला नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे वक्त में मैं 236 मैगावाट की इन्स्टाल कपैस्टी छोड़ गया था। उसमें 16 मैगावाट के दो हाईडल प्लांट्स, 55-55 मैगावाट के दो प्लांट्स फरीदाबाद में और 110 मैगावाट का एक प्लांट पानीपत थर्मल प्लांट मैं छोड़ कर गया था। अध्यक्ष महोदय, अगर ये इनका जोड़ लगा तो यह 236 मैगावाट बनता है। (विघ्न)

श्री संपत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये हमें यह बता दें कि जनरेटर किसके वक्त में आई थी?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ये भी मुझे यह बता दें कि 13-6-86, 1-6-87, 22-11-74, 6-3-76 और 11-1-87 को मुख्य मंत्री कौन था? आप सच्ची बात तो मान लिया करें। आप अपना भाषण कितना लम्बा कर दें, मुझे उसे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन आप सच्ची बात मान लिया करें। अध्यक्ष महोदय, चौधरी संपत सिंह जी ने कह दिया कि सात सौ करोड़ रुपये की सबसिडी का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मैं इनका ध्यान मैमोरैंडम आफ एक्सपलानेटरी नोट आन बजट की ओर केन्द्रित करना चाहता हूँ। आप इसमें पेज नम्बर 15 पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि:—

“During 1997-98 subsidy of Rs. 679.94 crore was provided to the Board. During the year 1998-99, the state

Govt. is contemplating to provide Rs. 700 crores as Rural Electricity subsidy out of which rs. 364 crores have been provided as cash subsidy.”

श्री सम्पत सिंह: फिर यह बिजली बोर्ड ने झूठ का पुलिन्दा क्यों छाप रखा है? आप बिजली बोर्ड का ऐस्टीमेट देख लें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, यह 700 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड ने नहीं देना है बल्कि यह स्टेट गवर्नमेंट को देना है।

श्री संपत सिंह: स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ और लिखा है। आप इसको पढ़ लें।

श्री बंसी लाल: आप इसको घर जाकर पढ़ लेना।

श्री सम्पत सिंह: जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, वह भी इसमें लिखा हुआ है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक जो हम बिजली दे रहे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 22-7-98 को हमने 427.60 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को 356.15 लाख यूनिट बिजली दी। इसी तरह से इस साल 23 तारीख को हमने 442.29 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 380.10 लाख यूनिट बिजली दी। इसी प्रकार से 24-12-98 को हमने 433.67 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 390.49 लाख

यूनिट बिजली दी। इसी तरह से इस साल 25 तारीख को हमने 430.05 लाख यूनिट बिजली दी और पिछले साल इसी तारीख को हमने 380.33 लाख यूनिट बिजली दी। इसी प्रकार से इस साल 26 तारीख को हमने 434.69 लाख यूनिटस बिजली दी और पिछले इसी तारिख को हमने 383.17 लाख यूनिट बिजली दी और 27-7-98 को यानी कल हमने 423.92 लाख यूनिट बिजली दी ओर पिछले साल इसी तारीख को हमने 398.05 लाख यूनिट बिजली दी। अध्यक्ष महोदय, हम पूरी मुस्तैदी से बिजली दे रहे हैं, पूरी कोशिश से हम इस बारे में लगे हुए हैं। लेकिन जो ढांचा ये लोग और पहले वाली सरकार छोड़कर गयी थी, उसको सुधारने में हमें कुछ समय लगेगा। कुंआ खोदने के बाद तो वह मुक्ति कल से ही भरता है। मैं इनका खोदा हुआ कुंआ भरने में लगा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं। श्री नफे सिंह राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हत्यारों को संरक्षण देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री से जब दिल्ली में एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था तब मैंने कहा था कि चाहे बीस आदमी मर जाएं मैं क्या ठेकेदार हूँ। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मैं या मेरा कोई भी रिश्तेदार किसी मूलजिम को कभी नहीं छिपाता। यह काम तो इनका ही है। ये ही ऐसा काम करते हैं। मेरे पास एक डैपुटेशन जरूर आया था। उससे पहले वाले दिन भाम को इन्होंने डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) को फोन किया था कि हमारे मूलजिम को सी0 एम0 या उनके लडके ने घर में छिपाया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जब उनका टेलीफोन हमारे पास आया, उससे पहले ही वह मुलजिम हमरि मला मे गिरफतार कर चुके थे। जबकि वह इनको मेरे घर बता रहे है। बाद मे मेरे पास दस या बारह आदमियो के साथ एक लम्बा चौडा आदमी भी आया था और मेरे से मिलने के बाद वे सीधे चौधरी देवीलाल जी और चौटाला जी के घर गए। लेकिन उनमे से दो या तीन आदमी फिर अगले दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे से गलती हो गयी। हमने एम० एल० ए० और उस लम्बे चौडे आदमी सरंपच के बहकाने से ऐसा कह दिया था। परंतु अब हम उसके लिए माफी चाहते है। अध्यक्ष महोदय, जितना " " होता है वह सब यही सिखाते है क्योंकि इनका काम यही है और इनको कोई काम है ही नहीं। इसके अलावा असैम्बली के दूसरे मैम्बर्ज ने और भी बातें कहीं।

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, " " लफज क्या पार्लियामेंटरी है। ये जो चाहे कह दे तब तो ठीक है लेकिन राम बिलास जी को हमारी इस बात पर भी आपत्ति है कि गुमराह भाब्द कार्यवाही से हटा दिया जाये जोकि उर्दू का लफज है। लेकिन ये हमे " " की बात करते रहते है।

श्री बंसी लाल: कोई बात नहीं इस भाब्द को निकाल दो।

श्री अध्यक्ष यह भाब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री बंसी लाल: मैम्बर साहेबान ने भी कई बातें उठाई है जो बातें इन्होंने उठाई हम उन सबके उपर गौर करेंगे और जो बातें जायज है उनको हम करेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया बहादुरगढ़ के 20 आदमियों का एक प्रतिनिधिमंडल इनसे दिल्ली में दिनांक 18-4-98 को मिला था। उस प्रतिनिधि मंडल में हरियाणा विकास पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, भी शामिल थे, पूर्व मंत्री भी शामिल थे और भाजपा के लोग भी शामिल थे।

श्री अध्यक्ष: इसमें प्वायंट आफ आर्डर क्या है?

श्री नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वह असत्य है। (गौर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by one hour.

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by one hour.

वर्ष 1998-99 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now the demands and cut motions will be put to the vote of the Housr.

First of all I will put the cut motion on the demands to the vote of the House and then i will put the demands to the vote of the Housr.

Demand No. 1

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 28462000- for revenue expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 28836000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Demand No. 2

That Demand No. 2 of Rs. 1614211000 on account of General Administration be reduced by Re. 1/-.

The motion was carried.

Demand No. 3

That a sum not exceeding Rs. 1763073000- for revenue expenditure and Rs. 100000000- for capital expenditure be granted to the Governor to dfray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 253584400- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 3- Home.

The motion was carried.

Demand No. 4

That Demand No. 4 of Rs. 971780000 on account of Revenue be reduced by Re.1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 311423000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 660355000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 4- Revenue.

The motion was carried.

Demand No. 5 to 7

That a sum not exceeding Rs. 195884000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 228818000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 5- Excise & Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 2759106000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 2654192000- already

voted on account) in respect of charges under Demand No. 6- Finance.

That a sum not exceeding Rs. 3160818000 for revenue expenditure and Rs. 933000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 4329758000- and capital expenditure amount of Rs. 467000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 8 of Rs. 4941345000 on account of Buildings & Roads be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 2048549000 for revenue expenditure and Rs. 1536145000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 998503000- and capital expenditure amount of Rs. 347348000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 8- Building & Roads.

The motion was carried.

Demand No. 9

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, हमारे शिक्षा मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। चण्डीगढ़ कैपिटल के बारे में बार बार जिक्र आता है कि हम फलां एरिया लिए बगैर चण्डीगढ़ को नहीं देंगे। एक एक करके अलग अलग अमैडमेंट भारत सरकार से आते हैं जिनकी वजह से हमारा हौंसला और भी बढ़ जाता है। मैं सिर्फ एजूकेटन के बारे में जिक्र करूंगा। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, डी० पी० आई और विधान सभा के दो सदस्य सीनेट के मैम्बर चुने जाते थे। अब भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

“The Ministry of Home Affairs, Government of India vide a Gazette notification dated October 27, 1997 (copy enclosed) has amended the Punjab university Act. vide above notification the membership of the Punjab University Senate in respect of the following has been permanently terminated.”

जो ये मैंने नाम बताये हैं उन सदस्यों के नाम रजिस्टर्ड काउंसिल के लिए डिलीट कर दिये गये हैं जिसके कारण पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाण प्रदेश की दखलअंदाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या वर्तमान सरकार ने इसके बारे में कोई एतराज किया है? क्योंकि केन्द्र में गृह मंत्री अभी तो आडवाणी जी हैं क्या उनको इस बारे में कोई रिप्रैजेंटेशन दिया है उनको कोई रिक्वेस्ट की है कि हमारा कलेज खत्म हो गया है?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ठीक कह रहे हैं। इस तरह का एक कम्यूनिक्वैशन हमारे पास भारत सरकार का आया है उसके बाद 25 तारीख को मैं भारत सरकार के गृहमंत्री जी से मिलकर आया हूँ तथा अगली चार तारीख को हम प्राईम मिनिस्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार को लिखा है। हमने अपना प्रोटैस्ट दर्ज करा दिया है और मैं इस सदन को आवासन देता हूँ कि हम इस मुद्दे को दुरुस्त करा लेंगे।

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 9 of Rs. 13784817000 on account of Education and Roads be reduced by Rs. 1-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 7509302000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 6275510000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 9- Education.

The motion was carried.

Demand No. 10

श्री सम्पत सिंह(फतेहाबाद): स्पीकर साहब, मैं लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाहता। मैं होस्पिटल में दी जाने वाले

कंसे इनल मैडीसनज के बारे मे जिक करुंगा। वित मंत्री महोदय ने इस बजट मे स्वास्थ्य विभाग के लिए जो 8 करोड रुपये का प्राविजन रखा है उसके हिसाब से यह हरियाणा की दो करोड जनता को 4 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आता है। इसमे डाक्टरज के अपने जानने वाले रि तेदार भी है और हमारे जैसे वी० आई० पीज० लोग भी है। फिर आप ही अनुमान लगा सकते है कि इतने थोडे बजट मे गरीब आदमी के हिस्से मे तो कुछ भी दवाई नही आयेगी। ये लोग ही बहुत बडी मात्रा मे मैडीसन ले जाएंगे और आम आदमी के हिस्से मे कुछ भी नही आयेगा। गरीबो को मैडीसंज न मिलने से प्राईवेट होस्पिटल वाले गरीब लोगो के भारी को चीर फाड कर छोड देंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि चार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मैडीसन के लिए बजट रखना नाकाफी है।

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 10 of Rs. 7727577000 on account of Medical and Public Health be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 3540770000 for revenue expenditure and Rs. 1097773000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2571147000- and capital expenditure amount of Rs.

516327000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 10- Medical & Public Health.

The Motion was carried.

Demand No. 11

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 11 of rs. 515997000 on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 319464000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 196533000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 11- Urban Development.

The motion was carried.

Demand No. 13

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No 13 of Rs. 2699886000 on account of Social Welfare and Rehabilitation be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 1811715000 for revenue expenditure and Rs. 27836000- for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 851171000- and capital expenditure amount of Rs. 9164000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 13- Social Welfare & Rehabilitation.

The motion was carried.

Demand No. 14

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 92654000 for revenue expenditure and Rs. 918379000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 142117000- and capital expenditure amount of Rs. 3968447000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 14- Food & Supplies.

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker: Sampat Singh Ji, would you like to speak on it?

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद): जी हां, अध्यक्ष महोदय, हम ने जो कट मो एन नं० 9 डिमांड नं० 15 पर दिया है, उसपर मैं बोलना चाहता हूँ। यह सिंचाई विभाग का कट मो एन है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 12 मई 1994 को एक लम्बे अर्से से चले

आ रहे झगडे पर यमुना वाटर समझौता हुआ था। जब यह यमुना जल समझौता हुआ था तो इसका आपने भी विरोध किया था और हम ने भी विरोध किया था। हम ने क्या क्या किया होगा, वह बात अलग है लेकिन चौधरी बंसी लाल जी ने उस वकत जो कुछ कहा था, वे सारी बातें अखबारों में छपी थीं। चौधरी बंसी लाल जी ने कहा था कि यमुना जल समझौता करके भजन लाल ने हरियाणा के साथ विवास धात किया है। फिर ये बोले कि यमुना समझौता हरियाणा के हित में नहीं है। and Bansi Lal demanded Bhajan Lal's sack. भजन लाल के भासनकाल में हरियाणा के हितों की बलि, यमुना जल समझौते से हरियाणा के हितों को आघात पहुंचा, At that time Bansi Lal had stated that Bhajan Lal has sold Haryana's interest, फिर इन्होंने यह भी कहा था कि यमुना जल समझौता के विरोध में हरियाणा विकास पार्टी असहयोग आंदोलन भुरु करेगी। 5 जून को चौधरी बंसी लाल का जवाब आया था कि खुराना की धमकी के आगे भजन लाल ने घुटने टेक दिये। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा एक आंतरिक प्रश्न भी था कि क्या हरियाणा जल समझौता हुआ है तो क्या वह हमारे हित में हुआ है? इस पर मुख्यमंत्री जी ने हां में जवाब दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस वकत तो भजन लाल जी ने घुटने टेक दिये थे, अब क्या इन्होंने भी घुटने टेक दिये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, ये बात का बतंगड बना रहे हैं। जो काम पिछली सरकार कर लेती है वही अगली सरकार पर लागू होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक कंटीन्यूड

प्रोसैस है। 5 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्ज ने बैठकर जो फैसला कर लिया हो, जो एग्रीमेंट उस समय हो गया हो, उससे हम बैंक आउट कैसे कर सकते हैं?

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 15 of Rs. 15324438000 on account of Irrigation be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 2333738000 for revenue expenditure and Rs. 3387828000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 5744700000- and capital expenditure amount of Rs. 2478172000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

The motion was carried.

Demand No. 16

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 16 of Rs. 629182000 on account of Industries be reduced by Rs. 100000/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 295318000 for revenue expenditure and Rs. 149217000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 143424000- and capital expenditure amount of Rs. 41183000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 16- Industries.

The motion was carried.

Demand No. 17

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इस कट मो एन के माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान 3-4 एसे मामले जहां बड़े मेजर स्तर पर सब स्टेण्डर्ड दवाईयां और खाद सरकारी महकमो के द्वारा हरियाणा के किसानो को दिए गए की तरफ दिलाना चाहूंगा। जिनमे से कुछ की इन्कवायरी करवाई गई। कुद आफिसर्ज के खिलाफ इस बारे मे इनकवायरी रिपोर्ट भी आ गई हैं। जींद मे भी इस तरह का एक मामला था जहां पर किसानो को तिलहन की फसल के लिए जिप्सम सबसीडाइजड रेट पर मुहैया नही करवाया गया। चन्द लोगो ने इस बारे मे रिक्वायत की तो ए० डी० सी० जींद ने 17-4-97 को उसकी इन्कवायरी करवाई जिसमे ये रिक्वायत सच पायी गई। ए० डी० सी० जींद ने अपनी रिपोर्ट मे जो लिखा है उसकी चन्द लाईने मैं आपको पढकर सुना देता हू। इसमे लिखा है कि "उपरोक्त विवरण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि समाचार पत्र मे इस

बारे में प्रकाशित समाचारों में लगाए गए आरोपों में सच्चाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिले में तिलहन फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की 90 प्रतिशत अनुदान लाभार्थियों के नाम पर या तो जिप्सम झूठा वितरित किया गया है या उसके नाम से प्राप्त करके उनके खेतों में प्रयोग न करके दूसरे किसानों के खेतों में प्रयोग हुआ है। इसके साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा योजना के अन्तर्गत अनुदान पर जिप्सम प्राप्त करके भी तिलहनी फसलों के लिए उपयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पाया है।" सर, इसमें कई लाख रुपये की हानि हुई। मैंने इस सारे मामले के बारे में इस इन्क्वायरी रिपोर्ट के साथ एक पत्र लिखकर 6 जून 1998 को मुख्यमंत्री जी को भेजा था लेकिन आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। 3-4 ऐसे मामले हैं जिनके एफ़ीडैविट मेरे पास हैं और जिनके बारे में सरकार को लिखा गया है। लेकिन आज तक भी दोषी आफिसर्स के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No 17 of Rs. 2518751000 on account of Agriculture be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 1536667000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 980934000- already

voted on account) in respect of charges under Demand No. 17- Agriculture.

The motion was carried.

Demand No. 18 to 20

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 515179000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 481701000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 53376000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 28407000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 19- Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 600054000- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the amount of Rs. 222961000- already voted on account) in respect of charges under Demand No. 20- Forest.

The motion was carried.

Demand No. 21

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 21 of Rs. 1284731000 on account of Urban Development be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Demand No. 23

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाडी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड नं० 23 पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। जो रिवाडी का बस अड्डा है उसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। उस पानी को बार निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने बेरोजगारों को रूट परमिट्स देने का वायदा किया था लेकिन रिवाडी जिले के किसी भी बेरोजगार नौजवान को पिछले दो साल के अन्दर एक भी रूट परमिट नहीं दिया गया है। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो मैक्सी कैब चल रही है वे बिना टैक्स भरे ही चल रही हैं। लगभग 10 हजार मैक्सी कैब ऐसी हैं जो बिना टैक्स दिए सड़कों पर घूम रही हैं और उनसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार ने यह खुद माना है कि 2597 मैक्सी कैब को रूट परमिट दिए गए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी वे मैक्सी कैब चल रही हैं। वे बकायदा बी० जे० पी० के कार्यकर्ताओं की चल रही हैं। (गोर) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना

चाहूंगा कि जो डीलक्स बसिज है उनकी बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बार बार कहा है कि आप डीलक्स बसिज की सीट्स अच्छी बनाएं और कम्फरटेबल बनाएं। लोग इनमें किराया देकर सफर करते हैं लेकिन उनकी सीटें कम्फरटेबल न होने के कारण लोग उनमें बैठते नहीं बल्कि वे दूसरी बसों में बैठते हैं।

Mr. Speaker: Question is-

That Demand No. 23 of Rs. 5463111000/- on account of Transport be reduced by Re 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 2864535000/- for revenue expenditure and Rs. 295933000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 2113066000 and capital expenditure amount of Rs. 185967000 already voted on account) in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

The motion was carried.

Demand No. 24& 25

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 95000 for revenue expenditure and Rs. 28867000- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 (excluding the revenue expenditure amount of Rs. 5375000- and capital expenditure amount of Rs. 13433000 already voted on account) in respect of charges under **Demand No. 24-Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 2478172000 out of Rs. 6057190000- already voted on account for capital expenditure be transferred to Demand No. 15 to defray charges that will come in the course of payment for the year 1998-99 under that Demand & balance amount of Rs. 3579018000- already stands on account under **Demand No. 25-Loan and Advances by State Government for the year 1998-99.**

The motion was carried

बिल्लज

(ii) हरियाणा सहकारी सोसायटी (सं गोधन) विधेयह,
1998

Mr. Speaker: Now the Co-operation Minister will introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1998 and he will also move the motion for its consideration.

Co-operation Minister (Shri Narbir Singh): Sir, I introduce the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1998.

Sir, I also move-

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Caluse 2

Mr. Speaker: Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

The the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Co-operation Minister will move that the Bill be passed.

Co-operation Minister (Shri Narbir Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाडी): स्पीकर साहब, इस संबंध में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सिक कोओपरेटिव सोसायटीज हैं, उनको सरकार पहले खुद संभालने की कोशिश करे क्योंकि इनको सीधा प्राइवेट सैक्टर में देना उनके व सरकार के हित में नहीं होगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker: Now the Town & Country Planning Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 1998 and will also move the motion for its consideration.

भाहरी संपदा मंत्री (सेठ सिरी कि ान दास): अध्यक्ष महोदय, मै पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू—

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा सं गोधन) विधेयक, 1998 पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill 1998 Bill be taken into consideration at once.

श्री सम्पत सिंह (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, इस बिल की दो अमैडमेंटस पर मेरा ओब्जेक्ट ान है एक तो मेरा

आब्जैक्टिव इन इस बिल की सैक्टिव इन 2 की क्लोज चार पर है इसमें दिया है कि—

“Commissioner means the Commissioner and Secretary to Government, Haryana Town and County Planning Department.

पहले कमि नर मीन्ज कमि नर अम्बाला डिवीजन था और अब इसकी जगह कमि नर, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग चण्डीगढ़ किया है। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जैक्टिव्स एण्ड रीजन में जो दिया गया है उससे बड़ी हैरानी होती है। इसमें लिखा है कि—

“That persons aggrieved by the decision of the Deputy Commissioner cum-Director, Town & Country Planning, Haryana may prefer an appeal to the Commissioner of the Ambala Division. However, it has been experienced that in the absence of expert advice, the Commissioner of the Division is not able to fully appreciate the provisions of the Act and the Rules.”

पहले बात इसमें यह है कि उसको मालूम ही नहीं है कि उनके पास कोई असिस्ट करने वाला ही नहीं है। कमि नर टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग जो आया है, उसकी पोर्टिंग भी तो अम्बाला हो जाएगी और वह भी अम्बाला से यहां आ जाएगा इसका उसके पास कोई ऐसी असिस्टैन्ट या उसके पास कोई एक्सपर्ट या उसकी अपनी कोई ओपीनियन नहीं है बल्कि यहां वाले कमि नर का ज्यादा ओपीनियर होगा। दूसरा इसमें लिखा है कि—

“Moreover, the aggrieved persons have to go to Ambala for filing appeals. Hence there is a case to make the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department the appellate authority instead of Divisional Commissioner by amending section 2 (4) of the Act.”

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा से अम्बाला दूर है या चण्डीगढ़। ये कह रहे हैं कि उनके लोगो के लिए वहां जाकर अपील दायर करना मुश्किल होता है इसलिए अपील फाइल करने के लिए अप्राप्टिगत जगह अम्बाला ही ठीक है बजाय चण्डीगढ़ के। चण्डीगढ़ तो 50 कि० मी० आगे है। (विधन एवं भाोर)

सेठी सिरी किान दास: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह चण्डीगढ़ के लिए है, यह चण्डीगढ़ के नजदीक है और यह चण्डीगढ़ से 16 कि० मी० अंदर रहेगा। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह इलाका तो हमारा है, तो हमारा पैरीफैरी एरिया है आप उसके लिए ही कह रहे हैं और उसी के लिए मैं भी कह रहा हूँ। (विधन एवं भाोर)

Speaker, Sir, I would like to quote Section 13A of Clause 8, Which is proposed to be inserted, which says as under:-

“Bar of jurisdiction-No civil court shall have jurisdiction to entertain or decide any question relating to matters falling under this Act or the rules framed thereunder.”

अध्यक्ष महोदय, क्या सिविल कोर्ट की जुरी 10-10 साल तक उनसे भी इसको निकाल रहे हैं? एक आदमी जिसका यह फण्डामेंटल राईट है और अगर वह वहां न जाये तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इस बारे में जो क्लोज है अगर उसको सेठ जी नहीं मानते तो वे यह मान लें और इस क्लोज को निकाल दें। (विधन एवं भाोर)

सेठ सिरी कि 10-10 साल तक उनका फ़ैसला नहीं होने देते। अध्यक्ष महोदय, लोग इसे नाजायज बनाते हैं, कोर्ट में जाकर 10-10 साल तक उनका फ़ैसला नहीं होने देते। अध्यक्ष महोदय, दीवानी की कोर्ट में इस तरह के केसिज का 10-10 साल तक फ़ैसला नहीं होता है और लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें कहां बीच में फंसा दिया।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या और अपील कोर्ट में नहीं जाती? जब और अपील कोर्ट में जाती है तो फिर यह अपील क्यों नहीं जा सकती या फिर दूसरी सारी अपीलें वापिस ले ली जाएं।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill 1998 Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 8

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister for Town & Country Planning will move that the Bill be passed.

नगर एवं आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किान दास):
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

18:00 बजे

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बिल की सैक 11 की क्लॉज पांच की तरफ दिलाना चाहूँगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि कन्वर्नि चार्जिज के पेमेंट पर परमिशन दे दी जाएगी चेन्ज आफ लैण्ड यूज की जो इसमें पहले नहीं थी। सर, इसमें 2 बातें हैं। एक बात पंजाब न्यू कैपिटल पैरीफेरी एक्ट है यह फिक्सड स्टैन्डर्ड नहीं है और जो फिक्सड स्टैन्डर्ड नहीं है उसमें से आप छोड़ सकते थे क्योंकि इस प्रकार का फीका प्रावधान पहले ही है, वह आप कर सकते थे इसलिए इस स्टैन्डर्ड का बेसिक परपज पैसा कमाना नहीं

है। अब जो मंत्री जी ने अमैडमेंट की है उसके माध्यम से यह अख्तियार एग्जैक्टिव को दिया गया है कि किसी प्रकार की कन्वर्शन आफ लैंड यूज में परमिशन दे कर अपने मनमाने रेट पर पैसा इकट्ठा किया जाए। मेरे विचार से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं आपका ध्यान स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स के पैरा-4 की तरफ दिलवाऊ तो उसमें साफ लिखा है—

“Since there is no enabling provision in the Act to levy conversion charges for converting the land use within the controlled area, a suitable provision to levy conversion charges in the first part of Section 11 (1) is required.”

सर, आपको याद होगा कि सरकार पिछले सत्र में पंजाब भौडयूल्ड रोड्स के अंदर भी इसी प्रकार की अमैडमेंट लेकर आई थी उस अमैडमेंट की वैधता आज अण्डर चैलेंज है। नॉन फिस्कल स्टैच्यूट को अगर आप पैसा इकट्ठा करने का माध्यम बनाएंगे और दूसरे अगर आप सरकार को यह पूर्ण हक देंगे कि वह किसी प्रकार की लैंड यूज गेन करके उसमें से पैसा बनाए तो मेरे विचार से न यह प्रान्त के हित में होगा और न ही इस सदन को यह बात माननी चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें।

Mr. Speaker: Question is

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9:30 a.m on Wednesday, the 29th July, 1998.

6:03 P.M. (The Sabha then adjourned till 9:30 a.m on Wednesday, the 29th July, 1998)